दैनिक जागरण

मनुष्य का आचरण ही उसका वास्तविक परिचय है

जवाबदेही की जरूरत

डिजिटल मीडिया कंपनियों मेटा और गूगल की ओर से जिस तरह यह कहा गया कि उनके लिए विवादित सामग्री की निगरानी करना संभव नहीं, वह एक तरह से जवाबदेही से बचने का बहाना ही है। यह पहली बार नहीं है, जब स्वयं को सोशल मीडिया कहने वाली कंपनियों ने फर्जी, भ्रमित करने, अफवाह, उत्तेजना और वैमनस्य फैलाने वाली खबरों की निगरानी करने के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की हो। वे ऐसी कोशिश लगातार करती चली आ रही हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के अनेक देशों को उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए तरह-तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि येन-केन-प्रकारेण अधिक से अधिक लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए डिजिटल मीडिया माध्यम ऐसे तौर-तरीके अपना रहे हैं, जिसके चलते वे बेलगाम हो रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि डिजिटल मीडिया कंपनियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, बल्कि यह भी है कि वे लोगों को लती बनाने के साथ उन्हें और विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक देश ऐसे कानून बनाने को बाध्य हो रहे हैं जिससे किशोरवय के लोग उनका उपयोग न कर सकें। चिंता की बात यह भी है कि डिजिटल मीडिया कंपनियां अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। अभी पिछले दिनों ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा को ऐसे सभी विज्ञापन एवं अन्य सामग्री हटाने का आदेश दिया था, जो यौन शोषण को बढ़ावा देती है। इसी तरह कुछ दिन पहले टेलीग्राम को इसके लिए नोटिस दिया गया कि वह अपने प्लेटफार्म से पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए।

टेलीग्राम लंबे समय से पायरेसी को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। यह वही इंटरनेट प्लेटफार्म है जिस पर कुछ दिनों पहले इसलिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना पड़ा था, क्योंकि उससे मेडिकल प्रवेश परीक्षा-नीट के प्रश्नपत्र लीक होने का खतरा पैदा हो गया था। इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपराधी एवं आतंकी तत्व भी डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। भले ही डिजिटल मीडिया कंपनियां यह दावा करती रहती हों कि वे नकारात्मक एवं आपत्तिजनक सामग्री की छानबीन करने और उन पर रोक लगाने के लिए सचेत हैं, लेकिन वस्तुस्थिति इससे विपरीत है। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि डिजिटल मीडिया कंपनियों को जबाबदेह बनाने के लिए हरसंभव उपाय किए जाएं। उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाना ही होगा, क्योंकि अब वे एआइ का भी बेजा इस्तेमाल कर रही हैं।

नवाचार की पहल

कोई भी स्टार्टअप अपनी संकल्पना के साथ जोखिम लिए होता है। यदि उसमें किसी प्रकार का सहयोग मिले तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति-2026 को दी गई स्वीकृति से युवा उद्यमियों की राह आसान होगी। व्यावसायिक धरातल पर सबसे ज्यादा आवश्यकता पूंजी, उसके प्रवाह और अन्य तकनीकी अनुमति की होती है। शासन ने नई नीति के अंतर्गत स्टार्टअप मिशन की स्थापना, 1000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड और 400 करोड़ का डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कार्पस फंड गठित किया है, उससे नई उम्मीद जगती है। स्टार्टअप को शुरुआती दो वर्षों तक हर महीने 20 हजार रुपये की भरण पोषण सहायता, 15 लाख से 50 लाख रुपये तक आरंभिक पूंजी और पांच करोड़ रुपये तक समानुपातिक अनुदान मिलने से प्रदेश में नए उद्यम को प्रोत्साहन मिलेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में आवश्यक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलाजी, स्पेस टेक्नोलाजी आदि के क्षेत्र में नवाचार हो। नई नीति में केवल व्यवस्थागत पूंजी प्रबंधन की ही चिंता नहीं की गई, बल्कि सेंटर आफ एक्सीलेंस और इन्क्यूबेशन सेंटर आदि का भी प्रबंध किया गया है। अनुसंधान एवं विकास पर भी सहायता का प्रविधान है। निश्चय ही उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को स्टार्टअप के माध्यम से वैश्विक नेटवर्किंग में नई पहचान मिलेगी। यह पहल प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं के द्वार खोलेगी।

> निश्चय ही उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को स्टार्टअप के माध्यम से वैश्विक नेटवर्किंग में नई पहचान मिलेगी

दिव्य साधना भी है अमरनाथ यात्रा

मनोज सिन्हा

सह-अस्तित्व का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करती अमरनाथ यात्रा इसका भी संदेश देती है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य लोगों को जोड़ना है

तीन जुलाई से प्रारंभ हुई पावन श्री अमरनाथ जी यात्रा भारतीय आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। अनादि काल से इस पवित्र तीर्थयात्रा ने हमारी आस्था, संस्कृति और पहचान को आकार दिया है। बाबा बर्फानी की तीर्थयात्रा केवल कठिन पर्वतीय मार्गों की पदयात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाली एक आंतरिक साधना भी है। यह यात्रा केवल पवित्र तीर्थस्थल तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। यह एक दिव्य साधना भी है। यह यात्रा ध्यान, शिव की प्रार्थना और कठिन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने के संकल्प, अनंतता और शाश्वत सत्य का प्रतीक है।

बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने की यात्रा मानव जीवन की सीमाओं और अस्तित्व के बीच चलने वाला एक निरंतर संवाद है। श्रद्धा, समर्पण और सामूहिक आस्था की इस पवित्र यात्रा का एक संदेश यह भी है कि आध्यात्मिकता अपने भीतर छिपे प्रकाश की खोज का मार्ग है। प्रत्येक वर्ष देश-विदेश से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्त इस यात्रा में केवल अपने या अपने परिजनों के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं नहीं लाते, वे समस्त मानवता की आकांक्षाएं भी साथ लेकर आते हैं। यह यात्रा हमारी पहचान है। हमारे जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा है। भारतवर्ष में इस यात्रा का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास इस बात को रेखांकित करता है कि अमरनाथ यात्रा सामाजिक एकता का प्रतीक है। सदियों से जम्मू-कश्मीर में विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं से जुड़े लोगों ने इस यात्रा के संचालन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सह-अस्तित्व का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करती यह यात्रा इसका संदेश देती है कि आस्था का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है और भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग मानवता के साझा मूल्यों की यात्रा भी है।

प्रतिवर्ष यात्रा के शुभारंभ से पहले सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़ी हस्तियां श्रीनगर में जुटती हैं। जैसे ही पहला जत्था जम्मू संभाग के रामबन जिले में पहुंचता है, वैसे ही हर आस्था, हर मजहब से जुड़े नागरिक फल और फूलों से यात्रियों का स्वागत करते हैं। सभी धर्मों के प्रति सम्मान भारत की एक दुर्लभ और अमूल्य धरोहर है और विभिन्न आस्थाओं के लोगों द्वारा श्रद्धालुओं का गर्मजोशी और भक्ति-भाव से स्वागत इसका जीवंत प्रमाण है। हर धर्म के प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन का ऐसा अद्भुत दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस यात्रा के दौरान भारत से पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि समाज में लोगों की उपासना पद्धति, विचार और विश्वास भिन्न हो सकते हैं, परंतु हमारी मानवता साझा है। यह पवित्र तीर्थयात्रा वैश्विक समाज के लिए अन्य आदर्श प्रस्तुत करती है कि दूसरों की सेवा भी सच्ची भक्ति का ही एक अन्य सर्वोच्च रूप है। जब हजारों श्रद्धालु एक साथ आगे बढ़ते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं तब वह दृश्य हमें याद दिलाता है कि समाज की वास्तविक शक्ति लोगों की आस्था, एकजुटता और परस्पर विश्वास में निहित होती है।

अवधेश राजपूत

बाबा बर्फानी की यात्रा हमारी सभ्यता के उस आदर्श को जीवंत रूप देती है जिसे हम 'विविधता में एकता' के नाम से जानते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि राष्ट्रीय एकता परस्पर सम्मान और साझा उद्देश्य से निर्मित होती है। पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, वहीं सतत एवं सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का विकास भी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हुआ है। देश के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में आयोजित होने के बावजूद यह यात्रा आज उत्कृष्ट प्रबंधन और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं का ऐसा आदर्श बन गई है, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रशंसा और प्रेरणा का विषय है। पिछले तीन वर्षों की यात्राओं में औसत श्रद्धालुओं की संख्या 4.57 लाख रही है, जो अब तक अमरनाथ यात्रा के समग्र औसत से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम रूप से यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु 'रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कार्ड' जारी किया जा रहा है। इस पावन तीर्थयात्रा के इतिहास में पहली बार बालटाल मार्ग पर पवित्र गुफा तक तथा पवित्र गुफा से पंचतरणी तक ग्रिड आधारित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है और यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यात्रा की रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है। समर्पित वायरलेस संचार इंट्रानेट नेटवर्क के माध्यम से यात्रियों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग, निगरानी तथा टट्टू, पिट्ठू, पालकी आदि सेवाओं की प्री-पेड बुकिंग जैसी विभिन्न ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चंद्रकोट के अतिरिक्त बालटाल, पंथा चौक, श्रीनगर तथा नुनवान में भी यात्री निवास निर्मित किए गए हैं। श्रीनगर में एक एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बाढ़ संभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित तथा उनका स्पष्ट सीमांकन किया गया है। आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए भी यात्रा की मूल आध्यात्मिक भावना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को एक विशेष पत्र लिखा है और इस पवित्र तीर्थयात्रा को पांच संकल्पों से जोड़ते हुए बाबा के भक्तों से उन्हें अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने तथा हरित और स्वच्छ तीर्थयात्रा के संकल्प के साथ 'जीरो-वेस्ट अमरनाथ यात्रा' अभियान के अंतर्गत 100 प्रतिशत कचरा संग्रह एवं पुनर्चक्रण, प्लास्टिक मुक्त पहल तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों के पीछे प्रशासन, सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास, समन्वय और जनसहभागिता ने असंभव लक्ष्यों को भी सफल बनाने का काम किया है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान शंकर का यह पावन तीर्थ आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था, एकता, शांति, सह-अस्तित्व और सतत विकास का प्रेरणास्रोत बने।

(लेखक जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं)

response@jagran.com

मजबूत होती भारत की प्रशांत कूटनीति

अनिल वाधवा

आस्ट्रेलिया भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का सुरक्षा स्तंभ है तो न्यूजीलैंड आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के नए द्वार खोल सकता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इंडोनेशिया के साथ आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं नए सिरे से गठित हो रही हैं, तकनीकी प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है, ऊर्जा व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समुद्री सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज भारत ऐसे भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है, जो उसकी आर्थिक प्रगति, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहयोगी बन सकें, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई प्रभाव न पड़े। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस दृष्टि से भारत के स्वाभाविक साझेदार हैं। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, समुद्री शक्ति रखते हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिर, खुली तथा नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थक हैं।

पिछले एक दशक में आस्ट्रेलिया भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में शामिल हो चुका है। क्वाड के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार गहरा हुआ है और रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के सोच में भी व्यापक समानता दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी की आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाने पर जोर रहने की संभावना है। आस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं, जिनकी आवश्यकता इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण, सेमीकंडक्टर उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए अनिवार्य है। भारत यदि हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो इन संसाधनों तक दीर्घकालिक और भरोसेमंद पहुंच सुनिश्चित करना उसकी रणनीतिक आवश्यकता है। नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम आपूर्ति, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भी दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे सकता है। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार 25 अरब डालर से अधिक हो चुका है। भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते ने व्यापार को नई गति दी है, जबकि अवसंरचना, खनन, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में आस्ट्रेलियाई निवेश लगातार बढ़ रहा है। अब आवश्यकता व्यापक आर्थिक साझेदारी के माध्यम से निवेश और व्यापार के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने की है।

प्रगाढ़ होते आस्ट्रेलिया-भारत रिश्ते। फाइल

यदि आस्ट्रेलिया भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का सुरक्षा स्तंभ है तो न्यूजीलैंड आर्थिक और तकनीकी सहयोग का नया द्वार खोल सकता है। हाल में संपन्न भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा दी है। फिलहाल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.4 अरब डालर है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता की तुलना में काफी कम है। भारत विशाल उपभोक्ता बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि न्यूजीलैंड कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों के बीच न्यूजीलैंड का अनुभव भारत की कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और आधुनिक बनाने में भूमिका निभा सकता है। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग भविष्य की साझेदारी को और मजबूत करेगा। द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 अरब डालर के निवेश का संकल्प भी व्यक्त किया है।

भारत के आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संबंधों की एक ताकत दोनों देशों में बसे भारतीय मूल के लोग हैं। आस्ट्रेलिया में लगभग दस लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में भी भारतीय समुदाय तेजी से प्रभावशाली होता जा रहा है। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान दोनों देशों के बीच एक मजबूत मानवीय सेतु बन चुका है। पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। नेताओं के बीच व्यक्तिगत विश्वास भी द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देता है। प्रधानमंत्री मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच विकसित हुई समझ ने दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ होने वाली वार्ता दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र रहेगा। ऐसे में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मजबूत होते संबंध भारत को केवल इस क्षेत्र में प्रभावशाली उपस्थिति ही नहीं देंगे, बल्कि उसे एक अधिक सुरक्षित, समृद्ध और आत्मविश्वासी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

(स्तंभकार पूर्व राजदूत तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की आस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट के लेखक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अंतस की निर्मलता

जब हृदय छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम, करुणा, सत्य और सद्भाव से भर जाता है, तभी जीवन अपने वास्तविक अर्थों में सुंदर बनता है। आज का मनुष्य भौतिक उपलब्धियों की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने अपने भीतर झांकना लगभग छोड़ दिया है। परिणामस्वरूप तनाव, असंतोष और मानसिक अशांति उसके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इसका कारण बाहरी अभाव नहीं, आंतरिक अशुद्धि है। जब मन लालच, क्रोध और स्वार्थ से भर जाता है, तब सुख के सभी साधन भी शांति नहीं दे पाते। इसके विपरीत, निर्मल हृदय वाला व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी संतोष और आनंद का अनुभव करता है। प्रकृति हमें निरंतर यह शिक्षा देती है कि पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्वच्छ जल अपनी निर्मलता से जीवन देता है, सूर्य बिना किसी भेदभाव के सब पर समान प्रकाश बरसाता है और आकाश सबको समान आश्रय प्रदान करता है। इसी प्रकार निर्मल अंतःकरण वाला व्यक्ति अपने व्यवहार, वाणी और कर्म से समाज में प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता का वातावरण निर्मित करता है।

अंतस की निर्मलता एक दिन में प्राप्त होने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर साधना का परिणाम है। आत्मचिंतन, ध्यान, सत्संग, सेवा, श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन और कृतज्ञता का अभ्यास मन को शुद्ध करने के प्रभावी साधन हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी वास्तविक आत्मविकास प्रारंभ होता है। निर्मल अंतस ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही उसे आत्मिक शांति, विवेक और जीवन का सच्चा आनंद प्रदान करता है। जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, वही अपने जीवन से समाज को प्रकाश, प्रेरणा और मानवीय मूल्यों की अमूल्य विरासत दे सकता है।

प्रेरणा अवस्थी

जल प्रबंधन में कैसे अग्रणी बना इजरायल

डा. सुधीर कुमार

समुद्री जल के विलवणीकरण पर जोर देकर इजरायल आज जल-प्रबंधन की अग्रणी शक्ति बन गया है

इजरायल की गिनती कभी दुनिया के सर्वाधिक जल तनाव वाले देशों में होती थी, पर प्रभावी जल प्रबंधन और उन्नत तकनीक के बल पर वह अपने नागरिकों को पर्याप्त, नियमित और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने में न सिर्फ कामयाबी पाई है, बल्कि इस मामले में पथ-प्रदर्शक भी बन चुका है। दुनिया इजरायल के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकती है।

इजरायल ने 1948 में स्वतंत्रता की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जल संकट की थी। आधे से अधिक भूभाग पर फैले रेगिस्तान, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जलवायु संकट के बीच जल संकट से निपटने के लिए इजरायल ने ऐसे कई प्रयोग किए, जो आगे चलकर दुनिया के लिए उदाहरण भी बने। इजरायल ने 1950 के दशक में 130 किलोमीटर लंबी जल परियोजना 'नेशनल वाटर कैरियर' शुरू की, जिसके जरिये वह देश के उत्तर से मध्य और शुष्क दक्षिणी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने में सफल रहा। इससे न सिर्फ सूखे क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता पूरी हुई, बल्कि कृषि और जनजीवन में भी सुधार आया। इसके एक दशक बाद इजरायल ने कृषि क्षेत्र में पानी की मांग को पूरा करने और बर्बादी नियंत्रित करने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक ईजाद की, जिसने दुनिया को कम पानी में अधिक पैदावार की राह दिखाई। साथ ही, इजरायल ने अपशिष्ट जल के उपचार पर भी ध्यान दिया, जिससे जल संकट को नियंत्रित करने के साथ-साथ उपचारित जल का कृषि, बागवानी और शहरी जरूरतों में पुनर्उपयोग भी सुनिश्चित किया गया। आज इजरायल की अपशिष्ट जल उपयोग दर दुनिया में सबसे अधिक है। वह कृषि के लिए लगभग 90 प्रतिशत अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करने में भी कामयाब रहा है। इजरायल का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र शफदान में स्थापित है। 1985 में इजरायल ने अपने 'राष्ट्रीय जल वाहक' के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल को खेतों तक भेजना शुरू कर दिया। जल प्रबंधन की सतत रणनीति के तहत में 1999 में खारे समुद्री पानी को विलवणीकरण करने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज वह अपनी नगरपालिका और औद्योगिक जल आवश्यकताओं का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अलवणीकृत जल से पूरा कर रहा है। भारत के पास 11,098.81 वर्गकिमी लंबी तटरेखा है। ऐसे में यह तकनीक अपनाकर भारत जल संकट पर नियंत्रण पा सकता है।

बहरहाल, ड्रिप सिंचाई से जल-संरक्षण, अपशिष्ट जल का उपचार एवं पुनः उपयोग और समुद्री जल के विलवणीकरण पर जोर देकर इजरायल आज जल-प्रबंधन की अग्रणी शक्ति बन गया है। इन रणनीतियों को अपनाकर कोई भी देश पानी की उपलब्धता और वितरण संबंधी परेशानियों को मात दे सकता है।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

मेलबाक्स

ब्रांड इंडिया का दशक

डा. जयंतीलाल भंडारी का आलेख "मुश्किलों के बीच निर्यात बढ़ाने की चुनौती" पढ़ा। भारत के लिए निर्यात वृद्धि का प्रश्न केवल वैश्विक परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक आर्थिक क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और नीति-क्रियान्वयन की विश्वसनीयता का भी है। आज विश्व में आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं। चीन-प्लस-वन रणनीति, फ्रेंडशोरिंग और उत्पादन विविधीकरण जैसे वैश्विक रुझान भारत के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर आए हैं। किंतु अवसर केवल उन्हीं देशों को लाभ देते हैं, जिनकी संस्थाएं भरोसेमंद, प्रक्रियाएं सरल और उद्योग प्रतिस्पर्धी हों। केवल मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर कर देना निर्यात बढ़ाने की गारंटी नहीं है। यदि बंदरगाहों पर कंटेनर दिनों तक अटकें, परिवहन लागत प्रतिस्पर्धी देशों से अधिक हो, बिजली और लाजिस्टिक्स महंगे हों तथा छोटे उद्योगों को वित्त और प्रौद्योगिकी तक समय पर पहुंच न मिले तो वैश्विक बाजार में भारत की क्षमता सीमित रह जाएगी। यदि हमें वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनना है तो 'निर्यात की गुणवत्ता' बढ़ानी होगी। उच्च मूल्यवर्धित इलेक्ट्रानिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, चिकित्सा उपकरण, हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और एआइ आधारित उत्पादों में वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाए बिना भारत लंबे समय तक कम मूल्य वाले उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सकता। भारत के लगभग आधे से अधिक निर्यात में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यही क्षेत्र वित्तीय कठिनाइयों, जटिल अनुपालनों, गुणवत्ता प्रमाणन और तकनीकी उन्नयन की चुनौतियों से जूझ रहा है। यदि इन उद्योगों को डिजिटलीकरण, अनुसंधान एवं विकास, कौशल उन्नयन तथा वैश्विक विपणन नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया तो बड़े निर्यात लक्ष्य केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित रह जाएंगे। आज आवश्यकता "मेक इन इंडिया" से आगे बढ़कर "ब्रांड इंडिया" स्थापित करने की है। विश्व बाजार केवल सस्ता उत्पाद नहीं खरीदता, वह गुणवत्ता, विश्वसनीयता, समय पर आपूर्ति और नवाचार खरीदता है। जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी ने यही सिद्ध किया है। भारत को भी 'लो-कास्ट मैन्युफैक्चरिंग' से आगे बढ़कर 'हाई-वैल्यू इनोवेशन' की पहचान बनानी होगी।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

बंद होते इंजीनियरिंग संस्थान

एआइसीटीई द्वारा देश में 58 इंजीनियरिंग संस्थाओं को बंद करना उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए चिंताजनक है। इंजीनियरिंग शिक्षा औद्योगिक विकास की आधारशिला है। इंजीनियरिंग कालेजों का बंद होना यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि और नामांकन में गिरावट आ रही है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की बढ़ती फीस, रोजगार को लेकर अनिश्चितता, प्रवेश एवं मान्यता संबंधी जटिल नियम इसके प्रमुख कारण हैं। एआइसीटीई और सरकार को इस स्थिति की गंभीर समीक्षा करनी चाहिए। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, छात्रवृत्ति, कम फीस तथा बेहतर प्लेसमेंट व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो तकनीकी शिक्षा का यह संकट देश के औद्योगिक विकास और कुशल मानव संसाधन निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

हेमंत कुमार, हवाई नगर, रांची

शिक्षक प्रशिक्षण का महत्व

आज शिक्षण प्रशिक्षण का महत्व बढ़ गया है। शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ केवल नई सामग्री सीखना ही नहीं है, बल्कि शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना भी है। जब शिक्षक अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं तो वे अपनी भूमिकाओं में अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावी होते हैं जिससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण शिक्षकों को विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों से जुड़ने में मदद करता है, समावेशिता को बढ़ावा देता है और हाशिए पर पड़े समूहों की उपलब्धि में सुधार करता है।

कुमार गौरव, मधुबनी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

40 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है इस वर्ष जून में, जिस कारण इस वर्ष यह माह वर्ष 1901 के बाद से पांचवां सबसे सूखा साबित हुआ है। अल नीनो के कारण ऐसा होना माना जा रहा है।

आजकल

मानसून की बदलती प्रकृति और चुनौतियां

प्रो. एम एल मीणा
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

कभी कृषि के लिए वरदान साबित होने वाला मानसून अब अपनी प्रकृति में बहुआयामी होता जा रहा है। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में अपनी सामान्य तिथि से तीन दिन की देरी से पहुंचा। इसके बाद यह क्रमिक रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा से गुजरते हुए आगे बढ़ता गया। हालांकि अब यह लगभग पूरे देश में पहुंच चुका है, परंतु एक गंभीर प्रश्न यह उभर रहा है कि मानसून का भौगोलिक विस्तार अब अपने साथ पर्याप्त वर्षा की गारंटी नहीं दे रहा है, और यह तथ्य इस वर्ष की सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है

देश के कई हिस्सों में अब तक मानसून की बारिश अपेक्षाकृत कम होने से खरीफ फसलों की बोआई प्रभावित हुई है। फाइल

मानसून का पदार्पण भले ही हो चुका है, परंतु मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार इस माह राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा दीर्घावधि औसत से भी कम और सीमित रह सकती है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है। यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि जुलाई वही महीना है जिसमें मानसून अपनी सबसे अधिक सक्रियता तक पहुंचता है, और खरीफ फसलों की बोआई, जलाशयों की पुनर्भराव प्रक्रिया तथा ग्रामीण जल-आपूर्ति की संपूर्ण योजना इसी महीने की वर्षा पर आधारित होती है। इस तरह जुलाई एक कमजोर और असमान मानसून-माह के रूप में व्यतीत होगा, जिसमें सक्रिय और शिथिल वर्षा-चक्र बारी-बारी से आते रहेंगे।

इस असमानता के पीछे कमजोर अल नीनो प्रभाव और हिंद महासागर द्विध्रुव की तटस्थ स्थिति का साथ सक्रिय होना है, जिनका संयुक्त प्रभाव वर्षा को कम तो नहीं करता है, परंतु उसका असमान पुनर्वितरण बहुत गंभीरता से कर देता है। इस बार दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग में वर्षा की कमी बने रहने का जोखिम है। यह भौगोलिक असमानता तत्काल एक प्रशासनिक दुविधा में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि जब एक तरफ कुछ राज्यों को बाढ़-नियंत्रण के लिए तत्काल संसाधन चाहिए, ठीक उसी समय दूसरे राज्यों को सूखा-राहत की जरूरत पड़ जाती है।

शहरी प्रशासन के स्तर पर तैयारियों की तस्वीर इससे भी अधिक निराशाजनक है। कई प्रमुख शहर हर मानसून में लगभग एक जैसी समस्या का सामना करते हैं जैसे पुरानी जल-निकासी व्यवस्था, अनियोजित शहरीकरण तथा तालाबों एवं प्राकृतिक जल-अवशोषण क्षेत्रों का लगातार क्षरण इत्यादि। इसका मूल कारण यह संस्थागत सत्य है कि नगर निगमों के पास न तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं, न वास्तविक प्रशासनिक अधिकार, और न ही उनके कार्यों की सतत गरानी की व्यवस्था है।

स्थिति की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जून के मध्य तक मुंबई की जलापूर्ति करने वाले सात प्रमुख जलाशयों का जल-भंडारण घटकर मात्र 10 से 12 प्रतिशत क्षमता तक सीमित रह गया था, और शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली मीठी नदी के पुनर्विकास कार्य मानसून प्रारंभ होने तक केवल 75 प्रतिशत ही पूरे हो सके थे। यही वह नदी है जिसके उफान ने वर्ष 2005 की विनाशकारी बाढ़ में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जिसमें सौ से अधिक लोगों की जान गई थी। वहीं बेंगलुरु में तीव्र एवं अनियोजित शहरी विस्तार ने प्राकृतिक जल-निकासी तंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों जैसे प्राकृतिक अवरोधकों और घाटा झील तथा नजफगढ़ झील जैसे मौसमी जलाशयों पर हुए अवैध अतिक्रमण ने प्रत्येक वर्षा-काल को एक संभावित संकट में बदल दिया है।

हिमालयी राज्यों की स्थिति इससे भी अधिक गंभीर है, जहां भूगोल और जलवायु परिवर्तन का संगम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं अब अपवाद न रहकर नियमित पैटर्न का रूप ले चुकी हैं। एक अध्ययन के अनुसार, भारत के तेरह हिमालयी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में पिछले चार वर्षों में लगभग आठ सौ दिन किसी न किसी अतिवादी मौसमी घटना से प्रभावित रहे हैं।

भू-राजनीतिक आयाम : इस पूरे परिदृश्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक आयाम भी जुड़ जाता है, जो मानसून की चर्चा को राष्ट्रीय सीमाओं से आगे ले जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अब भारत और चीन के मध्य एक नई प्रकार की जल-प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गई है। वहीं चीन तिब्बत के मेडोग क्षेत्र में 60 गीगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध निर्मित कर रहा है, जिसके प्रत्युत्तर में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में करोड़ों डालर की उच्च सियांग बहुउद्देशीय परियोजना सहित दो सौ से अधिक बांधों की योजना बनाई है। दोनों देशों के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी के प्रबंधन हेतु कोई बाध्यकारी संस्थागत संधि विद्यमान नहीं है, और चीन ने वर्ष 2022 से जल-प्रवाह संबंधी संपूर्ण हाइड्रोलाजिकल आंकड़े भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया है। यद्यपि अनेक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि तकनीकी रूप से भारत तथा बांग्लादेश की अपनी मानसूनी वर्षा ही ब्रह्मपुत्र के अधिकांश जल-प्रवाह और तलछट का स्रोत है, इसलिए चीन नदी का प्रवाह नियंत्रित नहीं कर सकता, तथापि आंकड़ों की यह अनुपलब्धता स्वयं में एक गंभीर विश्वास-संकट उत्पन्न करती है, विशेष रूप से मानसून के दौरान जब किसी भी अप्रत्याशित जल-निर्गमन की आशंका पूर्वोत्तर भारत में चिंता का विषय बन जाती है।

इस भू-राजनीतिक जटिलता की एक और परत तब उजागर होती है जब भारत की स्थिति को क्षेत्रीय संदर्भ में देखा जाए। चीन के समक्ष भारत स्वयं को निम्न तटवर्ती राष्ट्र के रूप में असुरक्षित अनुभव करता है, परंतु बांग्लादेश और पाकिस्तान के समक्ष भारत स्वयं उच्च तटवर्ती शक्ति की भूमिका में है, जिस पर जल-आधिपत्य की प्रवृत्ति अपनाने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह विरोधाभासी स्थिति एक व्यावहारिक रणनीतिक जोखिम उत्पन्न करती है, क्योंकि इससे बांग्लादेश के चीन के साथ जल-संबंधी सहयोग बढ़ाने की संभावना प्रबल होती है, जो अंततः भारत की पूर्वोत्तर सीमा-सुरक्षा नीति को प्रभावित करती है।

बारिश से जुड़ी आपदाओं से समय रहते सबक

डा. नवीन कुमार मिश्र
भूगोल के जानकार

पारिस्थितिकी, आर्थिकी और समाज के आपसी बंधन लगभग टूट जाने तथा वर्षा के स्वरूप की अनिश्चितता के कारण पीने से लेकर सिंचाई तक पानी का संकट उत्पन्न हो चुका है। इसी के साथ ही तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, बिजली गिरने और वनों में आग लगने जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। इन आपदाओं से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस बार अल नीनो के दुष्प्रभावों से मानसूनी वर्षा में कमी का असर देश के उपजाऊ मैदानी इलाकों पर भी दिखाई देने वाला है। जून में वर्षा में कमी देखी गई है। इससे खरीफ की बोआई प्रभावित होगी। सिंचाई में मुश्किलों के साथ ही उसकी लागत भी बढ़ जाती है, जिससे इसका असर रोजगार, सुरक्षा, महंगाई और आर्थिक विकास दर पर पड़ने लगता है। नमी की कमी के कारण वनों में आग की घटनाएं चिंता का विषय हैं। पहाड़ों पर पानी की कमी का असर केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झेलना पड़ता है। इस वर्ष जहां ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में पर्याप्त बर्फ जमनी थी, वह नहीं जम पाई।

पहले नदियां अधिक चौड़ी हुआ करती थीं और उनमें जल का प्रवाह भी अधिक रहता था, परंतु वर्तमान में नदियों की धारा पतली हो गई है और उन्होंने अपना रास्ता भी बदल लिया है। ऐसे में नदियों के मार्ग परिवर्तन के बाद उनके छोड़े हुए रास्तों पर कई तरह के निर्माण कार्य या कहें कि अतिक्रमण तेजी से हुए हैं और लोगों के आवास भी प्रमुखता से बने हैं। बादल फटने, अचानक बाढ़ आने तथा भूस्खलन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के साथ ही गंभीर तबाही का कारण बना हुआ है। पिछले वर्ष तीन हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर में जून से सामान्य से कहीं अधिक वर्षा हुई है, जिससे आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अनियमित शहरीकरण, जलविद्युत बांध और फोर-लेन मार्ग, ढलानों पर अनुचित कटाई और भूवैज्ञानिक परामर्श के बिना संवेदनशील ढलानों पर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण होना तथा नालियों के अवरुद्ध होने से हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बढ़ गई है।

वनों की कटाई व पहाड़ों पर असंतुलित और अनियोजित विकास कार्य से जलवायु परिवर्तन की स्थिति बन गई है। बिगड़ते पर्यावरण के कारण पहाड़ी क्षेत्रों की जड़ी-बूटियां लुप्त होती जा रही हैं। फसलों और फलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। विकास ने पर्यावरण को हाशिये पर धकेल दिया है। यही कारण है कि मानव की अधिकांश अस्वस्थता का कारण जलवायु परिवर्तन बनता जा रहा है, जिससे वह गर्मी, बाढ़, सूखा, तूफान व अन्य चरम मौसमी घटनाओं की मार झेलने को मजबूर है।

वनों का प्रबंधन और विशेष रूप से पौधारोपण कार्यक्रम, झाड़ियां लगाने, जलभृतों को फिर से भरने और अपवाह में कमी लाकर पहाड़ी ढलानों को स्थिर करने की पहल की आवश्यकता है। संवेदनशील ढलानों से बसाव को विस्थापित कर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नदियों या जल चैनलों का कोई प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो और सभी क्षेत्रों में वर्ष भर जल निकासी बनी रहे। जब भी इस तरह की आपदा आती है तो विकास की मौजूदा नीतियों और तौर-तरीकों पर बहस शुरू हो जाती है, परंतु धरातल पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य दिखाई नहीं देते हैं। आपदाओं से सबक लेकर राज्य सरकारें विशेषज्ञों की सहायता से पारिस्थितिकी और भूविज्ञान आधारित क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करने की पहल कर आपदाओं से बचाव पर सार्थक पहल करने की उम्मीद की जा सकती है।

खरी-खरी

मानसून का एंटी नेशनल चरित्र

विनय कुमार पाठक

मान शब्द का अर्थ है सम्मान या प्रतिष्ठा। अभिमान या अहंकार, नाप तौल का परिणाम, मूल्य आदि के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे इसी नाम के एक राजा ने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़कर कहीं न कहीं अपने मान में बट्टा जरूर लगाया है। वैसे कहा जाता है कि प्यार और युद्ध में सब जायज होता है।

एक और शब्द है मानसून। इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है और इसका मान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन देश में इसका बहुत मान है, क्योंकि इसी पर देश की कृषि निर्भर है। कुछ लोग मानसून के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह एंटी नेशनल है।

अब मानसून एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? वह ऐसे कि सरकार के खिलाफ जो भी बोले या सरकार की जो पोल खोले, वह एंटी नेशनल तो हो ही जाता है। सुनने में आया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने और राजनीतिक नारा लगाने के आधार पर देश के सबसे योग्य पुलिस लोगों को तड़ीपार कर दे रही है आजकल। ऐसे में मानसून का क्या बनेगा यह भविष्य के गर्भ में है।

अब प्रश्न उठता है कि गलती क्या है मानसून की? तो जवाब यह है कि मानसून हमेशा हमारे विकास की पोल खोल देता है और बड़ी ही निर्दयतापूर्वक खोल देता है। यह हाल तब भी होता है जब मानसून काफी कमजोर होता है। साथ ही यह बहुत ही दोहरा चरित्र दिखाता है। किसी क्षेत्र में तो इतना बरसता है कि जन-जीवन अस्त व्यस्त हो जाए तो कोई क्षेत्र एक-एक बूंद के लिए तरसता है।

चाहे जमकर बरसे या थोड़ा बहुत, यह सरकारी दावे की पोल खोलने का काम करता ही करता है। राजधानी में कुछ मिनट की बारिश में इसके कारण सड़कों पर कार चलाने के स्थान पर नाव तैराने की नौबत आ जाती है। सीवर की कितनी और कैसी सफाई हुई है यह इससे स्पष्ट हो जाता है। अस्पताल हो या स्कूल कालेज सभी पानी-पानी हो जाते हैं। दूसरी ओर देश की आर्थिक राजधानी में तो यह वहां के जीवन रेखा को ही ठप कर देता है।

पोस्ट

जब किसी मंत्री के कार्यालय में एक ही रात में पूरी टीम को हटा दिया जाता है तो यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि अपने आप में एक बड़ी खबर होती है। आखिर क्या गलत हुआ? क्या सामने आया? और इसकी जवाबदेही किसकी है?
अभिषेक सिंघवी @DrAMSinghvi

पंजाब में कांग्रेस फिर आत्महत्या पर उतारू है। पार्टी 2022 को दोहरा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पिछली बार मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस हारी। अब फिर वह कांग्रेस को हराना चाहते हैं क्या?
आशुतोष @ashutosh83B

कांग्रेस के तीन पूर्व मुख्यमंत्री इस समय कांग्रेस की नाव किनारे लगने से पहले डुबाने पर उतारू हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
समीर चौगांवकर @semeerc

अवसर इस बात का इंतजार नहीं करता कि आप उसका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। वह तो बिना बताए आता है, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए।
रजत शर्मा @RajatSharmaLive

डिग्री नहीं, कौशल बनेगा रोजगार की गारंटी

ऋषभ मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर, कानपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर

हाल ही में प्रकाशित 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट' के अनुसार देश में एंप्लायबिलिटी (रोजगार पाने की क्षमता) वर्ष 2021-22 की 46.2 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 56.3 प्रतिशत हो गई है। यह एक उत्साहजनक रुझान है और इस बात का मजबूत संकेत भी कि हमारा शिक्षित कार्यबल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप, उद्योगों की बढ़ती भागीदारी और एआइ जैसी स्किल सिखाने वाले प्लेटफार्म्स के विस्तार का परिणाम है। लेकिन इस रिपोर्ट का एक मतलब यह भी है कि करीब 44 प्रतिशत कार्यबल अब भी किसी रोजगार के योग्य नहीं है। यानी इन प्रयासों को और बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

यद्यपि आज भी कई लोग डिग्री को ही सफलता का नुस्खा अथवा पैमाना मानते हैं और कौशल (स्किल) को उतना महत्व नहीं देते। इस स्थिति को बदलने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाना जरूरी है। हमें व्यावसायिक व शैक्षणिक शिक्षा के बीच की दूरी को खत्म कर दोनों को एक-दूसरे के साथ जोड़ना होगा। जिसके लिए कार्य अनुभव एवं औद्योगिक दक्षता हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच पारस्परिक संवाद शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसा इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, जो पाठ्यक्रमों की डिजाइनिंग और उनके निर्माण में सहयोग करने के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 'अपडेटेशन' में भी सक्रिय भूमिका निभाए। यदि उद्योगों को पूरी शिक्षण प्रक्रिया में ही शामिल किया जा सकेगा तो सभी का फायदा होगा।

गौरतलब है कि कालेज शिक्षक उद्योगों से कितना जुड़े (कनेक्ट) हैं, यह भी काफी मायने रखता है। इस संदर्भ में एआइसीटीई इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम

प्रतीकात्मक

जैसी पहल फायदेमंद है। ऐसे कार्यक्रम कालेज शिक्षकों को उद्योगों के साथ समय बिताने का अवसर देते हैं। इसका मकसद यह है कि शिक्षक उद्योगों में कामकाज के तौर-तरीकों, तकनीकों और अपेक्षाओं को समझ सकें तथा फिर अपने छात्रों को भी बता सकें।

शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विकसित देशों ने भी अलग-अलग माडल अपनाए हैं। जर्मनी का 'ड्यूल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम' शिक्षा और नौकरी के बीच की खाई को पाटने का दुनिया का सबसे सफल माडल है। इसका मुख्य आधार 'सीखने के साथ कमाना' है, जिसमें छात्र का समय दो हिस्सों में बंटा होता है।

चीन में भी संबंधित सर्टिफिकेट सिस्टम लागू है। यहां भी छात्र को अपनी डिग्री के साथ-साथ एक या अधिक व्यावसायिक कौशल प्रमाण-पत्र हासिल करने होते हैं, जो उद्योगों द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इससे स्नातक छात्रों के पास न केवल डिग्री होती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के 'वर्किंग सर्टिफिकेट' भी होते हैं। इससे उनके लिए रोजगार की राह आसान हो जाती है। इसी तरह वहां 'व्यावसायिक कौशल ग्रेडिंग सिस्टम' लागू किया गया है। इसमें डिग्री को नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल को वेतन और पदोन्नति से जोड़ा गया है।

'सीआइआइ' और 'ईटीएस' द्वारा जारी 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट' के अनुसार भविष्य में मुख्यतः पांच सेक्टरों में स्किल्ड लोगों की मांग बढ़ेगी। इसमें पहला है 'एआइ व डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग' इसके अंतर्गत जेनरेटिव एआइ इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, इंजीनियर डाटा साइंटिस्ट, एआइ सपोर्ट एक्सपर्ट से जुड़ी अन्य तकनीकों में भी स्किल्ड लोगों की मांग बढ़ेगी। दूसरा, 'रिन्यूएबल एनर्जी' के अंतर्गत एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड डिजिटलीकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तीसरा, 'हेल्थकेयर टेक' के अंतर्गत टेलिमेडिसिन और वर्चुअल क्लीनिकल सेवाएं नए कौशल की मांग पैदा कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप हेल्थ इन्फार्मेटिक्स विशेषज्ञों की जरूरत और बढ़ेगी। चौथा, 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी' के अंतर्गत बैटरी टेक्नोलाजी, वाहन साफ्टवेयर, सप्लाई चेन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लाजिस्टिक्स प्लानिंग के फील्ड में स्किल्स लोगों की मांग बढ़ेगी। और पांचवां, 'सेमीकंडक्टर्स' के अंतर्गत चिप डिजाइन, वेरिफिकेशन और फेब्रिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में नौकरियों का विस्तार होगा। साथ ही इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य टेक्नोलाजी में भी स्किल्ड लोगों की मांग बढ़ेगी।

वस्तुतः एक अच्छा संकेत यह भी है कि अब भारत धीरे-धीरे उस दौर में पहुंच रहा है, जहां नियोक्ता केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल (स्किल) भी देखता है। नियोक्ता की अपेक्षा यह होती है कि छात्र ने कक्षाओं में जो सीखा है, वह उसे कार्यक्षेत्र (वर्कप्लेस) पर भी लागू कर पाए और 'रियल-टाइम प्राब्लम' का समाधान कर सके। लिहाजा, अब जरूरत हमारे पाठ्यक्रमों को उद्योगों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित या अपडेट करने की है, विशेषकर तेजी से विकसित (हाई ग्रोथ सेक्टर्स) हो रहे क्षेत्रों में। साथ ही इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स के जरिये व्यावहारिक अनुभव को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि छात्रों को प्रारंभिक स्तर पर ही इंडस्ट्री का व्यावहारिक अनुभव मिल सके। इससे वास्तविक तौर पर कौशल का विकास हो सकेगा और अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर उसका नए सिरे से गठन किया जाना चाहिए?

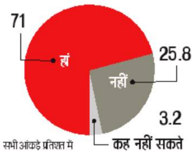

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से लिए गए फैसले उसके प्रति भरोसे को बहाल करने वाले हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

कौवा सेवा दे रहा बैठ राम दरबार,
रामायण पर स्वर्ण की रोज चढ़ रहा हार।
रोज चढ़ रहा हार बैंक में रक्खी चांदी,
लेकर जाएं माल स्वयं आ सारे वादी!
कालनेमि कह झूठ खड़ा कर बैठे हौवा,
काटेगा अब जाय उन्हीं को काला कौवा!!
-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

बदलती राजनीति में क्षेत्रीय दल

अजय कुमार राय
ajayrai@nda.jagran.com

क्षेत्रीय दलों में हो रहे विघटन को केवल दलबदल की सामान्य घटना से जोड़कर खारिज नहीं किया जा सकता। यह घटना भारतीय राजनीति में आ रही व्यापक रूपांतरण की अभिव्यक्ति है

तृणमूल कांग्रेस से बाहर निकलने के लिए एक बैठक में जुटे थे असंतुष्ट जनप्रतिनिधि। फाइल

पिछले दिनों बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हुई। विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और अब वे ममता बनर्जी को बेदखल कर तृणमूल कांग्रेस पर दावा जता रहे हैं। सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में पार्टी के 20 लोकसभा सदस्य भी अलग होकर एक नए दल में शामिल हो गए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्य पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के छह लोकसभा सदस्य टूटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसदों में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। आशंका है कि यह सिलसिला तमिलनाडु में डीएमके और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों तक भी पहुंच सकता है। देश के क्षेत्रीय दलों में हो रहे इस विघटन को केवल दलबदल की सामान्य घटना मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। वास्तव में, यह भारतीय राजनीति में उभर रहे एक व्यापक राजनीतिक रूपांतरण की अभिव्यक्ति प्रतीत होता है। इसके लिए अनेक कारक एक साथ जिम्मेदार नजर आते हैं।

मनभेद की राजनीति का बढ़ता वर्चस्व : आइएनडीआइए में शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व और सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच संबंध सामान्य नहीं दिखाई देते। देश की राजनीति को समझने वाला एक सामान्य नागरिक भी मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखकर यह कह सकता है कि पहले की तरह अब नेताओं के बीच केवल वैचारिक मतभेद नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के प्रति गहरे मनभेद और नफरत से भी भर गए हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके बीच मानवीय संवाद और आपसी मेलजोल लगभग ठप हो गया है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक गंभीर कमजोरी के रूप में सामने आ रहा है। क्षेत्रीय दलों के सांसद भी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस रवैये के कारण सत्ता पक्ष के साथ संवाद और तालमेल स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की क्षमता पर पड़ा है। चुनाव के दौरान वे मतदाताओं से अनेक वादे करते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। वर्तमान नफरत की राजनीति ने उनके लिए यह सहयोग प्राप्त करना कठिन बना दिया है। परिणामस्वरूप, अवसर मिलते ही वे दल बदलने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं।

सांस्कृतिक एकता : हाल के वर्षों में भारत में सांस्कृतिक एकता और हिंदू पहचान के प्रति सजगता बढ़ी है और यह निरंतर सशक्त होती जा रही है। इसके चलते मतदाताओं का एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण हो रहा है। अब क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय पहचानें राष्ट्रीय पहचान के साथ एक नए युग्म के रूप में जुड़ती जा रही हैं। अब मतदाता स्वयं को केवल अपनी क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि भारतीय पहचान, क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी तथा जाति के साथ हिंदू पहचान से भी प्रमुखता से जोड़ने लगे हैं। जैसे- मैं हिंदू भी हूं और तमिल भी। मैं भारतीय भी हूं और बंगाली भी। यद्यपि ये पहचानें पहले भी साथ-साथ मौजूद थीं, लेकिन आज इनके बीच का संबंध अधिक मजबूत होता दिखाई दे रहा है।

मतदाताओं के स्तर पर आ रहे इस परिवर्तन से जनप्रतिनिधि भी भली-भांति परिचित होंगे। हालांकि, कई क्षेत्रीय दलों के प्रमुख इस बदलाव को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके सदस्यों में एक प्रकार की छटपटाहट दिखाई देती है। यही व्यग्रता आजकल दलबदल के रूप में भी सामने आ रही है। जो क्षेत्रीय दल इस परिवर्तन को समझते हुए राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता और क्षेत्रीय गौरव के बीच संतुलन स्थापित कर सकेंगे, वही 21वीं सदी की भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख पाएंगे।

परिवारवादी दलों का कमजोर नेतृत्व : मानव का यह स्वभाव है कि वह अपने से कमजोर व्यक्ति का नेतृत्व या अधीनता सहजता से स्वीकार नहीं करता। आज कांग्रेस, राजद, सपा, डीएमके, बसपा, तृणमूल सहित अनेक दल परिवारवादी दलों में बदल गए हैं। इन दलों पर एक परिवार या एक व्यक्ति का वर्चस्व है। इन दलों के संस्थापकों में नेतृत्व की क्षमता थी, लेकिन अब कई ऐसे नेता हैं जिनमें वह बात नहीं दिखाई देती। इस कारण उनसे जुड़े कई नेताओं को यह लगता है कि वे उन्हें सत्ता तक नहीं पहुंचा सकेंगे, इसलिए अवसर मिलते ही वे पाला बदलने में देर नहीं करते।

क्षेत्रीय दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, परिवारवाद, सत्ताधारी दल से संवाद का अभाव व राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान से दूरी उनकी बड़ी कमजोरियां हैं। यदि उन्हें प्रासंगिक बने रहना है, तो इन भारतीय समाज और राजनीति में आ रहे परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए स्वयं में सुधार लाना होगा।

कल्टफिट ने सेबी के पास जमा किए आइपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली: फिटनेस से जुड़ी सेवाएं देने वाले प्लेटफार्म कल्टडाटफिट लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिये पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, प्रस्तावित आइपीओ में 950 करोड़ रुपये के नए शेयर और 17.86 करोड़ प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल कर्ज भुगतान, फिटनेस सेंटर नेटवर्क के विस्तार, नए विशेष ब्रांड आउटलेट स्थापित करने के लिए किया जाएगा। (प्रेट्र)

हाल के भूराजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में रुकावट और महंगाई के दबाव वाले मुश्किल वैश्विक माहौल के बीच भारत अलग व मजबूत स्थिति में रहा है।

– मोहित बर्मन, चेयरमैन, डाबर इंडिया

सेंसेक्स	78,180.72	▼ 104.35	
निफ्टी	24,398.70	▼ 31.65	
सोना	₹1,49,250	▼ ₹1,400	प्रति दस ग्राम
चांदी	₹2,39,800	▼ ₹1,400	प्रति किलो ग्राम
डालर	₹94.96	▼ ₹0.47	
क्रूड	$72.87		प्रति बैरल

एक नजर में

3.52 गुना सब्सक्राइब हुआ कोचीन का ओएफएस

नई दिल्ली : जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का आफर फार सेल (ओएफएस) पहले दिन ही 3.52 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस ओएफएस में गैर-खुदरा निवेशकों के लिए 59.66 लाख शेयरों बिक्री के लिए पेश किए गए हैं। इसके सापेक्ष 2.10 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोली लगाई है। सरकार कोचीन शिपयार्ड के 1.32 करोड़ शेयर या 5.04 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए ओएफएस लाई है। (प्रेट्र)

1,400 रुपये घटा सोने का मूल्य, चांदी भी लुढ़की

नई दिल्ली: रुपये में मजबूती और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत में 1,400 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। अब दिल्ली में पीली धातु का मूल्य 1,49,250 रुपये प्रति दस ग्राम (सभी करों सहित) हो गया है। इसी तरह, चांदी भी 200 रुपये घटकर 2,39,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो स्पाट गोल्ड 0.54 प्रतिशत घटकर 4,140.59 डालर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, स्पाट चांदी करीब दो प्रतिशत गिरकर 60.89 डालर प्रति औंस हो गई है। (प्रेट्र)

स्विगी में विदेशी निवेश 50 प्रतिशत से कम हुआ

नई दिल्ली : फूड डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी ने मंगलवार को बताया कि कंपनी में विदेशी निवेश 50 प्रतिशत से कम होकर 49.76 प्रतिशत पर आ गया है। कुल विदेशी निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अन्य अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल हैं। विदेशी निवेश 50 प्रतिशत से नीचे आने पर स्विगी को 'इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी' के तौर पर क्वालीफाई करने में मदद मिलेगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों के तहत, यह वर्गीकरण उन कंपनियों के लिए किया जाता है जिनका स्वामित्व और नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय नागरिकों या भारतीय संस्थाओं के हाथों में होता है। (प्रेट्र)

एआइ के वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी शून्य

550 अरब डालर का हो चुका है एआइ सर्विस और इससे जुड़ी सप्लाई चेन का वैश्विक बाजार

राजीव कुमार ● जागरण

- एआइ सर्विस देने में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे अधिक
- भारत में सालाना 10 लाख लोग एआइ के लिए कर रहे भुगतान

नई दिल्ली: रोजगारपरक सेक्टर में भारत का निर्यात बढ़ रहा है और विभिन्न विकसित देशों के साथ व्यापार समझौता होने से इसमें भारी बढ़ोतरी की संभावना भी है। दूसरी तरफ, तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी नगण्य दिख रही है। एआइ सर्विस और इससे जुड़ी सप्लाई चेन का बाजार 550 अरब डालर के पास पहुंच चुका है। ग्रांड व्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 से वर्ष 2033 के बीच एआइ के वैश्विक बाजार में सालाना 35.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। अगले सात साल में एआइ का वैश्विक बाजार 3500 अरब डालर का होगा।

ग्रांड व्यू और एलायंज की रिपोर्ट के मुताबिक एआइ सर्विस देने के मामले में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अमेरिका की एंथ्रोपिक्स, ओपन एआइ व एनविडिया जैसी बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं और इन कंपनियों के एआइ टूल्स व सेवाएं दुनियाभर के लोग ले रहे हैं। बदले में उन्हें भुगतान कर रहे हैं। भारत में सालाना 10 लाख लोग एआइ इस्तेमाल के बदले इन कंपनियों को प्रतिमाह 400 से लेकर 20,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। भारत में वित्त, स्वास्थ्य, इंश्योरेंस, विधि, रिटेल, मीडिया जैसे सेक्टर में एआइ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सैकड़ों छात्र एआइ सेवा के लिए प्रतिमाह 20 से 30 डालर का भुगतान ओपन एआइ और एंथ्रोपिक्स जैसी कंपनियों को कर रहे हैं। कंटेंट लिखने और तस्वीर बनाने वाले एआइ टूल के इस्तेमाल के लिए कंपनियां प्रतिमाह 50 हजार रुपये तक का भुगतान कर रही है। विभिन्न प्रोफेशनल्स का कहना है कि भारतीय एआइ माडल अभी अमेरिका के एआइ माडल की तरह विकसित नहीं है। इसलिए हमें दूसरे देशों की कंपनियों को पैसा देना पड़ रहा है।

एआइ सप्लाइ चेन में चीन सबसे आगे: एलायंज की रिपोर्ट के मुताबिक एआइ से जुड़ी सप्लाई चेन के वैश्विक बाजार में भी भारत की हिस्सेदारी अभी नाममात्र की है। एआइ से जुड़ी सप्लाई चेन में ताइवान (12 प्रतिशत), हांगकांग (11 प्रतिशत), चीन (18 प्रतिशत), जापान (तीन प्रतिशत), मलेशिया (चार प्रतिशत), सिंगापुर (सात प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (छह प्रतिशत) जैसे एशियाई देशों की हिस्सेदारी प्रमुख रूप से दिख रही है। एलायंज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में एआइ सप्लाई चेन में मैक्सिको, थाइलैंड, जैसे देशों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कुछ रिसर्च एजेंसियों का मानना है कि भारत अगले कुछ सालों के बाद तेजी से एआइ सेक्टर में विकास करेगा और एआइ बाजार में अमेरिका, चीन के बाद भारत की सबसे अधिक हिस्सेदारी होगी।

एआइ का इस्तेमाल बढ़ने से आइटी निर्यात पर असर संभव

विदेश व्यापार विशेषज्ञों ने बताया कि एआइ निर्यात के बाजार में प्रवेश लेने से भारत का निर्यात काफी तेजी से बढ़ सकता है। सर्विस सेक्टर के सालाना 400 अरब डालर से अधिक के निर्यात में 290 अरब डालर की हिस्सेदारी आइटी सेक्टर की है। लेकिन एआइ टूल्स व सर्विस के इस्तेमाल में बढ़ोतरी से आइटी निर्यात प्रभावित हो सकता है। विकसित देशों के साथ व्यापार समझौता होने से टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स-ज्वैलरी, इंजीनयरिंग गुड्स जैसे सेक्टर में भारत का निर्यात बढ़ने जा रहा है, लेकिन एआइ बाजार में पीछे छूटने से भारत इसका बड़ा आयातक बन सकता है। एआइ एक नए प्रकार का फ्यूल बन चुका है। एआइ सेवा लेने में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

एक अगस्त से ओपन मार्केट से शेयर बायबैक कर सकेंगी कंपनियां

सेबी ने ओपन मार्केट से शेयर बायबैक की व्यवस्था को फिर से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। एक अगस्त से कंपनियां ओपन मार्केट से अपने ही शेयरों की फिर से खरीदारी कर सकेंगी। सेबी के इस कदम का उद्देश्य सुगमता और क्रियान्वयन दक्षता बढ़ाना है। साथ ही, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पूंजी आवंटन के एक साधन के रूप में पुनर्खरीद को अधिक आकर्षक बनाना भी है।

पहले क्यों लगी थी रोक?

सेबी ने ओपन मार्केट के माध्यम से शेयर बायबैक की व्यवस्था को वर्ष 2025 में चरणबद्ध तरीके समाप्त किया था। उस समय नियामक ने शेयरधारकों के साथ असमान व्यवहार और टैक्स संबंधी विकृतियों पर चिंता जताई थी, क्योंकि यह व्यवस्था चुनिंदा निवेशकों के पक्ष में मानी जाती थी। इस व्यवस्था की फिर बहाली से कंपनियों की तरफ से शेयरधारकों को अतिरिक्त नकदी लौटाने और विशेष रूप से बाजार में कमजोरी के दौर में शेयर कीमतों को सहारा देने के लिए व्यापक रूप से अपनाए जाने वाले पूंजी प्रबंधन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

15% से कम होगी सीमा

सेबी की अधिसूचना के अनुसार, शेयर बाजार के माध्यम से खुले बाजार में पुनर्खरीद कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार के 15 प्रतिशत से कम होगा। इसकी गणना कंपनी के एकल और समेकित दोनों वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी। नए नियमों के तहत कंपनियां बायबैक के लिए अलग से 'बायबैक विंडो' के बिना नियमित कारोबार व्यवस्था के जरिए पुनर्खरीद कर सकेंगी। सेबी के निदेशक मंडल ने जून 2026 में ओपन मार्केट शेयर बायबैक संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

66 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

पुनर्खरीद की पेशकश सार्वजनिक घोषणा की तारीख से चार कार्य दिवस के भीतर खुलेगी और पेशकश खुलने की तारीख से 66 कार्य दिवस के भीतर बंद होगी। पहले यह अवधि अधिकतम छह महीने तक हो सकती थी। इसके अलावा कंपनियों को पुनर्खरीद के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति न करने की छूट होगी। मर्चेंट बैंकर नियुक्त नहीं करने पर उसकी ओर से किए जाने वाले कार्य कंपनी, अनुपालन अधिकारी, वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक और शेयर बाजारों को सौंपे जाएंगे।

आडिटर निभाएंगे अहम भूमिका

वैधानिक लेखा परीक्षक एस्क्रो खातों की निगरानी करेगा, जिसमें बैंक गारंटी, नकद जमा, 'एस्क्रो' निधियों का उपयोग और उन्हें जारी करना शामिल होगा। अनुपालन अधिकारी खुले बाजार में पुनर्खरीद के तहत शेयर को निरस्त किए जाने की निगरानी करेगा और उसका प्रमाणन करेगा। सेबी ने एक नया नियम जोड़ा है, जिसके तहत कंपनियां ऐसे बायबैक का एलान न करें जिनसे मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) के नियमों का उल्लंघन हो। साथ ही सेबी ने दो बायबैक आफर के बीच के कम से कम समय के अंतर को कंपनीज एक्ट, 2013 के नियमों के मुताबिक कर दिया है।

जागरण इन्फो

जून में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में जून में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री 3,06,220 यूनिट के अब तक के सबसे उच्चस्तर पर पहुंच गई। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के मुताबिक, यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 63 प्रतिशत ज्यादा है और इससे कुल ईवी हिस्सेदारी पहली बार 12 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।

ईवी बिक्री में वृद्धि की अगुआई दोपहिया वाहन क्षेत्र ने की और इस दौरान 1,93,735 यूनिट बिकीं। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,10,719 यूनिट था। इस तरह इस सेगमेंट की बिक्री में 74.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रिक यात्री वाहन की खुदरा बिक्री पिछले महीने दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 31,823 यूनिट हो गई, जबकि जून, 2025 में यह 15,318 यूनिट थी।

पिछले महीने सभी प्रकार के 3,06,220 ईवी की बिक्री हुई, इसमें जून 2025 के मुकाबले 63 प्रतिशत की वृद्धि रही

तिपहिया सेगमेंट में कुल खुदरा बिक्री 77,448 यूनिट रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 60,802 यूनिट थी। इस तरह इस सेगमेंट की बिक्री में साल-दर-साल 27.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन की खुदरा बिक्री पिछले महीने 3,214 यूनिट रही, जबकि पिछले साल जून में यह 1,219 यूनिट थी।

सभी प्रकार के लोन की बढ़ सकती है सीमा

- एसबीआइ ने विकसित भारत के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की
- सभी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन को प्राथमिक सेक्टर की श्रेणी में शामिल करने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: आने वाले समय में होम लोन से लेकर एजुकेशन लोन तक की सीमा बढ़ सकती है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, सभी प्रकार के इन्फ्रा, निर्यात और एमएसएमई लोन की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। एसबीआइ ने विकसित भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए बैंकों से मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इस पर अमल होता है तो प्राथमिक सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) के तहत मेट्रो में मकान खरीदने के लिए एक करोड़ तक का लोन मिल सकेगा। गैर मेट्रो शहर में पीएसएल के तहत 75 लाख होम लोन देने की सिफारिश की गई है। अभी शहर की आबादी के आधार पर होम लोन की सीमा तय होती है जो 50 लाख से लेकर 35 लाख तक है। एसबीआइ ने एजुकेशन लोन की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की सिफारिश की है।

एसबीआइ का मानना है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए बैंकों को लोन देने में बड़ी भूमिका अदा करनी होगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी लोन की सीमा को बढ़ाना होगा और नए-नए सेक्टर के लिए भी लोन के दरवाजे खोलने होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अभी बैंक अधिकतम 35 करोड़ का लोन देता है, जिसे बढ़ाकर 100 करोड़ करने की सिफारिश की गई है। सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन की सीमा सभी शहरों के लिए बढ़ाकर 25 करोड़ करने की सिफारिश की गई है। मंगलवार को जारी एसबीआइ की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन को प्राथमिक सेक्टर के लोन की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। प्राथमिक सेक्टर के लोन में जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभाव को कम करने के काम को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। एसबीआइ की इस सिफारिश पर वित्तीय सेवाएं विभाग भी पहले से काम कर रहा है। एसबीआइ की सिफारिश पर आरबीआइ को फैसला लेना है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 30 लाख करोड़ डालर से अधिक का होने का अनुमान है। बैंकों से काफी बड़े पैमाने पर लोन मिलने पर ही इस प्रकार के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय फलक

बैंक के काम में लापरवाही में वकीलों को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा-बैंक अन्य बैंकों को वकीलों के नाम भेज उन्हें पेशेवर अक्षम या लापरवाह ब्रांड नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बैंक सिर्फ लापरवाही या गलत कानूनी राय के आरोपों के आधार पर वकीलों का नाम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) की चेतावनी सूची में डालकर उन्हें पूरे बैंकिंग क्षेत्र से प्रभावी ढंग से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, वकीलों को ब्लैकलिस्ट करना उनके बार काउंसिल के कानूनी अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी या अतिक्रमण है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा व आलोक आराधे की पीठ ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा, वकीलों के पेशेवर आचरण से संबंधित प्रश्न एडवोकेट एक्ट के तहत बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो बैंकों के पास कानूनी पेशेवर को सेवामुक्त करने और पैनल से उसका नाम हटाने का विकल्प होता है, पर किसी वकील के आचरण, योग्यता या अयोग्यता के बारे में अन्य सभी बैंकों के समक्ष सार्वजनिक घोषणा करना स्पष्ट रूप से उनकी शक्ति और अधिकार क्षेत्र से परे और अवैध है।

हालांकि कोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह वकीलों के लिए नेशनल लीगल एकेडमी बनाने पर विचार करे और वकीलों के साथ-साथ एकेडेमिक संस्थान स्थापित करने के क्षेत्र में विशेषज्ञों की टीम बनाए। कोर्ट ने कहा, उम्मीद है कि बीसीआइ इस जिम्मेदारी को निभाएगी और अपने निर्णय के बारे में कोर्ट को सूचित करेगी। कोर्ट ने यह फैसला एक वकील द्वारा दाखिल अपील पर दिया है जिसमें उसने आइबीए की चेतावनी सूची में उसका नाम शामिल किए जाने को चुनौती दी थी, क्योंकि कैनरा बैंक ने उस पर ऋण लेनदेन के लिए स्वामित्व राय देते समय लापरवाही का आरोप लगाया था। कोर्ट ने बैंक को और आइबीए को निर्देश दिया है कि वह उस वकील का नाम तुरंत चेतावनी सूची से हटा दें।

कोर्ट ने कहा-वकीलों को ब्लैकलिस्ट करना उनके अधिकार क्षेत्र में बार काउंसिल की दखलंदाजी है

केनरा बैंक को वित्तीय जोखिम से शुरू हुआ विवाद : यह विवाद तब शुरू हुआ जब कैनरा बैंक ने आरोप लगाया कि वकील ने 2015 की कानूनी राय में इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि दो करोड़ रुपये के ऋण के लिए गिरवी रखी जमीन का एक हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका था, इससे बैंक को वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ा। बैंक ने 2019 में उस वकील को पैनल से हटा दिया था। उसने वकील का नाम आइबीए को भी भेज दिया था जिसके बाद से उसे चेतावनी सूची में डाल दिया गया था, जिससे टिप्पणी की गई थी कि उसने गलत राय दी थी व लापरवाही से काम किया था। वकील का कहना था कि इसके कारण उनका अन्य बैंकों से साथ अनुबंध समाप्त हो गया और उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकील की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आइबीए संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनौती सिर्फ बैंक के संविदात्मक निर्णय के विरुद्ध नहीं बल्कि एक उद्योग व्यापी तंत्र के विरुद्ध थी। जिसके संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत वकील के पेशे के अधिकार पर गंभीर परिणाम होते हैं। कोर्ट ने आरबीआइ परिपत्रों की जांच की और माना कि उनका उद्देश्य बैंकों को उन तीसरे पक्षों के बारे में सचेत करना था जो कि बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले धोखाधड़ी या अन्य बेइमान आचरण में शामिल थे।

जबरन श्रम से जुड़े 12.5% टैरिफ पर अमेरिका फिर करे विचार : भारत

साथ ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत ने अमेरिका से उस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का अनुरोध किय है, जिसके तहत जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक लगाने में कथित विफलता के चलते भारत पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं भारत ने किसी भी खास चिंता को दूर करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। यूएसटीआर ने 11 और 12 मार्च, 2026 को जबरन श्रम और जरूरत से ज्यादा औद्योगिक क्षमता से जुड़ी चिंताओं को लेकर 60 देशों के खिलाफ दो अलग-अलग 'सेक्शन 301' जांच शुरू की थीं। तीन जून को यूएसटीआर ने जबरन श्रम से जुड़ी जांच के नतीजे जारी किए और 54 देशों से होने वाले आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा।

प्रतीकात्मक

इस प्रस्ताव में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मैक्सिको और पाकिस्तान से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ और भारत व चीन सहित 48 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से होने वाले आयात पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात शामिल है। यह उपाय अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है और इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। छह जुलाई को यूएसटीआर को सौंपे गए अपने जवाब में भारत ने कहा कि यूएसटीआर उन सुबूतों को पेश करने में नाकाम रहा है, जिनसे यह साबित हो सके कि इन देशों में प्रतिबंध न होने से बाजार की स्थितियों में निर्णायक या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है और नियमों का पालन करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ता है।

भारत ने आगे कहा, 'सिर्फ जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक नहीं होने को 'सेक्शन 301' के तहत गलत नहीं माना जा सकता है। भारत ने कहा कि यूएसटीआर ने जिन 60 देशों में चल रहे कानून और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विशेष विश्लेषण नहीं किया है। इसके बजाय उसने बिना यह देखे कि देश कौन से खास उपाय लागू कर रहे हैं, एक व्यापक फैसला सुना दिया।

एनपीएस के तहत स्वायत्त निकायों के कर्मियों को मिले दो और निवेश विकल्प

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत निवेश के दो और विकल्प उपलब्ध कराए हैं। दरअसल, इससे पहले सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निवेश के अतिरिक्त विकल्प (जैसे एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड) शुरू किए थे और अब इन्हें केंद्रीय स्वायत्त निकायों में काम करने वाले एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है।

एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी-75) एक ऐसा निवेश विकल्प है, जिसमें इक्विटी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत तक होती है। इसे उन सब्सक्राइबर के लिए तैयार किया गया है जो लंबे समय में ज्यादा वृद्धि चाहते हैं। वहीं बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (बीएलसी) एक ऐसा निवेश विकल्प है, जिसमें इक्विटी हिस्सेदारी की सीमा 50 प्रतिशत है और 45 साल की उम्र से इक्विटी एलोकेशन में धीरे-धीरे कमी की जाती है, जिससे ग्रोथ और स्थिरता के बीच एक संतुलन रहता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन निवेश विकल्पों के दायरे में केंद्रीय स्वायत्त निकायों के एनपीएस सब्सक्राइबर को लाने का मकसद उन्हें ज्यादा लचीलापन देना है ताकि वे अपने पेंशन निवेश को अपनी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरतों के हिसाब से समायोजित कर सकें। ये निवेश विकल्प रिटायरमेंट स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस को और आकर्षक बनाते हैं।

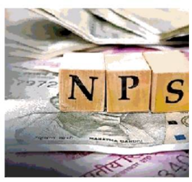

नेशनल पेंशन सिस्टम। फाइल

हाई-वे प्रोजेक्ट

30% से कम बोली पर लगेगी अधिक अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी

गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बार फिर नियमों में किया बदलाव, 30 प्रतिशत से कम प्रत्येक प्रतिशत पर होगी 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि, ई-बैंक गारंटी का भी नियम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं चाहती, लेकिन ठेकेदार प्रतिस्पर्धा में कम से कम मूल्य पर भी टेंडर पाने में संकोच नहीं कर रहे। निर्धारित सीमा से कम बोली पर अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी के पूर्व में लागू नियम का खास असर नहीं देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब नियमों को और सख्त कर दिया है। टेंडर के आधार मूल्य से 30 प्रतिशत कम बोली लगाने पर अब तीन प्रतिशत की एडीशनल परफारमेंस गारंटी को फिर लागू करते हुए इसमें प्रत्येक प्रतिशत की गिरावट के साथ 0.5 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रविधान कर दिया है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में एडीशनल परफारमेंस गारंटी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसमें कहा गया है कि निविदा के आधार मूल्य से 30 प्रतिशत से कम बोली लगाने वाली ठेकेदार फर्म को अब कुल निविदा मूल्य के तीन प्रतिशत के अलावा इस सीमा से नीचे प्रत्येक प्रतिशत पर 0.5 प्रतिशत की दर से एडीशनल परफारमेंस गारंटी जमा करनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से परफारमेंस गारंटी में सिर्फ ई-बैंक गारंटी को अनिवार्य कर दिया है।

हाईवे प्रोजेक्ट। फाइल

क्षमता से बड़ा टेंडर लेने वाले ठेकेदार होंगे प्रतिस्पर्धा से बाहर

माना जा रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई व्यवस्था से वे छोटे ठेकेदार प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकते हैं, जो अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक बड़ी परियोजनाओं का टेंडर ले लेते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल में हाथ तंग होने पर परियोजनाएं लंबित होती हैं और वे गुणवत्ता से भी समझौता करने का प्रयास करते हैं। ये नए नियम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी), हाइब्रिड एन्युटी मोड और मेंटिनेंस यानी रखरखाव वाले प्रोजेक्ट पर लागू होंगे।

पहले यह थी व्यवस्था

पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए थे, तब एडीशनल परफारमेंस गारंटी की अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत थी। लेकिन 2025 में इस कैप को हटाते हुए व्यवस्था बनाई थी कि जो ठेकेदार फर्में 10 प्रतिशत से कम बोली लगाएंगी, उन्हें 10 से नीचे के प्रत्येक प्रतिशत पर 0.1 प्रतिशत की दर से परफारमेंस गारंटी जमा करनी होगी, जबकि 20 प्रतिशत से कम पर प्रत्येक प्रतिशत पर 0.2 प्रतिशत की दर से इसे जमा करना होगा। अब सरकार को लगता है कि इस नियम के बावजूद ठेकेदार 30 प्रतिशत से कम बोली लगाने को लेकर हतोत्साहित नहीं हुए हैं, इसलिए नियमों को और सख्त किया गया है।

साख का सवाल

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय बंसल और सदस्य अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने सही कहा है कि 'इस पूरे प्रकरण से न्यास की छवि धूमिल हुई है।' मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हर सनातनी की गहरी आस्था है और वह हर हाल में यथावत रहेगी, मगर उनके काम-काज में किसी किस्म के अमर्यादित आचरण से क्षोभ व जन-आक्रोश का उपजना स्वाभाविक है। इसलिए, जब रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी का खुलासा हुआ, तो देश-विदेश का हरेक हिंदू स्तब्ध रह गया! इस एक मंदिर के लिए सनातनियों के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष ने काफी त्रासद स्थितियां झेली हैं। यह संतोष की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना वक्त गंवाए विशेष जांच दल का गठन किया और चंद घंटों के भीतर ही न सिर्फ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, बल्कि आठ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और अब ब्योरे हैं कि उनसे नकदी व आभूषणों की बरामदगी की गई है। सवाल है, न्यास बोर्ड के सदस्य अब एक-दूसरे पर तोहमत लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वे हैरान करने वाले हैं। बकौल गिरी, कोषाध्यक्ष होते हुए भी कोष के प्रबंधन में उनकी सीधी भूमिका नहीं थी!

जो घटित हो चुका है, उसका फैसला तो अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है, उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा।

नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को सौंपने का अपना फैसला सुनाया था, तब उसी फैसले में सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट, यानी न्यास का गठन करे। विडंबना यह है कि राम मंदिर बनाने के नाम पर जितनी राजनीति हुई, ट्रस्ट के गठन और सदस्यों के चयन को लेकर उससे कुछ कम विवाद नहीं हुए। यहां तक कि मंदिर बनने के बाद इसके लोकार्पण की तिथि और समारोह से चारों शंकराचार्यों की दूरी ने भी हिंदू धर्मावलंबियों में एक बड़ी बहस को जन्म दिया। उस समय भी चंपत राय के कुछ बयान साधु-संतों को नागवार गुजरे थे, मगर भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले गदगद थे कि उनके आराध्य का मंदिर साकार रूप ले चुका है। श्रद्धालुओं के इस भाव के संरक्षण की महती जिम्मेदारी ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक-एक व्यक्ति की थी।

बहरहाल, जो घटित हो चुका है, उसका फैसला तो अब अदालत को करना है, मगर जो आगत है, उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए कि अब किसी श्रद्धालु के मन में यह शंका न बचे कि उसने जो कुछ अपने प्रभु को अर्पित किया है, वह कल चोरी हो जाएगा। निस्संदेह, इस भव्य मंदिर की सुरक्षा और इसके रख-रखाव का खर्च बहुत अधिक है, मगर इसी देश में दर्जनों ऐसे बड़े ट्रस्ट और धर्मार्थ संगठन काम कर रहे हैं, जिनके प्रबंधन की मिसालें दी जाती हैं। मंदिर व्यवस्था के साथ-साथ ये ट्रस्ट शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक स्थानीय लोगों के कल्याण के कई ऐसे कार्य करते हैं, जिनसे उनके प्रति आस्था तो गहरी होती ही है, उनकी सुरक्षा का घेरा भी मजबूत होता है। चढ़ावा चोरी मामले में गठित विशेष जांच दल और इस ट्रस्ट की साख दांव पर है। जितनी जल्दी इस पूरे प्रकरण का खुलासा होगा और दोषियों को सजा होगी, चाहे वह दोषी कोई भी हो, लोगों के भरोसे की बहाली में उतनी ही आसानी होगी। यह समय तंत्र में जन-विश्वास की प्रतिष्ठा का है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 जुलाई, 1951

ग्राहम दिल्ली पहुंचे

संयुक्त राष्ट्रीय काश्मीर प्रतिनिधि डा. फ्रैंक पी. ग्राहम अपने दल सहित गत सोमवार को कराची से दिल्ली आ पहुंचे। आगमन पर उन्होंने पत्रों (अखबारों) को जो वक्तव्य दिया, उसमें कहा: 'भारत तथा पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि के नाते मेरा लक्ष्य दोनों राष्ट्रों के बीच की कलह को बातचीत, समझौता तथा सद्भावना के शांतिपूर्ण उपायों द्वारा सुलझाना है। हमें विश्वास है कि दोनों महान राष्ट्र जम्मू तथा काश्मीर की विषम समस्या को सुलझाने में अपना उत्तरदायित्व निभाकर हमें सहायता प्रदान करेंगे।'

हम श्री ग्राहम की सद्भावना का स्वागत करते हैं, किन्तु उनके लक्ष्य की सफलता में हमें सन्देह ही है। सुरक्षा-परिषद ने काश्मीर की समस्या को सुलझाने में जिस प्रकार की पक्षपातपूर्ण नीति प्रदर्शित की है और भारत की उचित भावनाओं की अवहेलना की है, उससे भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता कि वह परिषद के गत 30 मार्च के प्रस्ताव को न मानकर डा. ग्राहम के साथ असहयोग करे। भारत के उप-विदेश मंत्री डा. बी.वी. केस्कर ने हाल में एक भाषण देते हुए भारतीय जनता की इस भावना को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि सुरक्षा परिषद ने भारत और काश्मीर की जनता की इच्छा के विरुद्ध अपना कोई निर्णय थोपने का प्रयत्न किया, तो हम पूरी शक्ति से उसका प्रतिरोध करेंगे। शेख अब्दुल्ला ने भी एक बार फिर काश्मीर की जनता के दृढ़ मत को दुहराया है। वह लोकतंत्री ढंग से अपने भविष्य का निर्णय करने में संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी भी विदेशी राष्ट्र को बाधक न बनने देगी। ऐसी स्थिति में डा. ग्राहम का कार्य बड़ा नाजुक है। उनकी तनिक-सी भी असावधानी से भारत में सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा को भारी धक्का पहुंचेगा। पाकिस्तान में रणोन्मादः पाकिस्तान से पिछले कुछ दिनों से जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उनसे पता चलता है कि वहां एक प्रकार का रणोन्माद-सा छाया हुआ है। पाकिस्तानी पत्र और सरकार-नियंत्रित रेडियो भी काश्मीर के प्रश्न पर अनर्गल प्रचार कर रहे हैं और भारत के प्रति घृणा की आग फैला रहे हैं। हाल में सशस्त्र पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध-विराम संधि का उल्लंघन कर भारतीय सीमा में अनेक छापे मारे हैं।

हमारी साझेदारियों में चीन एक बड़ा मुद्दा

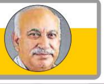

यहां स्कैन करें

एम जे अकबर | वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व केंद्रीय मंत्री

जब हम पूरब की ओर देखते हैं, तो हमें सिर्फ आर्थिक अवसर नहीं दिखते, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी दिखती हैं, जो एशिया का नक्शा बदल सकती हैं।

अब 'स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' (रणनीतिक साझेदारी), या इससे भी बड़ी 'कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' (व्यापक रणनीतिक साझेदारी) जैसी शब्दावलियां इतनी आम हो गई हैं कि कई द्विपक्षीय समझौतों में इनका असर सिर्फ कूटनीतिक दिखावे तक सीमित रह जाता है। सामरिक ताकत का असली लक्ष्य ये हासिल नहीं कर पातीं। मई 2018 में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इंडोनेशिया गए (हालांकि, आज वह ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं)। क्या इसका कोई खास मतलब है? या, बस यह ऐसी बात है, जो खुशनुमा एहसास देती है व एक-दूसरे के अहं को तुष्ट करती है?

सिर्फ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश आपसी रिश्तों को यह ऊंचाई नहीं देते। इसके लिए तो सस्ते हवाई टिकट और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद टैरिफ सिस्टम ही काफी हैं। रणनीतिक साझेदारी, खासकर जब उसमें 'व्यापक' जोड़ा जाता है, तो उसका अर्थ होता है, भू-राजनीतिक दायरे में परिभाषित साझा सुरक्षा चुनौतियों पर आपसी सहयोग बढ़ाना।

निस्संदेह, शांति और सद्भाव के आदर्शों पर चलने वाली दुनिया में, दो देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद किसी तीसरे देश के प्रति दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, पर हम वास्तविक दुनिया में रहते हैं, आदर्शवादी दुनिया में नहीं। इस समय चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य-आर्थिक संबंधों को सऊदी अरब तक विस्तार देने की कोशिशों में हैं; पिछले तीन हफ्तों में सऊदी मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने बीजिंग की यात्रा की है। मुमकिन है, इस वक्त सऊदी अरब की प्राथमिकताएं पाकिस्तान और चीन से अलग हों। उसकी रणनीतिक चिंताएं खाड़ी क्षेत्र में ईरान के बढ़ते दबदबे को लेकर होंगी, खास तौर से ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के शर्मनाक प्रदर्शन और इस खित्ते से काफी हद तक (पूरी तरह नहीं) उसके पीछे हटने के बाद। पाकिस्तान का सिर्फ एक मकसद है। वह भारत के साथ टकराव की किसी भी स्थिति का अपने हित में फायदा उठाना चाहता है। उसने चीन और अमेरिका के साथ गोलमोल बातें करके यही किया था और सऊदी अरब के साथ भी वह यही करेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा भी खोल लिया है, क्योंकि उसका मानना है कि काबुल नई दिल्ली के लिए तुरुप का पत्ता है, जबकि यह उसकी गलतफहमी है और इसका उसे आगे चलकर नुकसान भी होगा, क्योंकि अफगानिस्तान किसी देश का पिछलग्गू नहीं है।

पिछले हफ्ते भारत और जापान ने 2014 में बनी अपनी 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक ऐंड ग्लोबल पार्टनरशिप' को और मजबूत करते हुए 'स्टेल्थ तकनीक' में सहयोग करने का फैसला किया। इस पर मीडिया में बहुत चर्चा नहीं हुई, मगर यदि यह योजना साकार होती है, तो इसे व्यापक बदलाव लाने वाला कदम माना जाएगा। शायद इसीलिए बीजिंग ने तुरंत बयान जारी किया कि किसी भी गठबंधन का मकसद किसी तीसरे देश को निशाना बनाना नहीं होना चाहिए, जबकि वह खुद ऐसा करता रहा है। जापान इस बात को नजरंदाज नहीं कर रहा कि चीन 2028 तक, या कम से कम इसी दशक में ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी उसने घोषणा भी कर रखी है। अगर ऐसा हुआ, तो एक ऐसी जंग छिड़ सकती है, जिससे जापान भी बच नहीं पाएगा। भारत जानता है कि चीन के एकीकरण का जो फलसफा राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार-बार दोहराते रहते हैं, उसमें भारतीय इलाकों, खास तौर से अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना भी शामिल है। जाहिर है, मौजूदा हालात ने भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को अहम बना दिया है।

भारत और इंडोनेशिया ने सोच-समझकर अपने सैन्य सहयोग को मिसाइल, युद्धपोत और तकनीक के स्तर तक बढ़ाया है। आपको लग सकता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तो वहां की वायु सेना ने जो स्वागत किया, वह बस दिखावा था या 30,000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खिंचवाने का एक अवसर भर, किंतु मैं इसे ऐसा प्रतीक मानता हूं, जो बढ़ते सैन्य सहयोग के मद्देनजर सोच-विचारकर तैयार किया गया था। दोनों देश समझते हैं कि ऊर्जा और जल-मार्गों पर नियंत्रण के लिए होने वाली वैश्विक जंग का अगला मैदान हिंद महासागर बन सकता है और इस महासागर का सबसे अहम मोड़ या 'चोक प्वॉइंट' मलक्का जलडमरूमध्य है। इसी रास्ते से चीन की 80 फीसदी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं, साथ ही आसियान, जापान, चीन व दक्षिण कोरिया जैसी पूर्वी एशिया की बड़ी ताकतों का व्यापार भी यहीं से होता है। होर्मुज में हुई जंग ने मलक्का जलमार्ग की सुरक्षा-जरूरतों को और बढ़ा दिया है।

अंडमान और निकोबार में नौसेना-सुविधाओं के विस्तार से नई दिल्ली की रक्षा क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। अब भारत और इंडोनेशिया को मलक्का जलमार्ग पर वही भू-राजनीतिक बढ़त हासिल है, जो ईरान और ओमान की होर्मुज पर है। ऐसे में, भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक सहयोग महज कूटनीतिक शिष्टाचार या दिखावटी मेल-मिलाप वाला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक जरूरत बन गया है। निस्संदेह, इस तरह के शासकीय दौरों के दौरान होने वाली हर बातचीत का ब्योरा संबंधित देशों के प्रवक्ता नहीं बताया करते, पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच होने वाली बातचीत के एजेंडे में मलक्का का मुद्दा जरूर शामिल रहा होगा। इसलिए, जो बातें प्रच्छन्न हैं, उनको जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि दोनों देशों को सहयोग बढ़ाना चाहिए और जब इस क्षेत्र व दुनिया पर संकट आए, तो उन्हें साझा सुरक्षा नीति बनानी चाहिए। ऐसा न करना समझ से परे होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा उनके सबसे अहम दौरों में एक माना जाएगा, खास तौर से अमेरिका द्वारा बिना सोचे-समझे और एकतरफा ढंग से 'हिंद प्रशांत' शब्द में बदलाव के बाद। दिवंगत प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने 1990 के दशक में भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (पूरब की ओर देखो नीति) की शुरुआत की थी, लेकिन जब हम पूरब की ओर देखते हैं, तो हमें सिर्फ आर्थिक अवसर नहीं दिखते, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी दिखती हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एशिया का नक्शा फिर से बदल सकती हैं। अगर भारत और इंडोनेशिया इस बात पर सहमत हों कि मौजूदा व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, तो एशिया में शांति चाहने वालों को और मजबूती ही मिलेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

उलटफेरों में ही छिपा खेलों का असली रोमांच

यहां स्कैन करें

विवेक शुक्ला | वरिष्ठ पत्रकार

अगर आप ब्राजील के फैन हैं, तब भी अपनी पसंदीदा टीम के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर उदास मत होइए। जरा सोचिए, अगर खेलों में उलटफेर नहीं होंगे, तो खेलों का आनंद कहां रह जाएगा? ब्राजील का हारना इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर है। पांच बार का विश्व चैंपियन ब्राजील राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से 1-2 से हार गया। एर्लिंग हालांड के दो गोलों ने पसंदीदा टीम ब्राजील को घर भेज दिया। नेमार ने पेनल्टी पर गोल किया, पर वह काफी नहीं था। यह 1990 के बाद ब्राजील की सबसे जल्दी घर वापसी है।

यह हार खेल की उस सच्चाई को बताती है कि कोई भी टीम अजेय नहीं होती। उलटफेर तब होता है, जब कमजोर मानी जाने वाली टीम या खिलाड़ी मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हरा दे। फुटबॉल में ब्राजील जैसी दिग्गज टीम का हारना फैंस के लिए सदमा तो है, लेकिन यही खेलों का आनंद व उसकी खूबसूरती भी है। ब्राजील की टीम हमेशा स्टार प्लेयर्स से भरी रही है- पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, नेमार। फिर भी, नॉर्वे जैसी टीम ने उसे रोका। हालांड जैसे नए स्टार ने साबित किया कि फॉर्म, रणनीति और दिन का साथ कितना अहम होता है।

ब्राजील अगले विश्व कप में वापसी करेगा, पर इस हार की कसक उसे सदा रहेगी। खेलों का यही जादू है- कभी हार, कभी जीत, पर हमेशा उम्मीद।

फुटबॉल के इतिहास में ऐसे कई यादगार उलटफेर हुए हैं। 1950 के विश्व कप में उरुग्वे ने ब्राजील को माराकाना स्टेडियम में 2-1 से हराया। दो लाख से ज्यादा दर्शक थे, ब्राजील को सिर्फ ड्रॉ चाहिए था, पर उरुग्वे ने इतिहास रच दिया। अब बात 2022 विश्व कप की। तब सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। मेस्सी की टीम शुरू में पसंद की जा रही थी, पर सऊदी ने कमाल कर दिखाया। 1950 में ही अमेरिका ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था, जिसे तब बड़े उलटफेर में गिना गया था।

दूसरे खेलों में भी ऐसे उदाहरण भरपूर हैं। बॉक्सिंग में अजेय माने जाने वाले माइक टायसन 1990 में जेम्स बस्टर डगलस से हार गए। क्रिकेट के 2003 के विश्व कप में केन्या ने श्रीलंका को हरा दिया था। आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड को झटका दिया। ओलंपिक में 1980 'मिरेकल ऑन आइस' सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है, जिसमें अमेरिका की आइस हॉकी टीम ने सोवियत संघ की मजबूत टीम को हरा दिया था।

याद कीजिए, 15 फरवरी, 1978 को हुए विश्व के सर्वकालिक महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली का अनाम लियोन सिंपक्स के मुक्कों की बौछार के आगे पस्त हो जाना, पर उस हार से मोहम्मद अली का कद कतई छोटा नहीं हुआ, बल्कि इस अप्रत्याशित पराजय से खेलों की दुनिया ज्यादा जीवंत हो गई।

यहीं पर साल 2001 के विम्बलडन फाइनल मैच का जिक्र लाजिमी है। वह फाइनल यादगार था। 125 रैंकिंग वाले क्रोएशिया के गोरान इवानसेविक ऑस्ट्रेलियाई पैट राफ्टर के सामने थे। टेनिस के पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी कि राफ्टर क्रोएशियाई खिलाड़ी को धो देंगे। तीसरी वरीयता क्रम के खिलाड़ी राफ्टर ने सेमी-फाइनल में विश्व के नंबर एक आंद्रे आगासी को हरा दिया था। फाइनल देखने के लिए सेंटर कोर्ट की दर्शक दीर्घाएं ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों से खचाखच भरी थीं। वे राफ्टर की जीत के बाद जश्न मनाने के मूड में थे, पर फाइनल में क्रोएशियाई खिलाड़ी की फर्राटेदार सर्विस के आगे राफ्टर ने घुटने टेक दिए। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के ऊपर जो बीती, उसे बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय संदर्भ में बात करें, तो साल 1983 के क्रिकेट विश्व कप में कपिल देव की टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर सबको हैरान कर दिया था।

ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि खेल में तैयारी, मनोबल, रणनीति और थोड़ी किस्मत का मेल जरूरी होता है। बड़ी टीमें अक्सर दबाव में खेलती हैं, जबकि 'अंडरडॉग' बिना किसी उम्मीद के खुलकर खेलते हैं। अगर खेल में हमेशा वही जीते, जो मजबूत है, तो फिर यह बॉलीवुड फिल्मों जैसा मामला बन जाएगा। उलटफेर अनिश्चितता लाते हैं, जिनसे रुचि बढ़ती है।

अगला मैच देखते समय याद रखें, पसंदीदा टीम हो या अंडरडॉग, मैदान पर सब बराबर हैं। रोमांच इसी में है। ब्राजील अगले विश्व कप में वापसी करेगा, लेकिन इस हार की कसक हमेशा रहेगी। खेलों का यही जादू है- कभी हार, कभी जीत, लेकिन हमेशा उम्मीद।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सच्चा ब्रह्मचारी कौन

अधिकांश लोग मानते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना या शारीरिक संबंधों का पूर्ण त्याग करना है। यही कारण है कि अनेक गृहस्थ यह सोचकर साधना से दूर रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए उन्हें पारिवारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में यह धारणा अधूरी और भ्रामक है।

ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है, मन की बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बनाकर उसे पूर्णतः ब्रह्म की ओर प्रवाहित करना। जब मन बाहरी विषयों, इंद्रिय सुखों और भौतिक आकर्षणों में उलझा रहता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, लेकिन जब वही मन सूक्ष्म चेतना की ओर मुड़ता है, तब वह ब्रह्म के निकट पहुंचने लगता है। यही ब्रह्मचर्य का सार है। सृष्टि का स्थूल रूप वही है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, जबकि मन सृष्टि का सूक्ष्म पक्ष है। प्रकृति (प्रकृति शक्ति) के प्रभाव से मन धीरे-धीरे स्थूल विषयों की ओर आकर्षित होता जाता है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति का अधिकांश समय भौतिक वस्तुओं, इच्छाओं और आसक्तियों में बीतने लगता है। आध्यात्मिक मुक्ति का अर्थ है, मन को प्रकृति के इस प्रभाव से मुक्त कर पुनः सूक्ष्मता की ओर ले जाना।

ब्रह्म स्वयं अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए जो मन केवल स्थूल विषयों में डूबा रहता है, वह ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। जब साधना के माध्यम से मन का आकर्षण स्थूल से हटकर सूक्ष्म की ओर होने लगता है, तब वह धीरे-धीरे ब्रह्म में लीन होने लगता है। यही अवस्था वास्तविक ब्रह्मचर्य है। सच्चा ब्रह्मचारी वह नहीं है, जिसने केवल शारीरिक संयम अपनाया हो, बल्कि वह है, जिसका मन निरंतर ब्रह्म में स्थित रहता है। उसकी चेतना बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होती। यह स्थिति किसी बाहरी नियम से नहीं, बल्कि नियमित साधना से प्राप्त होती है।

सामान्यतः लोग केवल काम पर विजय को ब्रह्मचर्य मान लेते हैं, जबकि दर्शन के अनुसार मनुष्य के भीतर छह शत्रु (षड्रिपु) हैं- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य तथा आठ बंधन (अष्टपाश) कार्य करते हैं। ये सभी मन को बाहर की ओर खींचने वाली शक्तियां हैं

सच्चा ब्रह्मचारी वह नहीं है, जिसने केवल शारीरिक संयम अपनाया हो, बल्कि वह है, जिसका मन निरंतर ब्रह्म में स्थित रहता है। उसकी चेतना बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होती।

और सामूहिक रूप से अविद्या माया कहलाती हैं। केवल काम पर नियंत्रण पा लेने से ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं होती। जब तक मन इन सभी बंधनों से मुक्त नहीं होता, तब तक वह ब्रह्मोन्मुख नहीं हो सकता।

इन गहरे मानसिक बंधनों पर विजय केवल संकल्प या दमन से संभव नहीं है। इसके लिए नियमित साधना आवश्यक है। जो लोग साधना किए बिना केवल बाहरी नियमों या कठोर व्रतों के माध्यम से ब्रह्मचर्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे वास्तविक लक्ष्य से दूर रह जाते हैं।

श्री श्री आनंदमूर्ति

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

सफलता आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, लेकिन इसे आकार देने में आपके माता-पिता के त्याग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और समाज के सहयोग की भूमिका भी कम नहीं है। इसलिए, समाज के प्रति दायित्व निर्वहन भी आपकी जिम्मेदारी बनती है।

समाज के बदलते मनोविज्ञान का संकेत

आगरा में सामने आए उस हृदयविदारक मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने का आरोप है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज के बदलते मनोविज्ञान का गंभीर संकेत भी है। जिस घर को सुरक्षा, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, वही यदि भय और हिंसा का केंद्र बन जाए, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

आज का समय अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति, आर्थिक अवसरों और आधुनिक जीवनशैली का दौर है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं और रिश्तों की गर्माहट भी लगातार कमजोर होती दिख रही हैं। पति-पत्नी का संबंध भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और विश्वासपूर्ण माना गया है। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और अनेक भावनाओं का संगम होता है। जब इस रिश्ते में अविश्वास, क्रोध, स्वार्थ और हिंसा प्रवेश कर जाते हैं, तब उसका परिणाम केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की आत्मा को भी घायल करता है। पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों से पति या पत्नी द्वारा अपने जीवनसाथी की हत्या के कई मामले सामने आए हैं। कहीं अवैध संबंधों के कारण हत्या हुई, कहीं संपत्ति के विवाद ने रिश्ते खत्म कर दिए, तो कहीं लंबे समय से चले आ रहे घरेलू विवाद हिंसक रूप ले बैठे। इन घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जिन लोगों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाईं, वे एक-दूसरे की जान लेने में हिचक नहीं रहे।

बेशक ऐसे अपराध समाज के अधिकांश परिवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। देश में करोड़ों परिवार आज भी प्रेम, विश्वास और परस्पर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं, तो वे गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े करती हैं। क्या हमारी सहनशीलता कम हो रही है? क्या संवाद की जगह आक्रोश ने ले ली है? क्या छोटी-छोटी बातों का समाधान बातचीत से निकालने के बजाय हिंसा को आसान रास्ता समझा जाने लगा है? आगरा की घटना में जिस तरह शव को छिपाने का प्रयास किया गया, उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। यह घटना केवल हत्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके बाद किए गए कथित प्रयासों ने भी समाज को विचलित किया है। ऐसे मामलों में कानून अपना कार्य करता है, फिर भी ऐसी घटनाएं बताती हैं कि अपराध की मानसिकता कितनी भयावह हो सकती है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

रिश्तों का कत्ल

महिला हमेशा जुल्म क्यों बर्दाश्त करे

हर अपराध की शुरुआत हथियार से नहीं होती। कई अपराधों की शुरुआत घर के अंदर रोज मरने वाली इंसानियत से भी होती है। महिला का पति रोज शराब पीकर मारता है। माता-पिता कोई साथ नहीं देता, क्योंकि हमारा समाज बेटी का तलाकशुदा होना एक अपराध मानता है। ऐसे में, आगरा की घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, बल्कि यह उन सवालों का आईना भी है, जिनसे हमारा समाज वर्षों से बचता आया है। सोचिए, उस महिला ने लगभग 16 साल तक घरेलू हिंसा, शराब, मारपीट और अपमान झेला। वह एक ऐसे घर में थी, जहां हर रात डर था, हर सुबह समझौता था और हर दिन उम्मीद थोड़ी-थोड़ी मरती थी। बेशक कानून अपने हाथ में लेना कभी इसका समाधान नहीं होता। एक इंसान की जान लेना अपराध है और रहेगा, मगर यह भी सच है कि कोई भी बड़ा अपराध अचानक पैदा नहीं होता। उसकी जड़ें अक्सर वर्षों के दर्द, हिंसा, उपेक्षा, झूठ, नशे और टूटते रिश्तों की मिट्टी में धीरे-धीरे फैलती रहती हैं।

हम अक्सर सिर्फ आखिरी घटना देखते हैं- शव, पुलिस, गिरफ्तारी और अदालत। उससे पहले के हजारों दिन, हजारों आंसू, हजारों चीखें, कोई नहीं देखता। समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक कोई रिश्ता खून में नहीं बदल जाता, तब तक घर के अंदर होने वाली हिंसा को लोग पति-पत्नी का मामला मानते हैं। नहीं, कुछ भी 'ऐसे ही' नहीं होता। शराब सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पीती, वह पूरे परिवार का भविष्य पी जाती है। घरेलू हिंसा सिर्फ शरीर पर निशान नहीं छोड़ती, वह इंसान के दिमाग, धैर्य और सोच को भी घायल कर देती है।

जो हाथ पत्नी की रक्षा और सम्मान के लिए बने हैं, यदि वही हाथ उस पर अत्याचार करेंगे, तो एक दिन उस घर का सुख, विश्वास और अस्तित्व सब कुछ समाप्त हो जाएगा।

इस घटना से सबसे बड़ा सबक यही है- हिंसा को शुरुआत में ही रोकिए। नशे को सामान्य मत मानिए। पीड़ित की आवाज को 'घर का मामला' कहकर मत दबाइए, क्योंकि जब समाज समय पर नहीं सुनता, तब कई बार अदालत तक पहुंचने से पहले एक त्रासदी जन्म ले चुकी होती है। अपराध की सजा अदालत देती है, लेकिन अपराध की जड़ें समाज मिलकर तैयार करता है। ऐसे में, समाज, परिवार और प्रशासन- तीनों का दायित्व है कि घरेलू हिंसा, शराब की लत और पारिवारिक कलह को 'घर का निजी मामला' कहकर अनदेखा न करें। समय रहते संवाद, परामर्श और कानूनी हस्तक्षेप अनेक परिवारों को टूटने और ऐसी दुखद घटनाओं से बचा सकते हैं।

कविता गुप्ता, टिप्पणीकार

न्यायमूर्तियों के मामलों में मिले न्याय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ताजा एलान से न्यायिक क्षेत्र में नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ हुई जांच की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आमतौर पर न्यायमूर्तियों के इस्तीफे के साथ ही उनके खिलाफ लगे आरोपों का पटाक्षेप मान लिया जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के एलान से साफ है कि आगामी सत्र में कुछ ऐसा होने वाला है, जो पहले कभी नहीं हुआ। आगे न्याय की राह आसान नहीं, असाधारण है। पेश है उत्कर्ष आनंद की रिपोर्ट...

यह घटना लोग भूले नहीं हैं, जब दिल्ली में एक न्यायमूर्ति के घर करोड़ों रुपये बरामद हुए थे। काफी सारे नोट जल हुए थे। आग बुझाने की कोशिश में ही बेहिसाब नकदी का खुलासा हुआ था। मार्च 2025 में सामने आई इस शिकायत का क्या हुआ?

भारी जन दबाव के बाद पिछले वर्ष 9 अप्रैल को जस्टिस यशवंत वर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने न्यायिक पद से जुड़े आधिकारिक सुख-सुविधाओं और विशेषाधिकारों को त्याग दिया। न्यायिक वेतन लेना बंद कर दिया। हालांकि, उन्होंने बार काउंसिल में पुनः पंजीकरण करा लिया, जिससे उन्हें कानूनी रूप से निजी वकालत फिर शुरू करने की अनुमति मिल गई। उनकी पेंशन और अन्य अंतिम लाभ अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अब बड़ा सवाल है, यदि न्यायमूर्ति वर्मा न्यायाधीश नहीं हैं, तो क्या संसद महाभियोग के माध्यम से उन्हें पद से हटाने पर विचार कर सकती है?

पेश होगी जांच रिपोर्ट

ध्यान रहे, 4 जुलाई, शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की है कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की जाएगी। यहां कई सवाल खड़े होते हैं और सांविधानिक विरोधाभास भी पैदा होता है। संसद में जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या होगा? कार्रवाई के लिए क्या विकल्प हैं? क्या अब भी आरोपी जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है?

वैसे, न्यायाधीश ने बार-बार कहा है कि यह उनका धन नहीं है और उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के आंतरिक जांच पैनल ने उनकी सफाई को असंतोषजनक पाया था और उसके बाद ही तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कार्यपालिका को कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बाद ही संसद में निष्कासन की कार्यवाही शुरू हुई और जुलाई 2025 में दोनों सदनों में नोटिस पेश किए गए। लोकसभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक जांच समिति का गठन किया, जबकि राज्यसभा ने प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए समानांतर प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह विडंबना है कि इस मामले में दोनों सदनों के विचार में एकरूपता नहीं दिखी।

सांविधानिक विरोधाभास

लोकसभा अध्यक्ष की ताजा घोषणा ने एक ऐसे कानूनी विवाद को फिर से जन्म दिया है, जो केवल एक न्यायाधीश के भाग्य से कहीं अधिक व्यापक है। न्यायाधीशों के खिलाफ पहले की महाभियोग कार्यवाही के विपरीत, क्या संसद अब एक अनछुए सांविधानिक क्षेत्र की ओर बढ़ रही है? एक तरफ, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का 1978 का फैसला है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के इस्तीफे को एकतरफा सांविधानिक कार्य माना गया है, जिसके लिए किसी प्राधिकरण की स्वीकृति जरूरी नहीं है और यह न्यायाधीश द्वारा स्वयं चुनी गई तिथि से प्रभावी हो जाता है। दूसरी ओर, सरकार का संसदीय प्रक्रिया को जारी रखने का स्पष्ट निर्णय है, जो अन्य बातों के अलावा इस तथ्य पर आधारित है कि न्यायाधीश के इस्तीफे पर कार्यपालिका द्वारा अभी तक औपचारिक कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप है, जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी भी दिखाई देता है। प्रशासन दुविधा में है, उनका वेतन बंद हो गया है। उनकी पेंशन शुरू नहीं हुई है। क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेगी? क्या संसद इस मामले की दुविधाओं को दूर करेगी?

न्यायाधीश ने पद छोड़ दिया प्रतीत होता है, फिर भी संसद स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार करने की तैयारी कर रही है कि जिस पद को उन्होंने खाली किया है, उसे असाधारण निष्कासन प्रक्रिया के माध्यम से उनसे छीन लिया जाए या नहीं।

संविधान पीठ ने क्या कहा था?

सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) मामले में विरोधाभास को स्पष्ट किया था। पीठ ने फैसला सुनाया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एकतरफा इस्तीफा देने का सांविधानिक अधिकार प्राप्त है और इसमें इस्तीफे से संबंधित सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। न्यायाधीश कार्यपालिका का कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सांविधानिक पदाधिकारी होता है।

यदि कोई न्यायाधीश तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता है, तो न्यायाधीश द्वारा चुनी गई तिथि से सांविधानिक संबंध समाप्त हो जाता है। यहां राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी जरूरी नहीं है। इस फैसले में सांविधानिक पद को सामान्य सार्वजनिक रोजगार से अलग बताया गया। इस पर जोर दिया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सांविधानिक कार्य करते हैं और पारंपरिक अर्थों में नियोक्ता नहीं हैं। अब संविधान के इस सूत्र का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि वर्मा के त्यागपत्र में स्पष्ट कहा गया है कि त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से दिया जा रहा है।

सीधा सवाल - टेढ़ा उत्तर

यहां उठने वाला बड़ा सांविधानिक प्रश्न बहुत सीधा है, पर इसका उत्तर शायद उतना सीधा नहीं है। क्या किसी के पदत्याग की प्रक्रिया इस्तीफे के बाद भी जारी रह सकती है? यदि अनुच्छेद 217 के तहत इस्तीफा तत्काल प्रभावी हो जाता है, तो क्या अनुच्छेद 124(4), 217(1)(ख) व न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत स्थापित तंत्र, जो केवल किसी मौजूदा न्यायाधीश को हटाने का निर्णय लेने के लिए बनाया गया है, न्यायाधीश के पद छोड़ने के बाद भी काम करता रह सकता है?

क्या संसद को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर किसी न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश करनी चाहिए। इसमें पदत्याग से कम किसी अनुशासनात्मक दंड का प्रावधान नहीं है, न ही इसमें सांविधानिक पद के समाप्त होने के बाद कार्यवाही जारी रखने का स्पष्ट प्रावधान है। कई न्यायिक मिसालों के मुताबिक, एक बार इस्तीफा प्रभावी हो जाने पर, पदत्याग का विषय ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि संसद किसी व्यक्ति को उस पद से नहीं हटा सकती, जिस पर वह आसीन नहीं है।

इससे पहले क्या हुआ था?

पहले के उदाहरण अलग ही कहानी बयान करते हैं। जब 2011 में महाभियोग की कार्यवाही लंबित रहते हुए न्यायमूर्ति पी डी दिनाकरन ने इस्तीफा दिया, तब न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत गठित जांच समिति को भंग कर दिया गया और अंततः संसद के समक्ष कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसी प्रकार, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से उनके इस्तीफे के बाद प्रभावी रूप से समाप्त हो गई, भले ही राज्यसभा ने उनके निष्कासन की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था। बहरहाल, न्यायमूर्ति वर्मा का मामला कुछ अलग हो गया है। पहले के मामलों के विपरीत, जांच समिति ने वर्मा के इस्तीफे के बाद भी अपना काम जारी रखा और मई महीने में लोकसभा अध्यक्ष को एक सीलबंद रिपोर्ट भी सौंपी है।

अब सवाल है, संसद उस रिपोर्ट को केवल संस्थागत अभिलेख के हिस्से के रूप में पेश करेगी या निष्कासन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगी? इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष क्या परंपरा से हटकर कोई अलग लकीर खींचने वाले हैं?

कुछ अधिकारी इसे कानून का संदिग्ध क्षेत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायमूर्ति के इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में, यदि न्यायमूर्ति वर्मा अपने इस्तीफे के बावजूद सांविधानिक पद पर बने रहते हैं, तो एक अधिवक्ता के रूप में उनके पंजीकरण की बहाली को कैसे देखना चाहिए? वकील के रूप में यह बहाली उन्हें लागू नियामक ढांचे के तहत किसी भी समय निजी वकालत फिर से शुरू करने में सक्षम बना देती है। लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा से यह सवाल पैदा हो गया है कि अब वर्मा को एक न्यायाधीश माना जाए या एक सामान्य पंजीकृत वकील?

अब नया क्या होगा?

कुल मिलाकर, लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा केवल एक जांच को पुनर्जीवित करने से कहीं अधिक है। इसने स्वयं इस्तीफे के सांविधानिक अर्थ, संसदीय निष्कासन शक्तियों की सीमाओं और उससे जुड़े अनेक अनसुलझे सवालों को चर्चा में आने का मौका दिया है। यदि संसद केवल रिपोर्ट पेश करने से आगे बढ़कर न्यायमूर्ति के इस्तीफे के बावजूद निष्कासन की कार्यवाही का निर्णय लेती है, तो भारत ऐसी पहली आधिकारिक न्यायिक जांच व कार्यवाही का गवाह बनेगा। यह स्थापित हो जाएगा कि किसी न्यायमूर्ति का इस्तीफा ही पर्याप्त नहीं है, उसके इस्तीफे के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि इससे न्यायपालिका और विधायिका के बीच नई खींचतान की शुरुआत हो सकती है।

अनेक सवालों के जवाबों का इंतजार है। क्या न्यायमूर्ति के इस्तीफे को पर्याप्त मान लिया जाए? क्या शिकायतों को भुला दिया जाए? क्या हम न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय से देश में एक असामान्य सांविधानिक स्थिति बन गई है।

Hindustan Times

> **लोकसभा अध्यक्ष की ताजा घोषणा केवल एक जांच को पुनर्जीवित करने से कहीं अधिक है। उनके अभूतपूर्व फैसले ने न्यायपालिका से जुड़े अनेक अनसुलझे सवालों को चर्चा में आने का मौका दे दिया है। यदि भारतीय संसद एक न्यायमूर्ति के खिलाफ केवल जांच रिपोर्ट पेश करने से आगे बढ़कर इस्तीफे के बावजूद निष्कासन की कार्यवाही का निर्णय लेती है, तो भारत ऐसी पहली न्यायिक जांच व कार्यवाही का गवाह बनेगा।**

विशेषाधिकार प्राप्त न्यायपालिका को लेकर बड़ी दुविधाएं : शिकायत और सुनवाई की कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल

जवाब मांगते बड़े सवाल

1. यदि न्यायमूर्ति वर्मा अब न्यायाधीश नहीं हैं, तो क्या भारतीय संसद अभी भी उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है?
2. यदि यशवंत वर्मा अभी भी न्यायाधीश हैं, तो क्या उनके इस्तीफे के कानूनी परिणाम पहले ही लागू हो चुके हैं?
3. क्या यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानूनी रूप से कब पद छोड़ेंगे?
4. क्या एक न्यायाधीश के इस्तीफे से उसके खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग की कार्यवाही समाप्त हो जाती है?

इस्तीफे के बाद क्या हुआ?

- यशवंत वर्मा अब किसी न्यायिक सेवा में नहीं हैं और वह किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
- वर्मा ने किसी न्यायाधीश को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं और साधन वापस लौटा दिए हैं।
- उन्हें अब वेतन-भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं; पेंशन और अन्य अंतिम लाभ को अभी जारी नहीं किया गया है।
- बार काउंसिल में वकील के रूप में उनके पंजीकरण को बहाल किया गया है।
- बार नियमों के तहत यशवंत वर्मा निजी प्रैक्टिस शुरू करने के पात्र हो गए हैं।

1978 में आया संविधान पीठ का फैसला : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा एकतरफा सांविधानिक कार्य है। इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इस्तीफा तुरंत प्रभावी हो जाता है।

न्यायिक पहेली सुलझानी पड़ेगी

- यदि वर्मा का इस्तीफा प्रभावी हो गया है, तो क्या उन्हें हटाने की कार्यवाही जारी रह सकती है?
- यदि इस्तीफा प्रभावी नहीं हुआ है, तो न्यायिक पद से संबंधित प्रक्रियाएं पहले ही क्यों बंद हो गई हैं?
- क्या संसद किसी ऐसे व्यक्ति को पद से हटा सकती है, जिसने पहले ही इस्तीफा दे दिया हो?

मिलते-जुलते दो चर्चित मामले

न्यायमूर्ति पी डी दिनाकरन (2011) : महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान ही दिनाकरन ने इस्तीफा दे दिया और उनके लिए गठित जांच समिति भंग कर दी गई।

न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (2011) : राज्यसभा ने हटाने का प्रस्ताव पारित किया; लोकसभा में मतदान से पहले सेन ने इस्तीफा दिया और कार्यवाही समाप्त हो गई।

77 प्रतिशत भारतीयों ने साल 2007 में हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण में अपनी न्यायपालिका को भ्रष्ट माना था।

09 न्यायमूर्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की कोशिश हुई है व अब तक केवल एक को अवमानना में 6 माह की सजा सुनाई गई।

न्यायपालिका को लेकर भारत में कितनी शिकायतें?

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2016	729
2017	682
2018	717
2019	1037
2020	518
2021	686
2022	1012
2023	977
2024	1170
2025	1102

(फरवरी 2026 में सरकार ने लोकसभा में बताया)

भ्रष्ट जजों से कैसा सलूक?

अमेरिका : बड़े जजों के मामले में भारत जैसी महाभियोग प्रक्रिया है। भ्रष्ट जज को हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए। निचले स्तर पर हर राज्य में न्यायिक आचरण आयोग है। कुछ राज्यों में लोग मतदान से करते हैं फैसला।

इंग्लैंड : बड़े न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद और देश के राजा की मंजूरी जरूरी है। न्यायिक आचरण जांच कार्यालय है। पुलिस जांच कर सकती है और जजों पर किसी अन्य नागरिक की तरह ही मुकदमा चलाया जा सकता है।

चीन : कड़ाई से जजों की केंद्रीकृत भ्रष्टाचार-विरोधी निगरानी होती है। जांच के लिए सशक्त पर्यवेक्षण आयोग है। फैसले में जजों की आजीवन जवाबदेही होती है। जजों को आजीवन कारावास हो सकता है और संपत्ति जब्त हो सकती है।

फ्रांस : शिकायत, जांच और सुनवाई की पुख्ता व्यवस्था है। शिकायत करना आसान है और कार्रवाई भी होती है। फ्रांसीसी दंड संहिता के तहत, न्यायिक भ्रष्टाचार बहुत गंभीर अपराध है, 10 वर्ष तक की कैद और भारी जुर्माना हो सकता है।

सिंगापुर : यहां आदर्श व्यवस्था है। जजों से जुड़ी शिकायतों के लिए तय टेलीफोन नंबर और मेलबॉक्स है। भ्रष्टाचार निवारण जांच ब्यूरो (सीपीआईबी) जैसी स्वतंत्र एजेंसी शिकायतों की जांच करती है। कड़ी कार्रवाई होती है, जिससे वहां न्यायिक पारदर्शिता बढ़ी है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

वृष : मन प्रसन्न रहेगा। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। बौद्धिक कार्यों में सम्मान में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि भी होगी। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है।

मिथुन : मन परेशान हो सकता है। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। सेहत का भी ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। आय में कमी आ सकती है। पिता का साथ मिलेगा।

कर्क : मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, परंतु किसी दूसरे स्थान पर भी जाना हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी।

सिंह : कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। लाभ में भी वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। कठिनाई आ सकती है। सेहत के प्रति सचेत रहें।

कन्या : मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में भी वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

तुला : किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संयत रहें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

धनु : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं।

मकर : लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय में वृद्धि भी होगी। कारोबार में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। किसी रुके धन की प्राप्ति हो सकती है।

कुंभ : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

मीन : मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ में वृद्धि होगी।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

08 जुलाई, बुधवार, **शक संवत्**: 17, आषाढ़, (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग**: 24, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 22, मोहर्रम, 1448 **विक्रमी संवत्**: आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12.22 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, रेवती नक्षत्र सायं 04 बजे तक पश्चात अश्विनी नक्षत्र, अतिगण्ड योग दोपहर 12.38 मिनट तक पश्चात सुकर्मा योग, चन्द्रमा मीन राशि में सायं 04 बजे तक उपरांत मेष राशि।

सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। पंचक समाप्त सायं 04 बजे।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

यहां जानें कि वृक्षों से वास्तु कैसे प्रभावित होता है:

- दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में तुलसी लगाने से संतान दुखी रहती है।
- बरगद का वृक्ष यदि घर की पश्चिम दिशा में हो, तो घर में मांगलिक कार्यों में विलंब एवं बाधा होती है।
- बबूल का पेड़ जीवन में सुख-समृद्धि का नाश करता है। घर में ताड़ का वृक्ष होना संतान के लिए कष्टकारी होता है।
- बेर का पेड़ धन के लिए हानिकारक होता है। पपीते का पेड़ धन संबंधित समस्याएं देता है। सूखे पेड़ की छाया घर पर पड़े, तो इसको शुभ नहीं माना जाता।

वर्ग पहेली : 8383

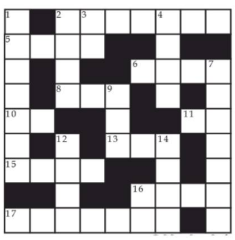

बाएं से दाएं
2. बाद में अप्रयुक्त लौटाने के उद्देश्य से वस्तु या धन रखना (4,3)
5. नरम और रोयेंदार रेशमी कपड़ा; मुलायम परत वाला; वैल्वेट (4)
6. संगी; साथी; साथ चलने वाले; एक ही राह के व्यक्ति; सहकर्मी; सहयात्री (4)
8. तेज; वेगपूर्वक चलता हुआ; शीघ्रतापूर्वक (3)
10. ऊंचाई; लंबाई; डील-डौल; हैसियत (2)
11. बगल; कमरा; कोठरी (2)
13. अंबर; तूला; बदर; बिनौले सहित रूई; रूई का पौधा (3)
15. अयोग्य; निकम्मा; मूरख (4)
16. पैना; दृढ़; मजबूत; शक्तिशाली; टिकाऊ (4)
17. इस प्रकार शब्द कहना कि औरों को सुनाई दे; निश्चित और शुद्ध ढंग से शब्द कहना या बोलना; पढ़ कर सुनाना; बोल कर सुनाना (4,3)

ऊपर से नीचे
1. करार करना; संधि करना; सहमत होना; मेल मिलाप करना (4,3)
2. अमर होने का भाव; अजरता; अमरता; देवत्व (4)
3. सामान; असबाब; बढ़िया वस्तु; धन संपत्ति क्षेत्र (2)
4. कृपा; दया (4)
7. अपने हस्तलेख में अपना नाम लिखना (4,3)
9. अत्यल्प; अल्प; कम; जरा; थोड़ा (3)
12. आय पर लगने वाला कर (4)
14. डरना; भयभीत होना; सिमटना (4)
16. स्थान; दरवाजा; द्वार; भाव (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8382

1 म	■	2 घ	र	3 का	रा	स्ता	4 ले	ना
द	■	ट	■	या	■	■	न	■
5 द	र्द	ना	क	■	6 ब	लि	दा	न
दे	■	स्थ	■	7 का	■	■	र	■
ना	■	8 ल	ज्जा	ज	न	9 क	■	10 चं
■	11 मा	■	■	ल	■	ह	■	क
12 भ	या	न	क	■	13 ग	र	ज	ना
■	मो	■	■	14 भू	■	ढा	■	चू
15 क	ह	क	हा	ल	गा	ना	■	र

सुडोकू : 8337

*मध्यम

				3			5	4
		4	2					
	3		4	6				
5					3		8	7
	4						6	
8	1		9					3
				5	7		3	
					9	4		
1	8			2				

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8336

4	6	7	8	5	3	1	9	2
5	1	9	2	6	7	4	3	8
3	8	2	9	1	4	7	5	6
1	4	6	3	9	2	5	8	7
2	9	5	1	7	8	3	6	4
8	7	3	6	4	5	9	2	1
6	5	8	7	3	1	2	4	9
7	2	4	5	8	9	6	1	3
9	3	1	4	2	6	8	7	5

भारतीय शहरों की पोल खोल देता है मानसून

टॉप गियर में ऑटो सेक्टर, जून में गाड़ियों की बिक्री का नया रिकॉर्ड

जून महीने में गाड़ियों की रिटेल बिक्री का नया रिकॉर्ड बताता है कि अर्थव्यवस्था पर मौसम और ऊर्जा संकट के असर के बावजूद देश में उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत बना हुआ है. फाडा, यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, जून में वाहनों की खुदरा बिक्री 25 लाख वाहनों तक पहुंच गयी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है और जून महीने की अब तक की सबसे अधिक बिक्री है. जून में चार लाख से ज्यादा लोगों ने देश में कार खरीदी और 18 लाख से अधिक लोगों ने दोपहिया वाहन. लोगों की आमदनी, रोजगार, बढ़ती ग्रामीण मांग और आसान कर्ज इसके कारण हैं. इसके अतिरिक्त, कार और बाइक अब रोजगार, शिक्षा व रोजमर्रा के लिए आवाजाही के जरूरी साधन हैं. जून में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी 17 प्रतिशत बढ़ गयी, जो पिछले तीन महीने का उच्चतम स्तर रहा. यात्री वाहनों की बिक्री में आयी इस तेजी से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ रहा है. दरअसल, जीएसटी की दरों में किये गये बदलाव का लाभ भी बिक्री में दिखाई दे रहा है. ऐसे ही, पश्चिम एशिया का संकट कुछ हद तक सुलझने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक माहौल और सुदूर इलाके में डिलीवरी सेवाओं में वृद्धि से भी वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र को फायदा मिला है. ई-कॉमर्स क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन और बढ़ती बुनियादी ढांचा गतिविधियों ने भी बिक्री को बढ़ावा दिया. जहां तक आगे की संभावनाओं की बात है, तो यात्री कारों के मोर्चे पर इवी और सीएनजी मॉडल की मजबूत बुकिंग होने तथा नये मॉडल लॉन्च होने से आगे भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है. सच्चाई यह है कि भारत ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है. ऐसे ही, वाणिज्यिक वाहन के क्षेत्र में माल ढुलाई और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों की वजह से बाजार स्थिर रहने का अनुमान है. सामान्य मॉनसून, गांवों में बढ़ते धन प्रवाह और इवी व फ्यूल एफिशिएंट मॉडल की बढ़ती मांग से दोपहिया वाहनों की भी बिक्री बढ़ सकती है. हालांकि, जिन इलाकों में बारिश कम होगी और जुलाई में कंपनियों की कीमत बढ़ोतरी लागू होगी, वहां कुछ ग्राहक खरीदारी टाल सकते हैं. इसके बावजूद ऑटो क्षेत्र की स्थिति अर्थव्यवस्था की आशावादी तस्वीर तो पेश करती ही है.

यात्री वाहनों की बिक्री में आयी इस तेजी से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ रहा है. जीएसटी की दरों में किये गये बदलाव का लाभ भी बिक्री में दिखाई दे रहा है.

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.in

मॉनसून का जो मौसम नवीनीकरण का होना चाहिए, वह तबाही व अव्यवस्था लेकर आता है. सड़कें गंदी नदियों में बदल जाती हैं, नालियां सड़कों पर सीवेज उगलती हैं, बिजली के तार मौत के जाल की तरह लटकते हैं. वर्ष 2005 में मीठी नदी और नालों के गाद से भर जाने के कारण हुए जल जमाव में मुंबई की सड़कों ने 1,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी. वर्ष 2015 में चेन्नई का तीन-चौथाई हिस्सा पानी में डूब जाने के कारण पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे. दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कई दूसरे शहर हर साल इसी भयावह स्थिति को दोहराते हैं.

यह अब ढर्रा ही बन चुका है कि मॉनसून के देश के कुछ हिस्सों में पहुंचते ही नागरिक एक और भयावह स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी को दुख, खतरे और अपमान के दलदल में बदल देती है. मॉनसून का जो मौसम नवीनीकरण का होना चाहिए, वह तबाही व अव्यवस्था लेकर आता है. सड़कें गंदी नदियों में बदल जाती हैं, नालियां सड़कों पर सीवेज उगलती हैं, बिजली के तार मौत के जाल की तरह लटकते हैं, फुटपाथ खोमचे व मलबे के नीचे गायब हो जाते हैं, कचरे के ढेर पहाड़ बन जाते हैं और कंकरीट की अवैध इमारतें रातोंरात उग आती हैं. यह केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं है. यह भ्रष्टाचार, उदासीनता और उन लोगों की आपराधिक लापरवाही से पैदा हुई एक मानव निर्मित आपदा है, जिन्हें सेवा की शपथ दी गयी थी. यह हर साल मौतों का उत्सव बन गया है, जो हर स्तर की विफलता से पैदा होता है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे देश को एक योजनाबद्ध ठहराव की स्थिति में धकेल दिया गया है.

शहरी भारत 250 से अधिक नगर निगमों, हजारों नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा संचालित होता है. बाबुओं, ठेकेदारों और नेताओं के सड़े गठजोड़ से भरी ये संस्थाएं नागरिक जीवन के व्यवस्थित पतन की जिम्मेदार रही हैं. हर मॉनसून उनकी विफलता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है. मॉनसून के कारण आने वाली बाढ़ तो हर साल की परंपरा ही बन चुकी है. वर्ष 2005 में मीठी नदी और नालों के गाद से भर जाने के कारण हुए जल जमाव में मुंबई की सड़कों ने 1,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी. वर्ष 2015 में चेन्नई का तीन-चौथाई हिस्सा पानी में डूब गया था, जिस कारण पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गये थे, क्योंकि जलमार्ग बंद हो गये थे और आर्द्रभूमि गायब हो गयी थी. दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कई दूसरे शहर हर साल इसी भयावह स्थिति को दोहराते हैं-जलभराव से लोग करंट का शिकार होते हैं, यातायात दिनों तक ठप रहता है और घर गंदगी भरे गड्ढों में बदल जाते हैं. मुंबई, चेन्नई और दिल्ली के बड़े नाले पूरी तरह गाद से भरे हैं, उनकी सफाई या तो खराब तरीके से हुई है या गाद छोड़ दी गयी है. विडंबना यह भी है कि नयी बनने वालीं तथाकथित विश्व स्तरीय सड़कें कुछ ही महीनों में टूट जाती हैं. घटिया सामग्री, कमीशन और रख-रखाव की कमी इसके कारण हैं. छोटे शहरों में ट्रैफिक जाम रोज का संकट बन गया है. सड़क की खराब डिजाइन, संकरी गलियां, सिग्नल की कमी और अव्यवस्थित चौराहे, साथ ही भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिस मिलकर जाम पैदा करते हैं, जिससे समय और ईंधन की बर्बादी होती है.

एंबुलेंस रेंगती रहती हैं और मरीज मर जाते हैं. विफलता की बदबू हर जगह फैली है. कचरे के ढेर सड़कों और फुटपाथों को जाम कर देते हैं, क्योंकि नगर निकायों के पास कचरा प्रबंधन का कोई ठोस समाधान नहीं है, जबकि रियल एस्टेट का विस्तार लगातार निर्माण मलबा और घरेलू कचरा बढ़ा रहा है. जिस स्वच्छ भारत मिशन को कभी परिवर्तनकारी बताया गया था, वह अब बुरी तरह विफल हो चुका है. इसके सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर और स्वयंसेवक गायब हो गये हैं. बड़े शहरों के लैंडफिल साफ नहीं हुए, कचरे का अलगाव असंगत है, और प्रसंस्करण के दावे केवल भरे हुए कचरा स्थलों और जहरीले रिसाव को छिपाते हैं. बड़े शहर स्वच्छता सर्वेक्षणों में लगातार खराब प्रदर्शन करते हैं. विदेशी पर्यटक भारत आने से बचते हैं या अपनी यात्रा जल्दी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह गंदगी का सामना करना पड़ता है. उस स्मार्ट सिटीज मिशन को लगभग भुला दिया गया है, जिसका उद्देश्य 100 शहरों को आधुनिक बनाना था. वर्ष 2025 की शुरुआत तक 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद केवल कुछ शहर ही वास्तविक परिवर्तन हासिल कर पाये.

एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़े भारतीय शहरों में केवल नौ से 20 फीसदी फुटपाथ ही मानकों पर खरे उतरते हैं. अधिकांश फुटपाथ अवैध कब्जों से भरे हैं. अवैध निर्माण शहरों को भीतर से खत्म कर रहा है. कई शहरों में हर साल स्वीकृत इमारतों से अधिक अवैध इमारतें बनती हैं. ये सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती हैं और इनमें आपातकालीन निकास नहीं होते. पिछले साल केवल दिल्ली में 4,766 अवैध निर्माण दर्ज किये गये और हजारों ध्वस्तीकरण आदेश जारी किये गये. देशभर में घटिया या अवैध इमारतों के कारण हजारों मौतें हुई हैं. वर्ष 2024 में आग की 5,971 घटनाओं में 5,888 लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन लगभग 16 मौतें. हर दुर्घटना के बाद कुछ दिनों तक कार्रवाई होती है और फिर सब शांत हो जाता है. बाबू, ठेकेदार और नेताओं का गठजोड़ दोषियों को बचा लेता है. इस पूरे तंत्र के केंद्र में भारतीय नौकरशाही है, जिसे लगभग पूरी सुरक्षा प्राप्त है. ये अधिकारी एयरकंडीशंड दफ्तरों में बैठे रहते हैं और पदोन्नति व लाभ पाते रहते हैं, जबकि शहर बदहाल होते जाते हैं. ये अवैध निर्माणों को मंजूरी देते हैं, नालों की दशकों से सफाई नहीं करते, खराब सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं और कचरा व अतिक्रमण की समस्या को नजरअंदाज करते हैं. जब नागरिक गंदगी में डूबते हैं, करंट से मरते हैं या आग में अपने प्रियजनों को खोते हैं, तब भी ये अधिकारी अपनी नौकरी में आगे बढ़ते रहते हैं. सरकारी रिपोर्टों ने भी शहरों की खराब स्थिति उजागर की है. कुल 4,589 शहरी निकायों के मूल्यांकन में 3,642 को कचरा मुक्त शहर मानक में शून्य अंक मिले. ये संस्थाएं उसी गिरावट पर फलती-फूलती हैं, जो वे स्वयं पैदा करती हैं. लेकिन आम नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं.

लोग अपने घर साफ रखते हैं, लेकिन सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, अवैध निर्माण करते हैं और अतिक्रमण करते हैं. नागरिक खुद गंदगी और भ्रष्टाचार फैलाकर सिस्टम से जवाबदेही की मांग नहीं कर सकते. अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध, सख्त सजा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई आवश्यक है. केंद्र सरकार को सख्त नियम लागू करने चाहिए और प्रदर्शन के आधार पर फंड देना चाहिए. अधिकारियों और नागरिक, दोनों को जवाबदेह बनाना होगा. बिना कड़े कदमों के भारत दुनिया के सबसे गंदे देशों में गिना जायेगा. भारतीय शहर सचमुच और प्रतीकात्मक रूप से डूब रहे हैं. मॉनसून फिर आयेगा. सवाल यह है कि क्या भारत अगली त्रासदी से पहले जागेगा. अब बहानों का समय समाप्त हो चुका है और सख्त जवाबदेही का समय आ चुका है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बदल रही स्वास्थ्य व्यवस्था

डॉ मयंक भारद्वाज
(29 Years)
अतिथि अध्यापक
मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी
bharadwajmayank@yahoo.com

40 under 40

निःसंदेह, एआइ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज, सटीक और प्रभावी बनाकर चिकित्सा क्षेत्र में एक नये युग की शुरुआत कर रहा है. किंतु इसे चिकित्सकों के विकल्प के रूप में नहीं, उनके एक सशक्त सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए. स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य तकनीक और मानवीय विशेषज्ञता के संतुलित समन्वय में ही सुरक्षित है.

वर्ष की शुरुआत में नयी दिल्ली में आयोजित 'एआइ इंपैक्ट समिट' ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) की अभूतपूर्व संभावनाओं को रेखांकित किया. उस सम्मेलन में पुणे के एक हेल्थ-टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित एआइ सक्षम उपकरण विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जो सर्वाइकल कैंसर की सस्ती और सुलभ प्रारंभिक जांच को संभव बनाता है. वहीं, 'वाइसा एआइ' ने यह प्रदर्शित किया कि एआइ आधारित चैटबॉट भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकते हैं.

असल में, एआइ जटिल चिकित्सीय आंकड़ों का विश्लेषण कर चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाते हैं. एआइ प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआइ जैसी छवियों, प्रयोगशाला रिपोर्टों और जीनोमिक आंकड़ों का तीव्र एवं सटीक विश्लेषण कर सकती है. इससे रोगों की समय पर पहचान, उपचार योजना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है. भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था एआइ के व्यापक उपयोग के लिए अत्यंत अनुकूल है. यद्यपि, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:811 है, जो डब्ल्यूएचओ के 1:1000 के मानक से बेहतर है, फिर भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भारी क्षेत्रीय असमानता है. साथ ही, गैर-संक्रामक रोगों का बढ़ता बोझ, वृद्ध होती आबादी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार बढ़ती लागत देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं. ऐसे में तकनीक आधारित 'इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस' हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सक्षम और प्रभावी बना सकते हैं. अस्पतालों तक सीमित न रहकर एआइ अब रोग निगरानी, महामारी की पूर्व चेतावनी, टीकाकरण की योजना, संसाधनों के बेहतर आवंटन तथा आपातकालीन प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अधिक सशक्त बना रही है.

जब एआइ को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ा जाता है, तब इसके लाभ और व्यापक हो जाते हैं. भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, जबकि विशेषज्ञ चिकित्सक और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं. एआइ संचालित टेलीमेडिसिन दूरस्थ परामर्श, सटीक निदान व रोगियों की निरंतर निगरानी संभव बनाकर इस भौगोलिक दूरी को कम कर रही है. सरकार की विभिन्न पहलें भी, जैसे 'इ-संजीवनी' टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म', 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' आदि एक समेकित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रही हैं. एआइ की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रभाव स्तन कैंसर की जांच के क्षेत्र में देखने को मिलता है. भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है, किंतु पारंपरिक मैमोग्राफी की अधिक लागत, सीमित उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कम पहुंच के कारण प्रारंभिक जांच अब भी बड़ी चुनौती है. इन समस्याओं के समाधान के लिए बेंगलुरु स्थित हेल्थ-टेक स्टार्टअप 'निरामई' ने 'थर्मलाइटिक्स' नामक एआइ आधारित स्तन कैंसर जांच प्रणाली विकसित की है, जो शुरुआती अवस्था में ही शारीरिक असामान्यताओं की पहचान कर सकती है. यह तकनीक पूरी तरह गैर-आक्रामक (नॉन-इंसिव), विकिरण मुक्त और बिना किसी शारीरिक संपर्क के जांच करने वाली है. इसके पोर्टेबल स्वरूप के कारण इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मोबाइल स्वास्थ्य शिविरों और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से ले जाया जा सकता है.

हालांकि, एआइ की इस क्षमता के साथ कई नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं. एआइ प्रणाली संवेदनशील रोगी आंकड़ों पर निर्भर करती है, जिससे गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और अनधिकृत पहुंच जैसी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं. यदि एआइ मॉडल पक्षपातपूर्ण या अपूर्ण आंकड़ों पर प्रशिक्षित हों, तो वे गलत या भेदभावपूर्ण परिणाम दे सकते हैं. इसके अतिरिक्त, अधिकतर एआइ मॉडल की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया को समझना चिकित्सकों के लिए भी कठिन होता है. इससे एआइ आधारित चिकित्सा निर्णयों पर विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो सकता है. सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि एआइ कभी भी मानवीय संवेदनशीलता, नैतिक विवेक और उस चिकित्सीय अनुभव का स्थान नहीं ले सकता, जो रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मा है. भारत के अनेक अस्पतालों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी गुणवत्तापूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, इंटरनेट सुविधा और आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे का अभाव है. एआइ प्रणाली को लागू करने की उच्च लागत, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी तथा व्यापक कानूनी व नियामक ढांचे का न होना भी इसके विस्तार में बड़ी बाधाएं हैं. निःसंदेह, एआइ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज, सटीक और प्रभावी बनाकर चिकित्सा क्षेत्र में एक नये युग की शुरुआत कर रहा है. किंतु इसे चिकित्सकों के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि उनके एक सशक्त सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए. स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य तकनीक और मानवीय विशेषज्ञता के संतुलित समन्वय में ही सुरक्षित है. इसके लिए मजबूत डाटा संरक्षण कानून, पारदर्शी एल्गोरिदम, प्रभावी नियामक व्यवस्था और नैतिक शासन की सख्त जरूरत है. (ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

यूरोप को समझ में आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन आज की समस्या है

वर्षों से, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को झेल रहे हम जैसे देशों के लोग दुनिया को समझा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की घटना नहीं है. यह वर्तमान की पीड़ा है जो समय-समय पर हमारे घर को बहा ले जाती है, शहर में बाढ़ ला देती है, फसल नष्ट कर देती है, या हमारे समुद्र तट को बदल देती है. जंगल की आग, सूखा, बुनियादी ढांचे की कमी और गर्मी से होने वाली मौतें त्रासदी हैं, चाहे वे कहीं भी हों. जलवायु परिवर्तन इसलिए कम विनाशकारी नहीं हो जाता क्योंकि यह पटुआखाली के बजाय पेरिस तक पहुंच जाता है. वातावरण ने कभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की परवाह नहीं की है. पर विडंबना यह है कि जिन देशों ने सबसे पहले औद्योगीकरण, सबसे अधिक उत्सर्जन किया और जीवाश्म ईंधन के जरिये शताब्दियों की समृद्धि अर्जित की, वे अब उस बात को समझने लगे हैं, जिसे वैश्विक दक्षिण के कई देश दशकों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं. धनी देशों को समझना होगा कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने वाले देश ही इसकी सर्वाधिक कीमत चुका रहे हैं. यहीं पर यूरोप को पिघला रही भीषण गर्मी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है. यह उस भ्रम को तोड़ देती है कि जलवायु परिवर्तन किसी और की मानवीय समस्या है. सरकारें अब अचानक से गर्मी से निपटने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, मजदूरों की सुरक्षा, जंगल की आग से निपटने की तैयारी, अस्पतालों की क्षमता और पानी की सुरक्षा पर उसी तेजी से चर्चा कर रही हैं, जिस तेजी की मांग जलवायु कार्यकर्ता वर्षों से कर रहे थे. यहां असली परीक्षा यह नहीं है कि विकसित देश यह मानते हैं या नहीं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है. असली परीक्षा यह है कि क्या यह नयी सच्चाई अंततः उत्सर्जन में अधिक कटौती, लगातार और दीर्घावधि तक चलने वाले जलवायु वित्त तथा अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे देशों को असली मदद दिलाने में बदलती है या नहीं. ऐसा लगता है कि वह क्षण आ गया है. जलवायु संकट अंततः सभी के लिए समान रूप से विघ्नकारी बन गया है.

The Daily Star

-नौशीन नवल

बोधि वृक्ष

ज्ञान का प्रयोग

हम हर एक चीज के साथ स्वयं को पहचान देते हैं. यह पहचान प्रक्रिया यांत्रिक है. व्यक्ति एक कठोरता पैदा कर लेता है और जीवन की अन्य प्रभावित करने वाली वस्तुओं को देख पाने से चूक जाता है. क्यों कुछ लोग आलोचनाओं या असफलताओं का दर्द जीवनभर ढोते रहते हैं? कठोरता पहचान प्रक्रिया का हिस्सा है. आध्यात्मिक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है गैर-पहचान. आप परेशान हो जाते हैं कि आपके दृष्टिकोण को सम्मान नहीं मिला. यह दर्द पैदा करता है. घायल शरीर अस्तित्व बचाने के लिए एक काल्पनिक स्वयं रचने की चाल चलता है. मतभेदों के दर्द को लंबे समय तक ढोते रहना, यांत्रिक दिमाग का हिस्सा है. जब तक हम अपने यांत्रिक केंद्र को एक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित नहीं कर लेते, नकारात्मक आकार यूं ही जारी रहेंगे. यांत्रिकता के अधीन दिमाग में अपेक्षाकृत कम चेतना होती है. हम जो भी करें, उसमें जितनी 'मौजूदगी' का अहसास होगा, उतनी अधिक संभावनाएं और अवसर होंगे कि चेतना बढ़ाकर चुंबकीय केंद्र को जगा दे. एक बार चुंबकीय केंद्र हमारे अंदर खुल जाये, तो हम दर्द को सहने की मूर्खता को स्वयं ही समझ सकते हैं. लोग दुख भरा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वे काम ही यांत्रिकता से करते हैं. दो तरह के क्षेत्र हैं, 'ज्ञान' का क्षेत्र और 'अस्तित्व' का क्षेत्र.

अपने अस्तित्व को उन्नत करने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए. इससे जिंदगी परिपक्व हो जाती है. एक परिपक्व जीव के तौर पर जब आप उसी ज्ञान को देखेंगे, तो उसका गहरा अर्थ पायेंगे. जिंदगी और अस्तित्व में गहरे अर्थों का पालन करने से जिंदगी और भी परिपक्व हो जायेगी और इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ महान घटित हो सकता है. ज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा आप उस गधे के समान होंगे जो चंदन की लकड़ियां लिये बेखबर चलता जाता है. अपने शरीर के बारे में सचेत रहें. आप शांत हैं या तनावपूर्ण? अपनी भावनाओं के बारे में सचेत रहें. क्या आप यांत्रिक रूप से किसी से घृणा या प्रेम करते हैं? अपने विचारों को देखिए. अपने मस्तिष्क के बारे में अधिक सचेत रहें.

-स्वामी सुखबोधनंद

कुछ अलग

फ्री एसी सर्विसिंग के झमेले

राकेश सोहम्
व्यंग्यकार
sohamsahitya@gmail.com

जनकलाल ने नया एसी लिया. पूरे एक वर्ष के भरोसे वाला. वर्ष में दो सर्विसिंग फ्री. कुछ महीने बाद उन्होंने सेवा प्रदाता को फ्री सर्विसिंग के लिए टोल-फ्री नंबर घुमाया. बमुश्किल चौबीस घंटे में समस्या के निराकरण का आश्वासन मिला, परंतु सेवा प्रदाता का बंदा चौदह मिनट में ही हाजिर हो गया, 'जनकलाल जी, आपने फोन किया था?' जनकलाल आशंका से घिर गये. कहीं फर्जी कॉल तो नहीं लग गया? आजकल इंटरनेट और मोबाइल के बड़े लफड़े हैं. कस्टमर केयर के नंबरों पर कस्टमर के लुटेरे बैठते हैं.

जनकलाल अभी 'एक दो, तीन, चार, पांच, छह, सात...' के राग से उबरे भी नहीं थे कि बंदा आ धमका है! वह बोले, 'हां, मैंने ही टोल फ्री पर कॉल किया था!' सेवा प्रदाता लापरवाही से बोला, 'धुलाई लगेगी. आउटर यूनिट कहां है?' जनकलाल ने घर की बाहरी दीवार पर टंगे आउटर यूनिट की ओर अंगुली उठा दी. 'और एसी किस कमरे में है?' उसने पूछा. जनकलाल आशंकित थे. सो बोले, 'फोन पर तो बताया कि चौबीस घंटे में सेवाएं दी जायेंगी! आपका आइडी है?' सेवा प्रदाता हंसा, 'लाना भूल गया. आपके मोहल्ले में ही कंप्लेन अटेंड कर रहा था. इसलिए यहीं के यहीं आ गया.' 'ओ अच्छा!', जनकलाल आश्वस्त हुए. 'तो फिर शुरू करो सर्विसिंग.' सेवा प्रदाता बाहरी दीवार पर टंगे आउटर यूनिट को देखते हुए बोला, 'अरे! यह तो ऊपर है. सीढ़ी लगेगी चढ़ने के लिए. है क्या?' जनकलाल ने न में मुंडी हिलायी. 'फिर तो मुश्किल है', वह मुंह बनाते हुए बोला. जनकलाल थोड़ा आवेशित हुए, 'और क्या-क्या लगेगा बेटा?' वह बोला, 'पानी की सप्लाई, पानी की सटक. धोने के लिए पानी में अच्छा प्रेशर होना चाहिए. सटक भी लंबी हो, ताकि वहां ऊपर तक पहुंच जाये.' उसने नीचे से आउटर यूनिट की ऊंचाई तक अंगुली उठायी.

जनकलाल अंदरूनी आवेश में कसमसाये, 'ऐसा पता होता तो एसी के साथ ये सब भी खरीद लेते.' फिर जरा जोर से पूछा, 'बेटा! पाना-पिंचिस, स्क्रू-ड्राइवर वगैरह तो लाये होंगे, कि वह भी मुझे ही देना होगा?' सेवा प्रदाता दोनों हाथ झुलाते हुए हंसा, 'अरे अंकल! वो सब मेरे पास है.' जनकलाल भन्नाये, 'नहीं... खाली हाथ चले आये, इसलिए पूछा. वैसे जिनके यहां से आ रहे हो, उनके एसी में क्या प्रॉब्लम है?' वह तपाक से बोला, 'वही, उनके पास भी सीढ़ी नहीं है.' जनकलाल जानते हैं कि पानी की उपलब्धता के अलावा बाकी साधन सेवा प्रदाता के पास होने चाहिए. वे अपने एक और पुराने एसी की सर्विसिंग स्वयं के खर्चे पर प्राइवेट एजेंसी से करा चुके हैं. पर फ्री सेवाओं के नाम पर लूट मची है. जनकलाल क्रोध में घर के अंदर जाते हुए बोले, 'आज नहीं करानी फ्री सर्विसिंग.'

आपके पत्र

नगर प्रशासन ने दुरुस्त नहीं करायी सड़क

रामनगर नगर परिषद के वार्ड-4, रतनपूरवा मोहल्ले की गली अभी तक कच्ची है. सड़क न बनने से यहां भीषण जलजमाव रहता है और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है. समस्या के समाधान के लिए कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर डीएम के जनता दरबार तक गुहार लगायी गयी, लेकिन निर्माण कार्य अब तक ठंडे बस्ते में है. हद तो यह है कि कच्ची सड़क दुरुस्त करने के नाम पर नगर प्रशासन ने इसे कचरे से भर दिया, जिससे अब बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गयी है. प्रशासन की यह कार्यप्रणाली बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

लव राज, (रामनगर) प. चंपारण

मिसाइल युग में भारत की सुरक्षा चुनौतियां

चीन की बढ़ती मिसाइल क्षमता एशिया में सामरिक संतुलन के लिए चुनौती है. आधुनिक युद्ध अब लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों, हाइपरसोनिक तकनीक, एआइ और उपग्रह निगरानी पर निर्भर हैं. भारत ने अग्नि, ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइलों से क्षमता मजबूत की है, लेकिन केवल संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. भविष्य की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, मजबूत रक्षा प्रणाली, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष नेटवर्क जरूरी हैं. रक्षा में निजी भागीदारी, स्वदेशी विनिर्माण और अत्याधुनिक तकनीक में निवेश बढ़ाना होगा. भारत का उद्देश्य हथियारों की दौड़ नहीं, बल्कि विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाना है.

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

कल्पमेधा

बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है।

– रोबर्ट फ्रास्ट

पारदर्शिता का तकाजा

राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास में कथित गबन का मामला जब से सामने आया है, तभी से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के समांतर एक संपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी संभव न हो सके। विडंबना यह है कि इस मामले के खुलासे के बाद जहां न्यास के दायरे में जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, वहां शुरू से आरोपों की दिशा भ्रमित करने की कोशिश होती रही। अब सोमवार को न्यास की एक अहम बैठक के दौरान इसके महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए और अंतरिम व्यवस्था के तौर पर एक अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। निश्चित तौर पर यह कदम विवाद के बीच जिम्मेदारी और आरोपियों के प्रति नरमी बरतने को लेकर उठते गंभीर सवालों की तीव्रता को कम करने की एक कवायद है, लेकिन इस बीच जैसी असहज करने वाली स्थितियां पैदा हुईं, उसने आम लोगों के भरोसे को कमजोर ही किया है।

इस संबंध में अब तक सामने आए आरोप-प्रत्यारोपों के बाद स्थिति इतनी उलझ गई है कि जब तक विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक एक तरह की अस्पष्टता कायम रहेगी। विडंबना यह है कि न्यास के जिन लोगों पर इसके वित्त की निगरानी, उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसकी संपत्तियों की रक्षा करने का दायित्व था, या तो उनके लिए ये तकाजे गैरमहत्त्वपूर्ण थे या फिर वे ही कठघरे में खड़े दिखे। सवाल है कि आरोपों की अनदेखी करके क्या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा सकता है! इतने समय तक किसकी देखरेख या संरक्षण में चढ़ावे की चोरी करने वालों का धंधा बेरोक-टोक चलता रहा? क्या यह उन तमाम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, जिनकी आस्था की बुनियाद पर ही न्यास का समूचा कामकाज टिका हुआ है? लोगों के भरोसे को ताक पर रख कर पैसों का गबन करने की हरकत कैसे संभव हुई? अब यह देखने की बात होगी कि इस अनियमितता के वास्तविक आरोपियों को कानून के कठघरे में खड़ा करके सजा दिलाई जाती है या नहीं?

हालांकि न्यास के नए महासचिव का कहना है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से सिर्फ इस्तीफा इस मामले का हल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार कानून के दायरे में एक परिभाषित अपराध है, तो उसके लिए सजा भी निर्धारित है। जांच में जिन लोगों को वास्तव में जिम्मेदार पाया जाएगा, उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलाना इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी होनी चाहिए। यों अनियमितता का जैसा स्वरूप सामने आया है, उसके मद्देनजर अब देश भर के लोगों की नजर इस पर रहेगी कि मंदिर में चढ़ावे, खर्च और वित्तीय खातों की निगरानी सहित न्यास के सभी कामकाज के प्रबंधन और संचालन के लिए जो नई व्यवस्था बनाई जाएगी, उसमें संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन कमियों को दूर करने लिए क्या किया जाता है, जिसकी वजह से न्यास के कोष में इतनी व्यापक गड़बड़ी की गई। राम मंदिर का दर्शन और वहां दान करना करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। मगर इस समूचे मामले की वजह से आम लोगों के भीतर न्यास को लेकर एक तरह का अविश्वास पैदा हुआ है, उसकी छवि को चोट पहुंची है।

हिंसा का दायरा

मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय तनाव के बीच हिंसा फिर से अपने पांव पसारने लगी है। राज्य में शांति बहाली को लेकर सरकार के तमाम दावों के बावजूद उग्रवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता आग में घी का काम कर रही है। उखरुल जिले में सोमवार को उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो जवानों के शहीद हो जाने की घटना ने समूची सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सुरक्षाबलों के जवान ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करेंगे। सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों का विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौते के बाद भी अगर उग्रवादी संगठन हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो इसकी वजह पता लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या सिर्फ सुरक्षाबलों की अतिरिक्त तैनाती के दम पर राज्य में शांति बहाल हो पाएगी? जाहिर है कि इसके लिए समस्या की जड़ में जाकर समाधान के रास्ते तलाशने होंगे।

गौरतलब है कि मणिपुर में वर्ष 2023 में मेइती और कुकी-जो समूहों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में ढाई सौ से अधिक लोगों की जान गई है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद हालात में ठोस सुधार संभव नहीं हो सका। वहां सरकार के फिर से कमान संभालने के बाद हिंसक गतिविधियां नए सिरे से जोर पकड़ने लगी हैं। राज्य में आए दिन सामुदायिक झड़पों, उग्रवादियों के हमले और विरोध प्रदर्शन की खबरें आती रहती है। बीते रविवार शाम को भी कांगपोकपी जिले के थिंगखोंगजांग में एक गांव पर हथियारबंद समूह ने हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से राज्य में सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार की नीतियां सुरक्षा एवं शांति बहाली के मोर्चे पर कमजोर साबित क्यों हो रही हैं। किसी हिंसक वारदात के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और जातीय मतभेदों का स्थायी हल निकालने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता क्यों नजर नहीं आ रही है? निस्संदेह, जब तक स्थानीय लोगों को भरोसे में नहीं लिया जाएगा, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है।

परतों में पलती स्त्री के विरुद्ध हिंसा

हाल में हुई कई निर्मम घटनाएं भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। घरेलू हिंसा के प्रति सामाजिक सहजता इस अपराध को और बढ़ा रही है।

संगीता सहाय

अक्सर बड़े पदों पर आसीन, निजी व्यवसाय या अन्य कामों में व्यस्त महिलाओं से भी यह आशा की जाती है कि वे अपनी नौकरी के काम के साथ-साथ घर के कामों को भी शिद्दत के साथ निपटाएं। चाहे इसके लिए उन्हें अपने विकास से समझौता ही क्यों न करना पड़े। हमारे आसपास घर के कामों में पिसती, चूल्हा-चौकी के लिए 'दिन-रात एक करती' और ऐसा नहीं कर पाने पर तानों की बौछार झेलती, अपमानित होती और पिटती महिलाएं देखी जा सकती हैं। आश्चर्य यह है कि ज्यादातर महिलाएं इन चीजों को सहज भाव से लेती हैं। उनके अनुसार दोहरी, तिहरी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में ही स्त्री होने की सफलता है। सामाजिक मानक ऐसी स्त्रियों को ही अपने खांचे के अनुकूल मानता है।

आर्थिक रूप से सक्षम और मानसिक रूप से खुद को मजबूत दिखाती और घर के अंधेरे में उत्पीड़ित और अपमानित होती स्त्रियां सभी जगह हैं। परिवार बनाने और बचाने से लेकर उसकी शांति और सुव्यवस्था के नाम पर अपनी योग्यता तथा डिग्रियों को दफ्न करती, अपनी पसंद-नापसंद को दरकिनार करती स्त्रियां किसी न किसी रूप में प्रत्येक घर में हैं। पिता की खराब आर्थिक स्थिति और भाई की शिक्षा के लिए पढ़ाई से वंचित की जाती बेटियां भी आम हैं। उच्च शिक्षित लड़कियों की शादी होते ही परंपरागत बहू, पत्नी, सेविका बन जाने की कामना अधिसंख्य भारतीय घरों में इतनी बड़ी है कि ऐसा न कर पाने वाली महिलाओं को लांछित और प्रताड़ित तो किया ही जाता है, कई बार हत्या तक कर दी जाती है। हाल में घटी कई निर्मम घटनाएं भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करती हैं।

दरअसल, स्त्री कोई भी हो, पढ़ी-लिखी सुयोग्य, ओहदेदार, डाक्टर, इंजीनियर, माडल, कलाकार, सामान्य घरेलू या कोई अन्य, सभी से कमोबेश यही आशा की जाती है और उसका मूल्यांकन इसी रूप में किया जाता है कि वह वंशवृद्धि कर पाई या नहीं, पति और ससुराल वालों को कितना खुश कर पाई, घर की सजावट, दूसरों की खुशी के लिए किस हद तक समझौता करती है, साफ-सफाई, खाना बनाने आदि में कितनी माहिर है और सबसे बढ़कर यह कि कैसे वह एक आदर्श परंपरागत बहू बनकर खुद को, अपने काम और पसंद को दोयम बना देती है। समाज कहता है कि स्त्री होने के नाते उसकी पहली और अंतिम प्राथमिकता यही है। वास्तव में समाज तथा परिवार के वर्तमान स्वरूप में बने रहने का बीज स्त्री के इसी दोहन में छिपा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 18-49 आयु वर्ग की लगभग 32 फीसद विवाहित महिलाओं ने अपने जीवनकाल में कभी न कभी पति या ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शारीरिक, यौन तथा भावनात्मक हिंसा को झेला है। 15-49 साल की महिलाओं में 31.9 फीसद ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में शारीरिक हिंसा झेली है। ग्रामीण क्षेत्र में हर चौथी तथा शहरी क्षेत्रों में हर छठी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। स्वयं को अतिशय संस्कृतिनिष्ठ कहने वाले हमारे देश को दुनिया भर में अंतरंग साथी द्वारा की जाने वाली

शारीरिक और यौन हिंसा के उच्च प्रसार वाले देशों में गिना जाता है। गौरतलब है कि एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ दर्ज हुए मामले बताते हैं। एनएफएचएस बताता है कि घरेलू हिंसा के मामले में 86 फीसद महिलाओं ने कभी मदद मांगी ही नहीं। यानी असली हिंसा के मामले इन आंकड़ों से कई गुना ज्यादा

> 'जिसकी छत टपकती है, निर्माण की पहल भी उसे ही करनी होती है।' यहां तो एक पक्ष चाहता ही है कि पितृसत्ता की भ्रामक श्रेष्ठता वाली व्यवस्था सदैव बनी रहे, क्योंकि उसका सुख उसी में है। स्त्री को हर स्तर पर इस जाल को न सिर्फ समझना होगा, बल्कि उसे काटने के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। पहचान, शिक्षा, सम्मान, कमाई, समय, पसंद, नापसंद जो भी उसका है, उसे हक के साथ लेना होगा। पहली बार में ही हिंसा की कुचेष्टा पर अंतिम रूप से लगाम लगाना अनिवार्य है। घर का होना और उसका हंसता मुस्कुराता स्वरूप जरूरी है, पर यह सब उस घर की बेटी, बहू या अन्य स्त्री की खुशियों की कीमत पर अस्वीकार्य है। कानून भी यही कहता है।

हैं। ज्यादातर महिलाएं सामाजिक बदनामी, लोकलाज, भय, असुरक्षा के भाव, आर्थिक परनिर्भरता आदि के कारण पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती हैं।

स्त्री के विरुद्ध हिंसा के तमाम मामले किसी खास वर्ग में सीमित न होकर शिक्षित-अशिक्षित, संपन्न-गरीब हर तबके में समान रूप से होते हैं। आश्चर्यजनक यह भी है कि स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम हो या घरेलू, पढ़ी-लिखी हो या अनपढ़, कमोबेश सभी स्तर पर घरेलू हिंसा का शिकार बनती है और कई कारणों से इसे जीवन का हिस्सा मानकर चुप्पी ओढ़े रहती है। चूंकि अधिकांश स्त्रियां अपनी मां, दादी, चाची, बुआ आदि को इसी रूप में देखती बड़ी होती हैं, इसीलिए उनके लिए यह सब साधारण बात होती है। आर्थिक रूप से पराश्रित स्त्रियों को अक्सर यह भी सुनने को मिल जाता है कि खाना, कपड़ा, गहना, दुलार, सुरक्षा सब तो मिल ही रहा है, पति है, गुस्सा में कभी-कभार पीट ही दिया तो क्या हो गया! घरेलू हिंसा के प्रति यह सामाजिक स्वीकार्यता ही इस अपराध को और बढ़ा रही है।

सवाल यह है कि क्या स्त्रियों के साथ होने वाली हिंसा बदस्तूर यों ही जारी रहेगी। तमाम कानूनों, नियमों और पहल के बावजूद इसमें कमी क्यों नहीं हो रही है? स्त्री की शिक्षा, उसका सशक्तीकरण आदि क्या इसे रोक पा रहे हैं? इस समस्या का निदान क्या है? सच यह है कि कई सकारात्मक सामाजिक और व्यवस्थागत कोशिशों के बावजूद भारत के लगभग हर हिस्से में स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के मामले और बढ़े हैं। कानून और व्यवस्थाएं एक हद तक अपना काम कर रही हैं, लेकिन जरूरत उस सोच को जानने और समझने की है, जो घरेलू हिंसा का कारण है। हमारी व्यवस्था में स्त्री को बेचारगी से उबारने के लिए पता नहीं कितने नियम और कानून बने हैं। सामाजिक संस्थाएं लगातार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम करने का दावा करती रही हैं। पर दुखद है कि अभी तक हम उस नासूर से ही अनजान हैं, जहां से यह दर्द निकल कर आता रहा है। वह नासूर है, पुरुष मानसिकता की श्रेष्ठतावादी सोच।

सदियों से पितृसत्तावादी समाज की जड़ों में यह बैठा है कि स्त्री, पुरुष से कमतर है, दोयम है, संपत्ति है आदि। हर स्तर पर हो रही स्त्री के खिलाफ हिंसा की असली वजह भी इसी सोच में समाई है। इसे रोकने के लिए इसी सोच के खिलाफ लड़ना और इसे मिटाना होगा। महिलाओं के कथित उत्थान में लगी व्यवस्थाओं को अपनी ऊर्जा इसी सोच को स्थायी तौर से मिटाने में लगानी होगी। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि जिसके साथ गलत हो रहा है, वह मजबूती से आवाज उठाए। सामाजिक बनावट, परंपरा, सोच, शर्म, भय आदि को परे झटककर स्त्री सबसे पहले अपने लिए, अपने साथ खड़ी हो जाए। उसे सबसे पहले अपने आप को मनुष्य समझना होगा, अपनी खुशियों की पहचान करनी होगी। स्वयं को वास्तविक संदर्भों में तरजीह देनी होगी। 'जिसकी छत टपकती है, निर्माण की पहल भी उसे ही करनी होती है।' यहां तो एक पक्ष चाहता ही है कि पितृसत्ता की भ्रामक श्रेष्ठता वाली व्यवस्था सदैव बनी रहे, क्योंकि उसका सुख उसी में है। स्त्री को हर स्तर पर इस जाल को न सिर्फ समझना होगा, बल्कि उसे काटने के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। पहचान, शिक्षा, सम्मान, कमाई, समय, पसंद, नापसंद जो भी उसका है, उसे हक के साथ लेना होगा। पहली बार में ही हिंसा की कुचेष्टा पर अंतिम रूप से लगाम लगाना अनिवार्य है। घर का होना और उसका हंसता-मुस्कुराता स्वरूप जरूरी है, पर यह सब उस घर की बेटी, बहू या अन्य स्त्री चरित्र की खुशियों की कीमत पर अस्वीकार्य है। कानून भी यही कहता है।

दुनिया मेरे आगे

सिकुड़ती संवेदनाएं

श्याम यादव

मौजूदा दौर में दुनिया की भीड़ ही सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता का कारण बन रही है। हमारे आसपास इतने लोग दिखाई देते हैं कि कई बार हम खुद को गुम होता पाते हैं। यह प्रत्यक्ष दुनिया की बात है, लेकिन इसके अलावा आज हम अकेले में भी कभी अकेले नहीं होते हैं। यानी वास्तविक दुनिया की व्यस्तताओं से इतर आभासी दुनिया में हमारी उपस्थिति हमें जरूरत से ज्यादा बड़ी भीड़ से घेरे रखती है। इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या है और क्यों है कि चारों तरफ लोगों और भीड़ से घिरे होने के बावजूद हम अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, अकेलेपन को लेकर परेशान होते हैं। यही शायद आज हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। मनुष्य पहले कभी इतना जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन शायद पहले कभी इतना अकेला भी नहीं था। मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और डिजिटल संपर्कों के इस दौर में संवाद बढ़ा है, पर आत्मीयता घटी है। यही कारण है कि अकेलापन अब केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है।

यों तो आभासी दुनिया में हर वक्त भीड़ देखने या उसके बीच मौजूद होने के बावजूद अकेलेपन के एहसास को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, लेकिन कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की सामाजिक संपर्क आयोग की रिपोर्ट ने भी अकेलेपन को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया है। दुनिया भर में हर वर्ष आठ लाख से ज्यादा लोगों की मौत सामाजिक अलगाव और अकेलेपन से जुड़ी हुई मानी जाती है। इससे पता चलता है कि अकेलापन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न भी है।

> भारत जैसे भावनात्मक समाज की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते, पड़ोस, साझा जीवन और संवाद की परंपरा रही है। अगर ये कमजोर पड़ते हैं, तो अकेलापन केवल व्यक्ति की समस्या नहीं रहता, वह समाज की भी समस्या बन जाता है। डिजिटल युग में तकनीक आवश्यक है, लेकिन वह मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं हो सकती।

भारत में परिवार केवल आर्थिक संस्था की हैसियत में चलने वाला कोई ढांचा नहीं है, बल्कि भावनात्मक सहारे का आधार भी रहे हैं। संयुक्त परिवारों में तो कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। घरों में बातचीत, हंसी, तकरार और अपनापन जीवन का हिस्सा थे। आज शहरीकरण और बदलती जीवनशैली ने परिवारों को छोटी-छोटी इकाइयों में बांट दिया है। लोग एक ही घर में रहते हुए भी अलग-अलग कमरों और उसमें भी अलग-अलग 'स्क्रीन' में सिमट गए हैं। यह शहरों की तस्वीर है, लेकिन सच यह है कि ग्रामीण समाज भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। रोजगार और शिक्षा की तलाश में युवा शहरों की ओर चले गए हैं। गांवों में पीछे छूटे माता-पिता और बुजुर्ग अक्सर सामाजिक और भावनात्मक अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। वहीं शहरों में रहने वाला युवा वर्ग भी प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और व्यावसायिक दबावों के बीच अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता है।

सच यह है कि अकेलापन उम्र नहीं देखता। बुजुर्गों के साथ-साथ युवा और किशोर भी इसकी चपेट में हैं। पढ़ाई, करिअर, असफलता का भय, रिश्तों की अस्थिरता और बढ़ती महत्त्वाकांक्षाएं व्यक्ति को भीतर से थका रही हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर संवाद का एक गहरा अभाव पैदा हो गया है। सोशल मीडिया ने संपर्क के नए अवसर दिए हैं, लेकिन कई बार उसने निकटता का भ्रम भी पैदा किया है। मित्रता 'फालोअर' और 'लाइक' में बदलती और सिमटती जा रही है। हजारों संपर्कों के बावजूद लोग अपनी समस्याएं और भावनाएं साझा करने वाला कोई करीबी व्यक्ति नहीं खोज पाते। लोग 'आनलाइन' हैं, पर एक-दूसरे के जीवन में उपस्थित नहीं हैं। तकनीक ने संचार को सरल बनाया है, लेकिन मानवीय संबंधों का विकल्प अभी तक नहीं बन सकी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक अकेलापन, अवसाद, चिंता, नींद की समस्या, हृदय रोग और समयपूर्व मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक संबंधों को अब स्वास्थ्य के एक महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में देखने की जरूरत पर बल दिया है। यह एक ऐसी अदृश्य महामारी है, जो धीरे-धीरे समाज की जड़ों को प्रभावित कर रही है।

दुनिया के कई देशों ने इस समस्या को सार्वजनिक नीति का विषय बनाया है। ब्रिटेन ने अकेलेपन से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की थी और जापान ने भी सामाजिक अलगाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए अलग सरकारी व्यवस्था बनाई। भारत में भी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को लेकर चर्चा बढ़ी है, लेकिन अभी इस दिशा में व्यापक सामाजिक पहल की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बुजुर्गों के लिए सामाजिक मंच विकसित करने की जरूरत है, लेकिन समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं निकलेगा। समाज को भी अपने भीतर झांकना होगा। पड़ोस, मित्रता, सामुदायिक गतिविधियां, पुस्तकालय, उद्यान, वरिष्ठ नागरिक समूह और परिवार के भीतर संवाद- ये सभी सामाजिक जीवन के वे सूत्र हैं जो व्यक्ति को अकेलेपन से बचाते हैं।

आज जरूरत यह है कि हम डिजिटल संपर्क और मानवीय संबंधों के बीच का अंतर समझें। संबंध केवल संपर्क करने से नहीं बनते, उन्हें समय, संवाद और संवेदना से निभाया जाता है। किसी का हाल पूछ लेना, किसी बुजुर्ग के साथ कुछ समय बैठ जाना या किसी मित्र की चुप्पी को सुन लेना भी सामाजिक उपचार का काम कर सकता है। भारत जैसे भावनात्मक समाज की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते, पड़ोस, साझा जीवन और संवाद की परंपरा रही है। अगर ये कमजोर पड़ते हैं, तो अकेलापन केवल व्यक्ति की समस्या नहीं रहता, वह समाज की भी समस्या बन जाता है। डिजिटल युग में तकनीक आवश्यक है, लेकिन वह मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि आखिरकार मनुष्य को वस्तुओं से अधिक किसी अपने के होने की आवश्यकता होती है।

सुविधा की मुश्किल

आज मोबाइल फोन, लैपटाप और कंप्यूटर केवल संचार के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा और मनोरंजन का आधार बन चुके हैं। कार्यालयों से लेकर घरों तक अधिकांश कार्य अब स्क्रीन के सामने बैठ कर पूरे किए जाते हैं। मगर तकनीक की इस सुविधा की एक ऐसी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंखों और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने के बाद अब कलाई और अंगुलियों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। यदि समय रहते इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो यह आने वाले वर्षों में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन सकती है। कुछ वर्ष पहले तक 'कार्पल टनल सिंड्रोम' और 'ट्रिगर फिंगर' जैसी समस्याएं कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों या अधिक आयु के लोगों में देखी जाती थीं। अब स्थिति बदल चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े लोग, बैंक कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, ग्राफिक डिजाइनर और यहां तक कि स्कूली बच्चे भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार टाइप करने और माउस के अत्यधिक उपयोग से हाथों की नसों पर दबाव पड़ता है।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

व्यवस्था पर सवाल

'भ्रष्टाचार की दीमक' (संपादकीय, 2 जुलाई) पढ़ा। एक घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और नैतिकता के सामने खड़े गंभीर सवालों की ओर संकेत करती है। जब व्यवस्था के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो आम नागरिक का व्यवस्था पर विश्वास स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है। यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि किसी भी आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। आरोप सिद्ध होते हैं, तो कठोर दंड केवल अपराधी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे तंत्र को यह संदेश देने के लिए भी आवश्यक है कि पद और प्रभाव कानून से ऊपर नहीं हैं। भ्रष्टाचार का समाधान केवल समय-समय पर होने वाली गिरफ्तारियों में नहीं, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने में है जहां ईमानदारी को संरक्षण मिले, भ्रष्टाचार के अवसर न्यूनतम हों और हर अधिकारी अपने निर्णयों के लिए वास्तविक रूप से उत्तरदायी हो।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

धोखे की कड़ियां

वाट्सएप अपनी नई सुविधाओं को लेकर विवादों में घिर गया है। इस सुविधा में 'यूजरनेम फीचर' से लोग अपना फोन नंबर और पहचान छिपा सकेंगे। वे केवल 'यूजरनेम' से संवाद कर पाएंगे। यह सच है कि नई सुविधाओं का लोगों में आकर्षण रहता है, पर यह नई सुविधा डिजिटल फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे सकती है। किसी भी व्यक्ति या अधिकारी का प्रतिरूपण कर लोगों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इससे जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले बढ़ेंगे। किसी के नाम का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लोगों को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि वे किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बढ़ते यौन अपराध, शोषण और भयादोहन के मामलों को देखते हुए वाट्सएप की नई सुविधा लड़कियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। संवाद करने वाले की अपनी सही जानकारी और पहचान उजागर करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी गलत पहचान के चलते किसी के साथ धोखा न हो।

– अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

सामाजिक त्रासदी

आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिश्तों में भरोसा और इंसानियत धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है? जिस रिश्ते में भरोसा, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने की उम्मीद होती है, अगर वहीं से धोखे और अपराध की खबर सामने आए, तो यह केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं होती, बल्कि समाज के मूल्यों पर भी सवाल खड़ा करती है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन कई बार उनमें विश्वास और धैर्य की कमी दिखाई देती है। छोटी-छोटी बातों से शुरू होने वाले विवाद कभी-कभी इतने गंभीर रूप ले लेते हैं कि इंसान सही और गलत का अंतर भूल जाता है। गुस्सा, लालच, बदले की भावना और स्वार्थ जब इंसान पर हावी हो जाते हैं, तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी पर पड़ता है।

– गंगा पांडेय, बाढ़, पटना

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

भारतीय एअरलाइंस से मई में 1.53 करोड़ यात्रियों ने किया घरेलू सफर : डीजीसीए

भारतीय एअरलाइंस से मई महीने में कुल 1.53 करोड़ यात्रियों ने घरेलू सफर किया जो अप्रैल के 1.38 करोड़ यात्रियों से 11 फीसद अधिक है। मंगलवार को आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। सालाना आधार पर भी घरेलू हवाई यातायात में 9.49 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, मई में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटकर 64.9 फीसद रह गई जबकि एअर इंडिया समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 25.6 फीसद हो गई। अकासा एअर की हिस्सेदारी 5.8 फीसद पर स्थिर रही, जबकि स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर 2.5 फीसद रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से मई 2026 के दौरान घरेलू एअरलाइंस से कुल 729.40 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह संख्या 715.70 लाख थी। इस तरह इस अवधि में 1.91 फीसद की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। (ए)

एनडी तिवारी के बाद धामी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री, जिन्होंने 5 साल किए पूरे

सुनील दत्त पांडेय

उत्तराखंड

फाइल फोटो

छठवें साल में किया प्रवेश, कई वादे पूरे किए, लेकिन अभी रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन आदि के क्षेत्र में काफी कुछ किए जाने की जरूरत, पहाड़ों में अवैध निर्माण के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति की आवश्यकता।

मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे होने व छठवें वर्ष में प्रवेश करने पर उत्तराखंड में 4 जुलाई से सेवा सुशासन समर्पण पखवाड़ा मनाया जा रहा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा है। वे पंडित नारायण तिवारी के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए हैं। वे छठवें साल में प्रवेश करने वाले उत्तराखंड के इकलौते और पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकारों के वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी (2002-2007) उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने धामी से पहले 5 साल और 5 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था। पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2022 में भाजपा ने धामी के चेहरे को आगे रख कर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उसके बाद वे दुबारा से मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तब से वे पदासीन हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और 26 सालों में यहां राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा रही। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों दलों ने मुख्यमंत्री बीच कार्यकाल में बदले। भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मुख्यमंत्री बदले। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री मैदानी क्षेत्र के रहने वाले हरियाणा के मूल निवासी नित्यानंद स्वामी को बनाया गया, जिसका उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जबरदस्त विरोध हुआ क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी और उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा भगत सिंह कोश्यारी या भुवन चंद्र खंडूडी को मुख्यमंत्री बनाएगा।

भाजपा को यह लगा कि 2002 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नित्यानंद स्वामी भाजपा की नैया पार नहीं लगा सकेंगे और उन्हें 11 महीने बाद मुख्यमंत्री पद से हटा कर राज्य के पर्वतीय खांटी नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता रहे भगत सिंह कोश्यारी को राज्य का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। परंतु प्रयोग असफल रहा। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और राज्य की पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता नारायण दत्त तिवारी बने। भगत सिंह कोश्यारी केवल 5 महीने ही मुख्यमंत्री रहे।

अब तक उत्तराखंड में कुल 12 मुख्यमंत्री रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से 10 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। भुवन चंद्र खंडूरी दो बार मुख्यमंत्री बने। खंडूरी के नेतृत्व में 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। परंतु जनता ने भाजपा और खंडूरी दोनों को नकार दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी भुवन चंद्र खंडूरी कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव हार गए।

सरकार को पहले ही पता होगा, कब होना है राजमार्ग-पुल का रखरखाव

पंकज रोहिला

देश

सितंबर तक देश में पुलों व राजमार्ग का बनेगा नया राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय डेटा बेस को नए सिरे से करेगी तैयार, एजंसियों को निर्देश।

देश में पुलों के बारे में सही जानकारी के लिए यह पहल की गई है। क्योंकि पुलों की खराब हालत से परिवहन में रुकावट आती है।

देश भर के राजमार्ग और उपरिगामी पुल कितने पुराने हैं और उन्हें कब मरम्मत की जरूरत है और बनावट में क्या बदलाव लाकर उसमें सुधार किए जा सकते हैं। इसके लिए देश भर में उपरिगामी पुल, राजमार्ग और पुलों का नए सिरे से नया राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा (नेशनल डेटाबेस) तैयार होगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने एजंसियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी राज्यों को राजमार्ग व पुलों संबंधित जानकारियां सितंबर तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

'इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम' में ये सारा आंकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी मदद से देश के सभी पुलों की सूची तैयार हो जाएगी और उनकी संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए विकसित किया जा सकेगा ताकि संरचना की गंभीरता के आधार पर समय पर मरम्मत और सुधार का काम किया जा सके। देश में पुलों के बारे में सही जानकारी के लिए यह पहल की गई है। क्योंकि पुलों की खराब हालत से परिवहन में रुकावट आती है और कई बार इससे दुर्घटनाएं भी हुई हैं और लोगों की जान भी गई है। इस तकनीक में संबंधित अधिकारी के पास मोबाइल पर ही पूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी और निगरानी की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि दर्ज की गई जानकारियों के लिए संबंधित स्थानीय जमीनी स्तर की यूनिट की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित परियोजना निदेशक को सात फीसद पुलों की जांच की रिपोर्ट को सत्यापित करना होगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मंत्रालय क ओर से आगामी 30 सितंबर 2026 तक समय दिया गया है। आदेशों में सर्वेक्षण के प्रारूप, पुल की स्थिति और प्राथमिकता के आधार पर रखरखाव, मरम्मत और दोबारा बनाए जाने संबंधित तथ्यों की जानकारियां शामिल की गई।

इस तकनीक में सूची बनाते समय, हर पुल को एक खास पहचान नंबर दिया जाता है। यह नंबर राज्य, आरटीओ जोन और इस आधार पर तय किया जाता है कि आसानी से पता चल जाता है कि पुल किस राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य मार्ग या जिला सड़क पर बना है। इसके बाद, जीपीएस की मदद से पुल की सही जगह (अक्षांश-देशांतर) का पता लगाया जाता है और इसी आधार पर पुल को 'ब्रिज लोकेशन नंबर' दिया जाता है।

इस आंकड़े में पुल की इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारी जैसे डिजाइन, इस्तेमाल हुई सामग्री, पुल का प्रकार, उम्र, भार सहने की क्षमता, यातायात लेन, लंबाई, सड़क की चौड़ाई (कैरेजवे) आदि इकट्ठा की जाती हैं और इनका इस्तेमाल पुल की पहचान तय करने में किया जाता है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में 2016 से पहल की शुरुआत की थी।

डीजल में 15% आइसोब्यूटेनाल मिलाने की तैयारी में सरकार

सर्वेश कुमार

देश

विशेषज्ञों के मुताबिक, पेट्रोल में ई20 मिश्रण की तुलना में डीजल में आइसोब्यूटेनाल का मिश्रण बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रक में इस्तेमाल होने वाले डीजल से वाहनों में अगर कोई समस्या आती है तो परेशानियां बढ़ सकती हैं।

पेट्रोल में 20 फीसद एथेनाल (ई20) के प्रयोग के बाद सरकार अब डीजल में 15 फीसद तक आइसोब्यूटेनाल मिलाने की तैयारी कर रही है। चूंकि एथेनाल डीजल में नहीं घुलता, इसलिए इसे एथेनाल से ही किण्वन (प्रोसेस) करके आइसोब्यूटेनाल में बदला जाता है। जनरेटर सेट पर सफल परीक्षणों के बाद अब व्यापक स्तर पर डीजल में आइसोब्यूटेनाल मिलाने की योजना है। चरणबद्ध इसे लागू करने से सालाना खपत में करीब एक करोड़ टन से भी अधिक डीजल की बचत हो सकती है। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होने के साथ अरबों डालर विदेशी मुद्रा भंडार की बचत हो सकती है। पेट्रोल में इथेनाल की तर्ज पर डीजल में आइसोब्यूटेनाल के मिश्रण से देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

एथेनाल के किण्वन से आइसोब्यूटेनाल तैयार किया जाता है जो एक जैव ईंधन है। भारत ने एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ई 20) का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया। इससे तेल आयात के मद में होने वाले खर्च (1.9 लाख करोड़ रुपए) की बचत के साथ साथ किसानों की आय में भी 1.6 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जनरेटर सेट पर 100 फीसद सफल परीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल में 15 फीसद तक आइसोब्यूटेनाल मिलाने की घोषणा की है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान कच्चे तेल के आयात के लिए अन्य देशों पर निर्भरता के कारण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि पेट्रोल में ई-20 मिश्रण को लेकर उठाए गए सवालों के बाद वाहन निर्माण कंपनियों ने भी कहा कि इससे वाहनों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा।

आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआइ) के अध्ययन से पुष्टि हुई है कि ई20 से माइलेज में 2-6 फीसद तक की कमी आई है (जिसे 2023 के बाद के वाहनों में ठीक कर लिया गया है)। हालांकि, कार बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने कोई बड़ी समस्या नहीं बताई है। इंस्टीट्यूट आफ केमिकल टेक्नोलाजी (आइसीटी) के प्रोफेसर पद्मश्री गणपति डी यादव के मुताबिक, पेट्रोल में एथेनाल मिश्रण की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि विज्ञान-आधारित नीतियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई दिशा दे सकती हैं। अब वक्त आ गया है कि डीजल में 15 फीसद नवीकरणीय आइसोब्यूटेनाल मिश्रण का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। भारत में सालाना करीब 9 करोड़ टन डीजल की खपत होती है और अगर 15 फीसद आइसोब्यूटेनाल मिश्रण अपनाया जाता है, तो हर साल 1 करोड़ टन से अधिक डीजल के समतुल्य ईंधन की बचत की जा सकती है।

कृषि

असम के मोरीगांव में धान के पौधे लगाने के लिए उन्हें बीज-क्यारी से खेत तक ले जाते किसान।

कभी नक्सल क्षेत्र रहे अबूझमाड़ में अब होगी कहवे की खेती

जनसत्ता विशेष

छत्तीसगढ़

देश से नक्सलवाद का धीरे-धीरे अंत हो रहा है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। कभी धुर नक्सल प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में अब बड़े पैमाने पर कहवे की खेती शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अबूझमाड़ के वन क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बेहद अनूठी पहल की है। बस्तर के इस अंचल में अब बड़े पैमाने पर कहवा (काफी) की खेती शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में नारायणपुर जिले के कलेक्टर ने भारत सरकार के काफी बोर्ड के विशेषज्ञों के साथ कुतुल, कच्चापाल, कोडलियार, ईरकभट्टी और तोके सहित आस-पास के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत जमीनी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान काफी बोर्ड के विशेषज्ञ दल ने क्षेत्र की जलवायु, वार्षिक वर्षा, तापमान, मिट्टी की प्रकृति और समुद्र तल से ऊंचाई का गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया। बोर्ड के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अबूझमाड़ का प्राकृतिक वातावरण काफी उत्पादन के लिए पूरी तरह अनुकूल है।

विशेषज्ञों के अनुसार, काफी के पौधों का करीब चार वर्षों तक रखरखाव करने के बाद व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। इसके बाद यह ग्रामीणों के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी नियमित आय का जरिया बनेगा। इस पूरी परियोजना में स्थानीय स्वयं-सहायता समूहों और ग्रामीणों की सीधी भागीदारी तय की जाएगी, जिससे हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अबूझमाड़ के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण का सही उपयोग करना, वनों का संरक्षण करना और स्थानीय ग्रामीणों को आय का एक स्थायी व मजबूत जरिया देना है। प्रारंभिक चरण में भूमि का चयन कर स्थानीय स्तर पर नर्सरी की शुरुआत की जा रही है।

पंजाब का कुका व ओड़ीशा का पाइका आंदोलन अब पाठ्यक्रम में

सुशील राघव

शिक्षा

न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से चार महीने पहले वापस ली गई आठवीं की पुस्तक जारी की गई

अब नए डिजाइन किए गए आवरण पृष्ठ पर सुप्रीम कोर्ट को प्रमुखता से दिखाया गया है।

फिर से लिखे गए पाठ में विवादित हिस्सों को हटा दिया गया है, और साथ ही जनहित याचिका, ट्रिब्यूनल और विवाद सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में नई जानकारी जोड़ी गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक में पंजाब का कुका और ओड़ीशा का पाइका आंदोलन शामिल किया है। पाइका आंदोलन को पहली पुस्तक में शामिल नहीं करने पर विवाद हो गया था। ओड़ीशा के नेताओं ने इसे पुस्तक में शामिल करने की मांग की थी। पुस्तक में कम जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानियों को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर सुप्रीम कोर्ट को प्रमुखता से दिखाया गया है। साथ ही फिर से लिखे गए पाठ में विवादित हिस्सों और अदालतों में लंबित मामलों व दो बड़े अदालती फैसलों के जिक्र को हटा दिया गया है, और साथ ही जनहित याचिका, ट्रिब्यूनल और विवाद सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में नई जानकारी जोड़ी गई है।

इस पुस्तक को सुप्रीम कोर्ट ने 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले विवादित हिस्से की वजह से किताब के पुराने संस्करण को हटाने का आदेश दिया था। पुस्तक में कूका आंदोलन (जिसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है) का उल्लेख किया गया है। यह एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जो 1860 के दशक में पंजाब में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य नैतिक सुधार, सामाजिक समानता तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और औपनिवेशिक संस्थाओं को अस्वीकार करने के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। कूका आंदोलन के अनुयायी गौ-हत्या का भी कड़ा विरोध करते थे। उनका विरोध उन बूचड़खानों के खिलाफ था, जिन्हें औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित या स्वीकृत किया गया था और जो कई बार जानबूझकर गुरुद्वारों के निकट बनाए जाते थे। 1872 में स्थिति तब गंभीर हो गई जब कुछ कूका अनुयायियों ने ऐसे कुछ बूचड़खानों पर हमला कर दिया।

इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने अत्यंत क्रूर कार्रवाई की। बिना किसी मुकदमे के 65 कूका अनुयायियों को मृत्युदंड दे दिया गया, जिनमें से कई को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया।ओड़ीशा का औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह पाइका संग्राम औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुए प्रारंभिक विद्रोहों में से एक था। यह विद्रोह वर्तमान ओड़ीशा के खुर्दा में हुआ था और इसकी जड़ें दशकों से चले आ रहे ब्रिटिश विश्वासघात और शोषण में निहित थीं। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने के बाद, खुर्दा के राजा ने पाया कि कंपनी ने उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और जगन्नाथ मंदिर पर उनका धार्मिक अधिकार छीन लिया गया है। राजा के गुरु जयी राजगुरु के नेतृत्व में हुए प्रतिरोध के परिणामस्वरूप 1806 में उन्हें फांसी दे दी गई, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा और भड़क उठा।

इतना ही नहीं पुस्तक में उत्तर-पूर्वी भारत में हुए स्वतंत्रता आंदोलनों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में अभी तक कम पढ़ाया जाता था। आजादी के संघर्ष में पूर्वोत्तर भारत का भी अलग-अलग समय पर योगदान रहा है। इनमें से कुछ आंदोलन 1857 से पहले हुए थे, जैसे मेघालय में तिरोत सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह (1829-1833) और असम के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह, जिसे सिंगफो विद्रोह (1830-1840 के दशक) के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान असम में अंग्रेजों ने मनीराम दीवान और पियाली बरुआ को सबके सामने फांसी दे दी थी।

मतभेद होने पर भी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखना ही सफल कूटनीति है। -झोउ एनलाई

लगातार बारिश ने जिस तरह से देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार थाम ली है और मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भी अगले एक हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी दी है, उससे यह प्रश्न फिर प्रासंगिक हो गया है कि आखिर हर वर्ष मानसून के आगे घुटने टेकती शहरी व्यवस्थाएं सबक कब लेंगी।

वही बारिश, वही कहानी

मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने जिस तरह सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त किया हुआ है और मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भी अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, उससे यह सवाल एक बार फिर प्रासंगिक हो गया है कि आखिर हर वर्ष मानसून के दौरान डूबते शहरों, बाधित यातायात और जान-माल के नुकसान से सबक लेने में हमारी शहरी व्यवस्थाएं इतनी असफल क्यों साबित होती हैं? मुंबई की बारिश में पिछले एक हफ्ते में कई लोगों की जान जा चुकी है, निचले इलाकों में जलभराव से हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं और मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाएं भी कई बार बाधित हुई हैं। कमोबेश यही स्थिति हर वर्ष दिल्ली, गुरुग्राम, बंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में भी देखने को मिलती है। मानसून का कैलेंडर तय है, उसकी संभावित तीव्रता का अनुमान भी मौसम विभाग अब अधिक सटीकता से लगाने लगा है। फिर आखिर क्यों हमारी तैयारी हर बार नाकाफी रह जाती है? बारिश एक प्राकृतिक घटना है, पर उसका हर वर्ष आपदा में बदल जाना क्या मानवीय विफलता का नतीजा नहीं माना जाना चाहिए? यह समझना चाहिए कि समस्या बारिश नहीं, बल्कि शहरी विकास का वह मॉडल है, जिसमें प्रकृति के लिए कोई जगह नहीं बची। नदियों, तालाबों, झीलों और प्राकृतिक नालों को पाटकर अव्यवस्थित ढंग से आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं खड़ी कर दी गईं। बारिश के पानी के प्राकृतिक प्रवाह के रास्ते अवरुद्ध हो जाने से पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता और थोड़ी देर की बारिश से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। ज्यादातर शहरों में दशकों पुरानी सीवर और ड्रेनेज प्रणाली आज की आबादी व कंक्रीट के फैलाव का भार उठाने में सक्षम नहीं है। नालों की समय पर सफाई नहीं होती, जबकि प्लास्टिक व ठोस कचरा उनमें भरता जाता है। बारिश शुरू होने के बाद सफाई अभियान की औपचारिकता निभाई जाती है, जबकि इसकी तैयारी गर्मियों से शुरू होनी चाहिए। यह देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन ने इस चुनौती

को अधिक गंभीर बना दिया है और अब कम समय में अधिक मात्रा में बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, सिर्फ पुराने ढांचे की मरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि मौसमी बदलावों के मद्देनजर नई तरह की शहरी योजना बनानी होगी। इस मामले में हम दुनिया के अत्याधुनिक शहरों से काफी कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने स्पंज सिटी मॉडल, हरित क्षेत्रों के संरक्षण और रियल-टाइम में बाढ़ की चेतावनी प्रणाली के जरिये शहरी बाढ़ के जोखिम को कम किया है। बारिश के बाद समीक्षा बैठकों, मुआवजे की घोषणाओं और जांच समितियों का चक्र अब टूटना चाहिए और शहरी नियोजन को भी जलवायु-जोखिमों के अनुरूप बदलना चाहिए।

बदलती भू-राजनीति के संकेत

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन की हालिया यात्रा दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह दर्शाती है कि इस क्षेत्र के छोटे व मध्यम देश अब किसी एक शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्पों का विस्तार कर रहे हैं। भारत के लिए यह चुनौती भी है और अवसर भी।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन की हालिया यात्रा दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस यात्रा को केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता कि उन्होंने नई दिल्ली से पहले बीजिंग का दौरा किया, बल्कि इसलिए कि, इस दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंचाने का निर्णय लिया। रणनीतिक हलकों में इसे दिल्ली-ढाका रिश्तों में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

चीन और बांग्लादेश ने अपने व्यापक रणनीतिक सहयोगी संबंधों को और मजबूत करते हुए 'नए युग में साझा भविष्य वाले चीन-बांग्लादेश समुदाय' के निर्माण की घोषणा की। दोनों देशों ने कूटनीति, रक्षा, व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, संपर्क, शिक्षा और बहुपक्षीय सहयोग सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। यह घटनाक्रम भारत के लिए स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय तो है ही, लेकिन अपनी पड़ोस नीति की समीक्षा करने और उससे जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर खोजने का अवसर भी है। यात्रा के दौरान हुए समझौतों में सबसे अधिक ध्यान दो परियोजनाओं ने आकर्षित किया।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपीआईडीएसए

पहली, तीस्ता नदी समग्र प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना (टीआरसीएमआरपी), जिसके लिए चीन ने तकनीकी सहयोग और व्यवहार्यता अध्ययन में सहायता देने का आश्वासन दिया है। दूसरी, मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उसके निकट चीनी आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास की परियोजना। दोनों परियोजनाएं भारत की पूर्वी सीमा के निकट स्थित हैं। तीस्ता परियोजना भारत के लिए इसलिए संवेदनशील है, क्योंकि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के शेष भाग से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जीवनरेखा है। वहीं मोंगला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जहां चीन पिछले कुछ वर्षों से अपनी आर्थिक

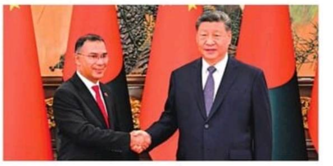

व सामरिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसलिए, भारत की चिंता स्वाभाविक है। दरअसल, चीन का बांग्लादेश में प्रभाव अचानक नहीं बढ़ा है। पिछले दो दशकों में उसने योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेश में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता व बड़े विकास साझेदारों में शामिल है। इसलिए, यह यात्रा नए दौर की शुरुआत कम, पहले से चल रही प्रक्रिया के और ज्यादा संस्थागत तथा व्यापक होने का संकेत अधिक है।

यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश ने चीन का साथ सिर्फ अधिक पैसे की वजह से नहीं चुना, बल्कि इसलिए भी, क्योंकि चीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करता है। इस संदर्भ में भारत का रिकॉर्ड मिश्रित रहा है। मोंगला बंदरगाह इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। 2015 में बांग्लादेश ने इस बंदरगाह के निकट विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भारत को भूमि आवंटित की थी। भारत ने परियोजना स्वीकार भी कर ली, पर वर्षों तक कार्य शुरू नहीं हो सका। अंततः बांग्लादेश ने परियोजना चीन को सौंप दी। इसी प्रकार, तीस्ता जल बंटवारा समझौता भी एक दशक से अधिक समय से लंबित है। पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसलिए, बांग्लादेश ने नदी प्रबंधन के लिए चीन की ओर देखना शुरू किया। यहीं भारत को आत्ममंथन करने की जरूरत है। चीन ने दक्षिण एशिया में अनेक परियोजनाओं को केवल व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा है। जबकि, भारत कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय बाधाओं व घरेलू राजनीतिक कारणों से समय पर निर्णय नहीं ले पाया। नतीजतन, जिन परियोजनाओं को भारत अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता था, वे चीन के हाथों में चली गईं।

इस यात्रा की खास बात यह रही कि दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है। आज वैश्विक राजनीति में अधिकांश मध्यम व छोटे देश किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण रूप से जुड़ने के बजाय बहु-संरेखण की नीति अपना रहे हैं। वे अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए विभिन्न शक्तियों के साथ समानांतर संबंध विकसित कर रहे हैं। भारत भी अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और यहां तक कि चीन के साथ भी सहयोग बनाए रखता है। ऐसे में, यदि बांग्लादेश चीन और भारत, दोनों के साथ संबंध मजबूत रखना चाहता है, तो इसे असामान्य नहीं माना जाना चाहिए।

वास्तव में, भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बुनियाद इतनी मजबूत है कि उन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। करीब चार हजार किलोमीटर लंबी साझा सीमा, साझा नदियां, व्यापक व्यापार, ऊर्जा सहयोग, सीमा पार संपर्क, सांस्कृतिक निकटता और लोगों के बीच गहरे संबंध दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों ने हाल के महीनों में संबंध सुधारने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। भारत ने ऊर्जा संकट के समय बांग्लादेश को ईंधन की आपूर्ति भी की है। स्पष्ट है कि दोनों संबंधों को पूरी तरह खराब नहीं होने देना चाहते।

भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि पड़ोस नीति केवल ऐतिहासिक संबंधों या भौगोलिक निकटता के भरोसे सफल नहीं हो सकती। प्रभाव बनाए रखने के लिए समय पर परियोजनाएं पूरी करनी होंगी, विकास साझेदारी को अधिक विश्वसनीय बनाना होगा और पड़ोसी देशों की प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। भारत की सुरक्षा चिंताएं भी पूरी तरह उचित हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या बंगाल की खाड़ी के निकट चीन की बढ़ती उपस्थिति का सामरिक महत्व है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर, इन चिंताओं का समाधान केवल विरोध दर्ज कराने या बांग्लादेश के निर्णयों पर असंतोष व्यक्त करने से नहीं होगा। भारत को स्वयं को सक्षम, भरोसेमंद और त्वरित विकास साझेदार के रूप में पेश करना होगा।

तारिक रहमान की चीन यात्रा यह दर्शाती है कि दक्षिण एशिया के छोटे और मध्यम देश अब किसी एक शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्पों का विस्तार कर रहे हैं। यह भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यदि नई दिल्ली अपने स्वाभाविक भौगोलिक लाभ, ऐतिहासिक संबंधों और आर्थिक क्षमता को बेहतर कार्यान्वयन, तेज निर्णय प्रक्रिया और बेहतर कूटनीति के साथ जोड़ सके, तो वह बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बना रहेगा। लेकिन, यदि वह अपनी पुरानी कमजोरियों को दूर नहीं कर पाया, तो चीन दक्षिण एशिया में उस रणनीतिक स्थान को भरता रहेगा, जिसे भारत स्वयं खाली छोड़ता जा रहा है।

जीवन धारा

श्री श्री रवि शंकर

जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या उद्देश्य होता है, जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो जीवन में स्वाभाविक रूप से उत्साह बना रहता है। तब हर दिन जीने का एक कारण होता है और मन अधिक प्रसन्न रहता है।

असली आनंद का रहस्य स्वयं से परे है

मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या उद्देश्य होता है, जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो जीवन में स्वाभाविक रूप से उत्साह बना रहता है। तब हर दिन जीने का एक कारण होता है और मन अधिक प्रसन्न रहता है। लेकिन, यदि हमारा पूरा ध्यान केवल स्वयं को खुश रखने पर केंद्रित हो जाए, तो धीरे-धीरे भीतर खालीपन बढ़ने लगता है और अवसाद की संभावना भी बढ़ जाती है।

अवसाद का मूल भाव ही यही है-'मेरे बारे में क्या?' जबकि जीवन का वास्तविक आनंद तब शुरू होता है, जब यह प्रश्न बदलकर 'मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं?' बन जाता है। इसीलिए, मैं सेवा को केवल सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि आंतरिक उपचार का माध्यम मानता हूं। जब व्यक्ति किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करने का संकल्प लेता है, तो उसका ध्यान अपनी सीमित समस्याओं से हटकर एक बड़े उद्देश्य की ओर चला जाता है। यही कारण है कि जहां सेवा, त्याग और सामुदायिक सहभागिता की भावना मजबूत होती है, वहां मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती हैं। मेरे अनुसार, अवसाद केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि जीवन को सीमित दृष्टि से देखने का परिणाम भी है। जब व्यक्ति को लगता है कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा, तब निराशा उसे घेरने लगती है। वहीं, जब हमारी प्राणशक्ति बढ़ती है, तो वही जीवन उत्साह, आनंद और नई संभावनाओं से भर उठता है। इसलिए, मैं हमेशा सही श्वास-प्रश्वास, ध्यान और सकारात्मक संगति पर जोर देता हूं, क्योंकि ये केवल मन को शांत नहीं करते, बल्कि जीवन ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। अक्सर हम तुच्छ चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी विशाल संभावनाओं को ही भूल जाते हैं। जैसे, आंख के सामने आया धूल का छोटा-सा कण पूरी दृष्टि धुंधली कर देता है, उसी प्रकार छोटी चिंताएं हमारी चेतना को सीमित कर देती हैं। लेकिन, जैसे ही सोच व्यापक होती है, वही समस्याएं अवसर के रूप में दिखाई देने लगती हैं।

मैं मानता हूं कि जब जीवन अर्थहीन लगने लगता है, तभी भीतर खालीपन जन्म लेता है और यही आगे चलकर अवसाद का रूप ले सकता है। विशेष रूप से युवाओं में आदर्शों, प्रेरणा और बड़े उद्देश्य का अभाव इस चुनौती को और गहरा बना रहा है। इसलिए, आध्यात्मिकता जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। यह किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं, बल्कि आशा, प्रेरणा और आत्मविश्वास जगाने का मार्ग है। ध्यान, सेवा, ज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने मनोबल को मजबूत करता है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने लगता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी भीतर गहरी शांति का अनुभव होता है। यही आत्मबोध, आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति हमें निराशा और अवसाद से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करते हैं।

दूसरों के लिए भी जिएं

सूत्र

जब जीवन स्वयं तक सीमित न रहकर सेवा, प्रेम और किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब भीतर नई ऊर्जा, आशा व आनंद का उदय होता है। ध्यान, सकारात्मक सोच, आत्मचिंतन और सामाजिक योगदान हमें छोटी चिंताओं से ऊपर उठाते हैं। तब हर दिन केवल जीने का नहीं, बल्कि अपने साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का अवसर बन जाता है।

दूसरा पहलू

परिचमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लगभग साढ़े तीन अरब वर्ष पुरानी चट्टानों से धरती पर जीवन के सबसे शुरुआती और स्वीकार्य प्रमाण मिलते हैं।

चट्टानों की उम्र में छिपे हैं धरती के राज

■ *क्रिस किर्कलैंड*

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा इलाके में लगभग साढ़े तीन अरब साल पुरानी चट्टानें मौजूद हैं। गहरे रंग की इन चट्टानों में दरारें हैं और इन्हें अब तक की सबसे पुरानी चट्टानों में माना जाता है। इतनी पुरानी ज्यादातर चट्टानें धरती में समा गई हैं, पर ये अब भी मौजूद हैं, जो बेहद हैरान करने वाली बात है। समय के साथ इनमें कुछ बदलाव जरूर आए, पर इतने नहीं कि इनकी शुरुआती कहानी मिट जाए।

कुछ जगहों पर इनमें अब भी पिलो बेसाल्ट की गोल आकृतियां दिखाई दे जाती हैं। यह वह लावा है, जो पानी के नीचे निकला और समुद्र की तलहटी में ठंडा हुआ था। इन्हीं चट्टानों में धरती पर जीवन के सबसे शुरुआती और व्यापक रूप से स्वीकार किए गए प्रमाण भी मिलते हैं। इन चट्टानों में बारीक दरारें (शेटर कोन्स) भी दिखाई देती हैं। ये नॉर्थ पोल डोम में उल्कापिंड की टक्कर से पैदा हुई तरंगों की जमी हुई छाप हैं और इसका ठोस प्रमाण हैं कि कभी अंतरिक्ष से कोई विशाल पिंड धरती से टकराया था। *जियोलॉजी* में छपे अध्ययन के अनुसार, यह टक्कर शायद 3.024 अरब साल पहले हुई थी। बाद में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने इसे चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह टक्कर 2.7 से 0.4 अरब साल पहले के बीच की रही होगी। दरअसल, दूर-दराज के इलाकों में एक चट्टान का दूसरी से संबंध जोड़ना मुश्किल भरा होता है। ऐसी चट्टानों के भीतर मौजूद छोटे-छोटे क्रिस्टल घड़ी की तरह काम करते हैं और यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वे कब बने या कब उनमें बदलाव आया। इसे मिनरल डेटिंग (खनिजों की उम्र का पता लगाने की तकनीक) भी कहते हैं। इन चट्टानों में मुख्य खनिज जिरकॉन था, जो समय का हिसाब रखने में अच्छा होता है। इसमें यूरेनियम भी होता है, जो धीरे-धीरे लेड (सीसे) में बदलता रहता है। यूरेनियम और लेड की मात्रा माप कर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह कब बना था, या उसमें कोई बड़ा बदलाव कब आया था। चट्टानों की संरचना में हमें कई तरह के जिरकॉन मिले। इनमें कुछ की उम्र 3.4 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी थी। चांद की चट्टानों में भी इसी तरह की जिरकॉन संरचनाएं मिली थीं। अलग-अलग खनिजों और चट्टानों में मौजूद दो घड़ियों ने लगभग 3.02 अरब साल पहले हुई एक ही घटना की ओर इशारा किया। उम्र का पता लगाने की यह कहानी दिखाती है कि पृथ्वी का सबसे पुराना इतिहास खत्म नहीं हुआ है। बस उसे पढ़ना मुश्किल है।

-द कन्वर्सेशन

ये चट्टानें उल्कापिंड की टक्कर से पैदा हुई तरंगों की जमी हुई छाप हैं और ठोस प्रमाण हैं कि कभी कोई विशाल पिंड धरती से टकराया था।

इन चट्टानों में मुख्य खनिज जिरकॉन था, जिनमें कुछ की उम्र 3.4 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी थी। चांद की चट्टानों में भी इसी तरह की जिरकॉन संरचनाएं मिली थीं।

आंकड़े

ई-रिटेल में भारत

चीन दुनिया का सबसे बड़ा ई-रिटेल (ऑनलाइन खरीदारी) बाजार है। भारत का बाजार अभी छोटा है, लेकिन इसकी वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज है।

चीन	14.0
वियतनाम	8.0
इंडोनेशिया	4.5
अमेरिका	4.0
भारत	1.6

आंकड़े विभिन्न देशों की जीडीपी में ई-रिटेल खरीदारी मूल्य के, प्रतिशत में। | स्रोत : वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या सफल हुई। मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरीं, पर महर्षि जह्नु के आश्रम में जो हुआ, उससे गंगा जी को एक नया नाम मिला।

देवनदी का जाह्नवी स्वरूप

पौराणिक कथाओं के अनुसार, महर्षि जह्नु वैदिक यज्ञों, कठोर तपस्या और धर्मपालन के लिए विख्यात थे। उनका आश्रम ऋषियों की साधना और वैदिक अनुष्ठानों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप कर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित कराया, तब उनका तीव्र और प्रचंड प्रवाह मार्ग में अनेक वनों, पर्वतों और आश्रमों से होकर आगे बढ़ा।

इसी क्रम में गंगा जी की धारा महर्षि जह्नु के आश्रम और यज्ञस्थल में प्रवेश कर गई, जिससे उनका यज्ञ बाधित हो गया। अपने तप और यज्ञ में विघ्न देखकर महर्षि जह्नु ने संपूर्ण गंगा को अपने भीतर समाहित कर लिया। मां गंगा के लुप्त हो जाने से राजा भगीरथ का उद्देश्य अधूरा रह गया। तब देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगीरथ ने महर्षि जह्नु से क्षमा याचना करते हुए गंगा जी को पुनः प्रवाहित करने का निवेदन किया। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर महर्षि ने लोककल्याण की भावना से अपने दाहिने कर्ण से मां गंगा को पुनः प्रकट किया।

अंतर्यात्रा
संकलित

महर्षि जह्नु के कर्ण से पुनः प्रकट होने के कारण गंगा जी को उनकी मानस पुत्री का सम्मान प्राप्त हुआ और वह 'जाह्नवी' नाम से प्रसिद्ध हुईं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 8 जुलाई, 1954

पांच लाख भारतीय मजदूरों की सांकेतिक हड़ताल

लंका के पांच लाख भारतीय मजदूरों की सांकेतिक हड़ताल

केन्द्र द्वारा हिंदी को बढ़ावा

भारतीयों को लेकर भेदभाव की नीति के विरोध में श्रीलंका के चाय व रबड़ बागानों में काम करने वाले पांच लाख भारतीय मजदूरों ने जबर्दस्त सांकेतिक हड़ताल की। इसका ऐलान लंका जनतंत्री कांग्रेस ने किया था।

लैरी, तुम जियो हजारों साल

कीर स्टार्मर के इस्तीफे से ज्यादा चर्चा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के स्थायी निवासी एक बिल्ले की रही, जिसे सरकारी अधिकारी का दर्जा भी प्राप्त है।

क्षमा शर्मा | **मुद्दा**

पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया कि मैंने स्टार्मर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह ट्वीट किसी इन्सान के नहीं, बल्कि एक बिल्ले के अकाउंट से किया गया था। इन महाशय का नाम लैरी द कैट है। यह प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट का स्थायी निवासी है।

बताया जाता है कि 2011 में जन्मे इन महाशय को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून के कार्यकाल में पशुओं के अनाथालय से लाया गया था। कैमरून इसे अपने बच्चों के लिए लाए थे। हालांकि, कैमरून के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बिल्लियां पसंद नहीं थीं, लेकिन इस बिल्ले ने उनके दिल में जगह बनाई। जब वह जाने लगे, तो इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर नहीं ले जा सके, क्योंकि यह उस जगह का स्थायी निवासी है। वह बहुत

उदास भी हुए। लैरी को भी उनसे और परिवार से बहुत लगाव था। इसलिए, सोचा जा रहा था कि उनके जाने के बाद पता नहीं यह कैसे रहेगा। लेकिन, इसने यह स्थान नहीं छोड़ा। कैमरून के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, सबके दिलों में लैरी ने अपनी जगह बनाई।

बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि वे घर बदलती रहती हैं, लेकिन लैरी शायद स्थान प्रिय है। इसलिए, वह कहीं नहीं गया। वह अब तक छह प्रधानमंत्रियों-डेविड कैमरून, टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर-के कार्यकाल को देख चुका है। कई लोग मजाक में कहते हैं कि लैरी अकेला, इन सभी प्रधानमंत्रियों से अधिक होशियार है। स्टार्मर से जब नाटो प्रमुख मार्क रुटे मिलने आए थे, तो जाते वक्त उन्होंने भी इससे प्यार से बातचीत की थी।

लैरी सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का निवासी ही नहीं सरकारी अधिकारी भी है। इसे चीफ माउजर आफ कैबिनेट ऑफिस का पद मिला हुआ है। इसका काम है, सरकारी इमारतों में चूहों से निपटना। इसके अलावा, परिसर की सुरक्षा और वहां आने वाले महत्वपूर्ण लोगों का अभिवादन और स्वागत करना। यह अक्सर पुराने फर्नीचर पर लेटकर झपकी लेता दिखाई देता है। यहां तक कि पत्रकार वार्ताओं के समय भी सो जाता है। विश्व के बड़े-बड़े लोगों से मिलता है, पर उन्हें जरा भी भाव नहीं देता।

ब्रिटेन की मीडिया का एक हिस्सा लैरी को आलसी कहता है, क्योंकि अभी तक महज दो चूहों के शिकार का काम ही इसके नाम दर्ज है। यह प्रधानमंत्री आवास में सबसे अधिक दिन काम करने वाला पालतू जानवर भी है। यह ब्रिटेन के मीडिया में छाया रहता है और सोशल मीडिया का स्टार है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट से अक्सर ऐसे संदेश आते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग हंसते हैं और आनंदित होते हैं। जब इसे प्रधानमंत्री आवास में लाया गया था, तो कुछ ही घंटों में यह ग्लोबल आइकन बन गया था। दुनियाभर में इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री आवास में बिताए गए इसके पहले सौ दिन पर एक पिक्चर बुक भी मिलती है। इसे जेम्स रॉबिन्सन ने लिखा है। लैरी की एक आत्मकथा भी है। बच्चों के लिए भी बहुत-सी रंग-बिरंगी किताबें हैं, जिनका प्रमुख नायक लैरी ही है। ये इतनी दिलचस्प हैं कि बच्चे बड़ी संख्या में इन्हें खरीदते और बड़े चाव से पढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा में इनकी कीमत एक सौ पचास रुपये से लेकर छह सौ रुपये तक है। लैरी के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वह प्रेस फोटोग्राफर्स और मीडिया को लेकर बहुत सजग है। इसीलिए, उसकी तरह-तरह की फोटोज दिखाई देती हैं। मजाक में लैरी के बारे में यह भी मशहूर है कि वह एक किताब लिख रहा है-*द राइज एंड फाल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स*, क्योंकि लैरी ने छह प्रधानमंत्रियों को आते-जाते देखा है।

अब इसकी उम्र हो चली है, मगर रिटायर होने को तैयार नहीं। हालांकि, जब यह इस दुनिया से विदा होगा, इसके लिए भी सरकार की तरफ से मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने के लिए योजना तैयार है। प्रेस रिलीज से लेकर सोशल मीडिया पर सूचना और बहुत-से चित्र। इन सभी को एक कंप्यूटर में रखा गया है। चूंकि, लोग इसकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, इससे लगाव भी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी मृत्यु पर राष्ट्रीय सम्मान देने की बात भी हो रही है।

इसके बाद भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कोई बिल्ला या बिल्ली आएगी, यह तो समय ही बताएगा। सफेद, काले इस बिल्ले के भाग्य जैसा भाग्य आखिर दुनिया में कितनी बिल्लियों को नसीब होता है। फिलहाल तो, लैरी, तुम जियो हजारों साल।

edit@amarujala.com

एआई बूम थमने की आशंका से सहमे निवेशक...मुनाफा 19 गुना बढ़ने की उम्मीद के बावजूद 10% टूटे सैमसंग के शेयर

नई दिल्ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने मंगलवार को 2026 की दूसरी तिमाही के परिचालन मुनाफे में 19 गुना उछाल का अनुमान जताया है, जो पिछले तीन वर्षों की उसकी संयुक्त कमाई से भी अधिक है। इसके बावजूद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संचालित चिप बूम के बने रहने से जुड़ी चिंताओं के कारण दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज के शेयरों में मंगलवार को 10.1 फीसदी तक की गिरावट आई। इससे कंपनी का बाजार मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक घट गया। इसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी एसके हाइनिक्स के शेयर भी 10.6 फीसदी तक गिर गए, जिससे बेंचमार्क सूचकांक कोस्पी 10.9 फीसदी नीचे आ गया। सैमसंग 30 जुलाई को विस्तृत नतीजे घोषित कर सकती है, जिसमें उसके हर व्यावसायिक विभाग की कमाई की जानकारी शामिल होगी। ■ ब्यूरो डेस्क

58.44 अरब डॉलर का मुनाफा संभव

एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, सैमसंग ने अप्रैल-जून का परिचालन मुनाफा 89.4 लाख करोड़ वॉन (58.44 अरब डॉलर) रहने का अनुमान लगाया है, जो एलएसईजी स्मार्टएस्टीमेट के 87.3 लाख करोड़ वॉन के अनुमान से अधिक है।

■ ***सता रहा ज्यादा आपूर्ति का डर :*** *बाजार विश्लेषकों का मानना है कि शेयरों में इस कमजोरी की वजह बाजार की अत्यधिक ऊंची उम्मीदें और एआई डाटा सेंटरों के विस्तार के थमने से जुड़ी चिंताएं हैं। विश्लेषकों का कहना है कि एआई चिप की मांग अब भी मजबूत है, लेकिन निवेशकों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस तेजी का सबसे आसान दौर बीत चुका है। डर इस बात का है कि चिप की मौजूदा किल्लत, भविष्य में जरूरत से ज्यादा आपूर्ति की समस्या न बन जाए।*

कमाई बढ़ने के बाद भी ट्रेंट 13 फीसदी लुढ़का

ट्रेंट के शेयरों में मंगलवार को 12.42 फीसदी की गिरावट आई। बीएसई पर कंपनी का शेयर 415.35 रुपये टूटकर 2928.05 रुपये पर बंद हुआ। यह बिकवाली तब हुई, जब पहली तिमाही में कंपनी की राजस्व वृद्धि बाजार के अनुमानों से कम रही। शेयरों में यह तेज गिरावट एक महीने में 23 फीसदी की तेजी और मार्च, 2026 के निचले स्तरों से आई 50 फीसदी की बढ़त के बाद आई है। निवेशक 2025-26 की चौथी तिमाही में दर्ज 20 फीसदी वृद्धि की तुलना में राजस्व वृद्धि में और तेजी आने की उम्मीद कर रहे थे।

स्टील उत्पादों के दाम घटे, ऑटो और निर्माण क्षेत्र को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में स्टील उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों और मकान बनाने वाले आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल के मुकाबले जून में प्रमुख स्टील उत्पादों के औसत भाव में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

आंकड़ों के अनुसार, सबसे बड़ी राहत घरों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले टीएमटी सरिये के दामों में मिली है, जिसकी कीमत करीब 6 फीसदी टूटकर 63,893 रुपये से 60,068 रुपये प्रति टन पर आ गई है। छतों और डक्टिंग में काम आने वाली जीपी शीट की कीमतों में भी 3 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है। वहीं, कारों और भारी मशीनरी में इस्तेमाल होने वाले एचआर कॉइल और सीआर कॉइल के दामों में भी क्रमशः 0.68 फीसदी और 1.73 फीसदी की कमी देखी गई है। कच्चे माल की लागत में नरमी और वैश्विक बाजार के रुख के चलते कीमतों में यह गिरावट आई है।

किसे होगा फायदा : टीएमटी सरिये के दाम करीब 3,800 रुपये प्रति टन तक कम होने से आम लोगों के लिए छत की ढलाई, बीम और पिलर का निर्माण किफायती होगा। एचआर और सीआर कॉइल के दाम घटने से कार, टू-व्हीलर, ट्रक बॉडी, चेसिस और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी। इससे वाहनों की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलेगी। ■ ब्यूरो डेस्क

एक्सप्लेनर

बाजार नियामक का नया प्लान

सेबी क्यों दोबारा शुरू कर रहा ओपन मार्केट बायबैक?

टैक्स नियमों में क्या बदला, जिससे सेबी को पुराना फैसला पलटना पड़ रहा...जानिए क्या है नया प्लान?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार के जरिये खुले बाजार में शेयर बायबैक व्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

इसके तहत, कंपनियां एक अगस्त से अलग से पुनर्खरीद खिड़की के बिना नियमित कारोबार व्यवस्था के माध्यम से खुले बाजार में अपने ही शेयर की पुनर्खरीद कर सकेंगी। इस कदम का उद्देश्य सुगमता और क्रियान्वयन दक्षता बढ़ाना है। साथ ही, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पूंजी आवंटन के एक साधन के रूप में पुनर्खरीद को अधिक आकर्षक बनाना भी है।

क्या है शेयर बायबैक?

■ जब किसी कंपनी के पास बहुत अधिक अतिरिक्त नकदी होती है, तो वह बाजार से अपने ही शेयरों को वापस खरीद लेती है। इसे शेयर बायबैक कहते हैं। आमतौर पर कंपनियां मौजूदा बाजार भाव से अधिक कीमत पर शेयर खरीदकर अपने शेयरधारकों को पैसा लौटाती हैं।

■ कंपनियां मुख्यतः दो तरीकों से बायबैक करती हैं। **पहला...**टेंडर ऑफर, जिसमें एक तय कीमत और समय होता है। **दूसरा...**ओपन मार्केट बायबैक जहां स्टॉक एक्सचेंज के जरिए धीरे-धीरे शेयर खरीदे जाते हैं।

अब क्या बदला इसे दोबारा शुरू करने का कारण बायबैक टैक्स ढांचे में बदलाव है। संशोधित आयकर अधिनियम, 2025 ने टैक्स व्यवस्था को बुनियादी रूप से बदल दिया है। एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी, बायबैक से मिलने वाली राशि पर शेयरधारकों के हाथ में पूंजीगत लाभ के रूप में टैक्स लगाया जाता है, जो किसी भी सामान्य शेयर बिक्री के समान है। यह कंपनियों को नपे-तुले तरीके से अतिरिक्त नकदी के उपयोग और स्टॉक की कीमतों को सहारा देने का लचीला तरीका भी देगा।

कड़े किए सुरक्षा उपाय

■ बायबैक की पूरी अवधि के दौरान कंपनी के प्रवर्तकों या उनके सहयोगियों के पास मौजूद शेयर आईएसआईए स्तर पर फ्रीज रहेंगे, ताकि वे इसमें भाग न ले सकें।

■ बायबैक कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार के 15 फीसदी से कम ही होना चाहिए। गणना कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर होगी।

■ बायबैक की पूरी प्रक्रिया को पेशकश खुलने की तारीख से 66 कार्य दिवस में पूरा करना होगा। बायबैक की पेशकश सार्वजनिक घोषणा तिथि से 4 कार्यदिवस में खुल जाएगी। ■ ब्यूरो डेस्क

निवेशकों को क्या होगा फायदा?

अब आपके पास कंपनी को सीधे शेयर बेचकर निकलने का लचीला विकल्प होगा। ध्यान रहे, यह पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर काम करता है, इसलिए आपका ऑर्डर मैच होगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। इस सौदे से होने वाले मुनाफे पर टैक्स स्लैब या नियमों के अनुसार कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, इसलिए कोई भी फैसला टैक्स की गणना करने के बाद ही करें।

न्यूज डायरी

एचडीएफसी बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक से कर्ज लेना अब महंगा पड़ सकता है। बैंक ने एक वर्ष के लोन की आधार दर (एमसीएलआर) बढ़ाकर 8.40 से 8.45 फीसदी और तीन वर्ष के लिए 8.55 से बढ़ाकर 8.60 फीसदी कर दिया गया है। एमसीएलआर वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक विभिन्न अवधियों के लिए कर्ज देते हैं। जिन ग्राहकों के होम लोन या ऑटो लोन एमसीएलआर से जुड़े हैं, वे अब महंगे हो जाएंगे। संशोधित दरें 7 जुलाई, 2026 से प्रभावी हो गई हैं। ब्यूरो

डॉलर के मुकाबले रुपया 47 पैसे मजबूत

मुंबई। डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 47 पैसे मजबूत होकर 94.96 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में बेहतर माहौल और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को मजबूती मिली। सऊदी अरब की ओर से एशिया के लिए अगस्त महीने के कच्चे तेल के दाम घटाने का भी असर बाजार पर दिखा। डॉलर की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने भी रुपये को समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.33 पर खुला। दिन में 94.93 से 95.37 के दायरे में रहा। एजेंसी

भारत 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश

एफडीआई : भारत ने लगाई दो पायदान की छलांग, निवेश 44% बढ़कर 39 अरब डॉलर

अमर उजाला ब्यूरो

अंकटाड की रिपोर्ट

नई दिल्ली। विनिर्माण क्षेत्र को आधुनिक बनाने और सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने जैसी सरकार की नीतियों के दम पर भारत 2025 में दो स्थान की छलांग लगाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पाने वाला दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल देश में 38.89 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो 2024 के 27.09 अरब डॉलर से 44 फीसदी अधिक है। 2024 में एफडीआई पाने वाले देशों में 13वें स्थान पर था।

यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (अंकटाड) ने मंगलवार को जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट-2026 में कहा, इस निवेश के दम पर भारत को वह स्थिति फिर पाने में मदद मिली है, जो दो साल पहले दुनिया के शीर्ष-10 देशों की सूची से बाहर होने से खो गई थी। भारत में यह तेजी विकासशील देशों में दिखे सुस्त रुझान के विपरीत है, जहां एफडीआई प्रवाह में सिर्फ दो फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी निवेश तीन फीसदी बढ़ा है।

अमेरिका-चीन में घटा निवेश

देश	2024	2025
अमेरिका	284	277
चीन	116	105

(आंकड़े : अरब डॉलर में)

अमेरिका शीर्ष पर, चीन का चौथा स्थान बरकरार

अमेरिका	277
सिंगापुर	151
हांगकांग	116
चीन	105
ब्राजील	77
यूके	75
जर्मनी	74
कनाडा	67
यूएई	48
मेक्सिको	41

(आंकड़े : अरब डॉलर में)

वैश्विक एफडीआई : 6 फीसदी बढ़ा

वैश्विक एफडीआई प्रवाह 2025 में 6 फीसदी बढ़कर 1.6 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया।

■ शीर्ष-20 देशों में कुल वैश्विक एफडीआई का करीब 80 फीसदी विदेशी निवेश आया।

■ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई 11 फीसदी बढ़कर 723 अरब डॉलर पहुंचा। 901 अरब डॉलर का निवेश विकासशील देशों में आया।

ग्रीनफील्ड निवेश में गिरावट

अंकटाड ने कहा, भारत में कुल एफडीआई प्रवाह जरूर बढ़ा है, लेकिन प्रोजेक्ट-स्तर संकेतक बताते हैं कि निवेश के मामले में सावधानी भरा माहौल रहा। इससे घोषित ग्रीनफील्ड निवेश का मूल्य 2024 के 111.14 अरब डॉलर से घटकर 2025 में 74.12 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया।

■ **इस गिरावट के बावजूद, 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा घोषित ग्रीनफील्ड निवेश प्रोजेक्ट भारत में आया।** अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट इंक ने भारत में एक डाटा सेंटर के लिए 14.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की, जो वैश्विक सूची में सबसे ऊपर रहा।

भारतीय कंपनियों का विदेश में 47 फीसदी अधिक निवेश

भारतीय कंपनियों ने 2025 में विदेश में 35.66 अरब डॉलर का निवेश किया। यह 2024 के 24.26 अरब डॉलर से 47 फीसदी अधिक है। इससे भारत एफडीआई के मामले में दुनिया की शीर्ष घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की सूची में दो स्थान की छलांग लगाकर 18वें पायदान पर पहुंच गया।

■ *भारतीय कंपनियों का विदेश में घोषित ग्रीनफील्ड निवेश मूल्य भी 41 फीसदी बढ़कर 25.29 अरब डॉलर पहुंच गया। राणा ग्रुप ने यूएई में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है।*

स्विगी अब भारतीय कंपनी, विदेशी निवेश घटकर 50% से नीचे

नई दिल्ली। फूड डिलीवरी एवं क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी अब भारतीय बन गई है, क्योंकि इसमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 50 फीसदी से नीचे आ गई है। चुकता इक्विटी पूंजी में कुल विदेशी हिस्सा अब 49.76 फीसदी रह गया है। इसके साथ ही कंपनी भारतीय (आईओसीसी) दर्जा मिलने के और करीब पहुंच गई है। हालांकि विदेशी हिस्सेदारी 50 फीसदी से नीचे आने से फिलहाल कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे शेयर पूंजी, प्रबंधन, कारोबार या मतदान अधिकार पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्विगी लंबे समय से आईओसीसी दर्जा पाने का प्रयास कर रही है। मई, 2026 में उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शेयरधारकों की आवश्यक मंजूरी नहीं मिली थी। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर स्विगी को आईओसीसी का दर्जा मिल जाता है, तो उसे इंस्टामार्ट को सीधे इन्वेंट्री रखने की अनुमति मिल सकती है। एजेंसी

अमर उजाला **Job Alert**
Real-time job alerts amarujala.com/jobs

इंडियन ओवरसीज बैंक

अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें आवेदन

750 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 20 जुलाई, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : iob.bank.in

संघ लोक सेवा आयोग ■ 450 पद

डिप्टी इंजीनियर व जूनियर इंजीनियर के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 17 जुलाई, 2026
योग्यताएं : पोस्ट-ग्रेजुएशन, लॉ व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : upsc.gov.in

कर्मचारी चयन आयोग ■ 341 पद

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 16 जुलाई, 2026
वेतनमान : रुपये 44,900 से लेकर रुपये 1,42,400 तक
यहां आवेदन करें : ssc.gov.in

एनएचएसआरसीएल में मौके ■ 237 पद

टेक्नीशियन के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 05 अगस्त, 2026
योग्यताएं : दसवीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : nhsrcl.in

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ■ 95 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जुलाई, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : isro.gov.in

मंत्रिमंडल सचिवालय में मौके ■ 25 पद

सीनियर फील्ड ऑफिसर के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 12 जुलाई, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : cabsec.gov.in

विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी...

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली : प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का पद रिक्त।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 20 जुलाई, 2026
■ aiims.edu

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद , नई दिल्ली : सीनियर रिसर्च एसोसिएट आदि के पद खाली।
■ वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 15 जुलाई, 2026
■ ncert.nic.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

सपने तभी सच हो सकते हैं, जब आप में उन्हें पूरा करने का साहस हो।

जब आप कॉलेज में नए हों

थोड़ी घबराहट तो स्वाभाविक है, लेकिन सक्रिय रहें, सवाल पूछें और हर समय सीखने की कोशिश करते रहें

लियो एम लैम्बर्ट
प्रोफेसर, एलन यूनिवर्सिटी

कॉलेज जीवन की शुरुआत हर छात्र के लिए एक नया और महत्वपूर्ण अनुभव होती है। यह वह समय होता है, जब व्यक्ति अपने परिचित वातावरण से निकलकर एक बिल्कुल नए माहौल में कदम रखता है, जहां नए लोग, नई सोच, नई पढ़ाई की शैली और नई जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। ऐसे में, उत्साह के साथ-साथ थोड़ी घबराहट और अनिश्चितता महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि छात्र स्वयं पर भरोसा रखें और खुद को धीरे-धीरे इस नए वातावरण में ढालें।

■ **शिक्षकों से करते रहें बात**
विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अच्छा संवाद बेहतर सीखने की आधारशिला है। नए छात्रों को प्रोफेसरों से बात करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कक्षा से पहले या बाद में परिचय देना, ऑफिस आवर में मिलना या ऑनलाइन मार्गदर्शन लेना अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत है। ऐसे संबंध विषय की समझ बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में शोध, सिफारिश पत्र और कॅरिअर मार्गदर्शन में भी सहायक होते हैं।

■ **नए दोस्त बनाएं**
कॉलेज का पहला वर्ष नए मित्र बनाने और मजबूत संबंध विकसित करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। कक्षा के बाद कुछ समय सहपाठियों से बातचीत करें, नोट्स साझा करें और असाइनमेंट या विषय से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करें। इससे आप एक-दूसरे से सीखते हैं और पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। समूह में अध्ययन करने से विषय की समझ गहरी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा का तनाव कम होता है। अच्छे मित्र हर चुनौती में सहयोग करते हैं और कॉलेज जीवन को अधिक सहज बना देते हैं।

■ **अनुभव एकत्रित करें**
कॉलेज केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। 'रिलेशनशिप एक्सीलरेटर' वे अनुभव होते हैं, जो कक्षा में सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। इनमें इंटर्नशिप, स्नातक शोध, लेखन-प्रधान सेमिनार, विदेश अध्ययन कार्यक्रम और कैंपस प्लेसमेंट जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ऐसे अनुभव छात्रों को व्यावहारिक कौशल सिखाते हैं और उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए कैंपस में किसी नौकरी के दौरान आपका पर्यवेक्षक आपकी क्षमताओं को पहचानकर आपको नई जिम्मेदारियां दे सकता है। कई बार दूसरे लोग हममें वे संभावनाएं देख लेते हैं, जिन्हें हम स्वयं नहीं पहचान पाते। ये अवसर व्यक्तित्व को निखारते हैं और भविष्य के लिए बेहतर रूप से तैयार करते हैं।

- *इस समय सबसे जरूरी है स्वयं पर भरोसा रखना और आत्मविश्वास बनाए रखना।*
- *सकारात्मक सोच से शुरुआती चुनौतियां आसान हो जाती हैं।*
- *प्रोफेसरों, स्टाफ और सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध भविष्य में मदद करते हैं।*

■ **खुद से जुड़ें**
नए छात्रों को अक्सर 'इम्पोस्टर सिंड्रोम' का अनुभव होता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें सक्षम और योग्य होने के बावजूद व्यक्ति स्वयं को कमतर समझने लगता है। यह भावना सामान्य है और समय के साथ दूर हो सकती है। सबसे पहले, अपनी पहचान और अपने गुणों को याद रखें। आपने यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत की है, इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें। यदि किसी विषय में कठिनाई हो या मन में संदेह उत्पन्न हो, तो प्रोफेसर या मित्र से खुलकर बात करें। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। **-द कन्वर्सेशन**

फेलोशिप प्रोग्राम

हार्वर्ड रैडक्लिफ फेलोशिप

- पात्रताएं : इसमें दुनिया भर के स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट और प्रैक्टिशनर शामिल हो सकते हैं।
- उद्देश्य : लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स पर गहराई से काम करने का मौका देना।
- स्टाइपेंड : 78,000 डॉलर
- अंतिम तिथि : 01 अक्तूबर, 2026
- आवेदन लिंक : tinyurl.com/5kefeexr

आवेदन आमंत्रित

यूआईडीएआई इंटर्नशिप प्रोग्राम

- पात्रताएं : पीएचडी/रिसर्च
- डोमेन/क्षेत्र : बायोमेट्रिक डोमेन व ह्यूमन रिसोर्स
- स्टाइपेंड : डोमेन के अनुसार रुपये 40,000 व रुपये 50,000
- अवधि : छह माह
- आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जुलाई, 2026
- आधिकारिक लिंक : tinyurl.com/3zckc39c

एग्जाम अलर्ट

एमपीईएसबी पीएनएसटी-2026

- परीक्षा की तिथि : 10 जुलाई, 2026
- इस परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, जनरल इंग्लिश और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे। प्रश्नों को हल करने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें tinyurl.com/4yzz5wje

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-II परीक्षा

- परीक्षा की तिथि : 10 जुलाई, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य जागरूकता, गणित और सामान्य बुद्धिमत्ता व तर्कशक्ति विषयों से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई नकारात्मक अंकन का प्रावधान है।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें tinyurl.com/3f2w3czc

वीकली जीके

1. हाल ही में खबरों में रहा त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है?
(a) महाराष्ट्र (b) कर्नाटक
(c) केरल (d) तमिलनाडु

2. मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है?
(a) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(b) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
(c) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(d) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

3. भव्य योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी?
(a) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(b) भारी उद्योग मंत्रालय
(c) एमएसएमई मंत्रालय
(d) वित्त मंत्रालय

4. 2026 पशुजन्य युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था?
(a) मध्य प्रदेश
(b) गुजरात
(c) कर्नाटक
(d) राजस्थान

उत्तर : 1.a, 2.c, 3.a, 4.a

8 जुलाई, 1994

आज का दिन

चियाकी मुकाई अमेरिकी अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के एसटीएस-65 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली जापान की पहली महिला यात्री बनीं।

■ 1972 : भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सौरव गांगुली का जन्म हुआ था।
■ 1996 : ब्रिटिश पॉप बैंड 'स्पाइस गर्ल्स' ने अपना पहला एकल गाना 'वानाबी' रिलीज किया था।
■ 2000 : वीनस विलियम्स ने पहली बार विंबलडन जीता था।
■ 2020 : भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी।
कल: वर्षा ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 13.30 से 15.00 तक।

■ सूर्योदय : 05.35
■ सूर्यास्त : 19.17
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 18 आषाढ़ मास शक 1948, आषाढ़ मास 25 प्रविष्टे, 23 मुहर्रम हिजरी 1448, आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी 10.37 तक उपरांत दशमी, अश्विनी नक्षत्र 14.55 तक उपरांत भरणी नक्षत्र, सुकर्मा योग 10.11 तक उपरांत धृति योग, गर करण 10.37 तक उपरांत वणिज करण, चंद्रमा मेष राशि में दिन-रात।

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : मानसिक तनाव बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र में सेवारत जातक सावधानी बरतें। अकारण वाद-विवाद से बचें।

वृष : सामाजिक क्षेत्र में रुचि रहेगी। आय का नया साधन बन सकता है। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा।

मिथुन : राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। अटका धन मिल सकता है। नौकरी में धैर्य बनाए रखें।

कर्क : अटके कार्य में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी। नौकरी का अवसर मिल सकता है।

सिंह : प्रभावी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। अजनबी पर भरोसा करने से बचें।

कन्या : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में कार्य कुशलता का लाभ मिलेगा। यात्रा में परेशानी होगी।

तुला : आरोग्य सुख मिलेगा। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। उद्देश्य प्राप्ति में सफल रहेंगे। विरोधी शांत रहेंगे।

वृश्चिक : बल और साहस में वृद्धि होगी। विकास के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे।

धनु : नए कार्य में व्यस्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र में चली आ रही परेशानियों में कमी आएगी। नौकरी में स्वयं पर भरोसा रखें।

मकर : मन में आशा का संचार होगा। नौकरी में उन्नति हो सकती है। किसी परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

कुंभ : आत्मबल बनाए रखें। नौकरी में उन्नति का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

मीन : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

सुडोकू

5	9			6			1	
		2		5			9	
6		7			1			3
	2					3		
8				9				4
		9					5	
9			5			8		1
	1			4		6		
	8			1			4	5

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

5	9	8	3	6	4	7	1	2
1	3	2	7	5	8	4	9	6
6	4	7	9	2	1	5	8	3
7	2	1	4	8	5	3	6	9
8	5	3	6	9	2	1	7	4
4	6	9	1	7	3	2	5	8
9	7	4	5	3	6	8	2	1
2	1	5	8	4	9	6	3	7
3	8	6	2	1	7	9	4	5

प्रेरणा

जिंदगी तो बहुत आसान है, लेकिन इसे हम कठिन बनाने में लगे रहते हैं। - **कन्फ्यूशियस**

संपादकीय

इथेनॉल के लिए मक्का एक बेहतर विकल्प होगा

देश में चावल बहुत मात्रा में है- दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा निर्यात, इस साल कुल पैदावार 154 मिलियन टन। खाने, फ्री बांटने और निर्यात करने के बाद भी रिजर्व लेवल से चार गुना बच जाता है। लिहाजा सरकार ने पर्यावरण, तेल संकट और सस्ता देशी विकल्प तलाशने के ध्येय से 20% ई-ब्लेंडिंग शुरू की। लेकिन नीतिकारों ने यह नहीं सोचा कि चावल पैदा करने की परोक्ष और प्रत्यक्ष कीमत और पर्यावरणीय क्षति कितनी होती है। एक किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी खर्च होता है। इसका आधा तो एक्विफायर सिस्टम में वापस हो जाता है लेकिन बाकी बर्बाद हो जाता है। इसके लिए खाद, बिजली और राज्यों द्वारा दी गई एक्स्ट्रा सब्सिडी जोड़ ली जाए तो यह बेहद महंगा पड़ता है। दूसरा कारण है धान बोने की गलत (पुनर्रोपण) विधि और समतल रोपाई, जिससे पानी पौधे से ज्यादा जमीन में जाता है। ऐसे में अनाज से बायोफ्यूल बनाने के लिए मक्का बेहतर विकल्प हो सकता है। गन्ने से भी एथेनॉल बनाना सही विकल्प नहीं, क्योंकि इसमें भी पानी का दोहन बहुत होता है। गन्ना महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा पैदा करते हैं, जहां पानी का स्तर पहले ही काफी नीचे है। बिहार, बंगाल, यूपी गन्ने के उत्पादन के लिए बेहतर राज्य हैं, लेकिन चीनी मिलें लगीं हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में। वहीं मक्का पैदा करने में एमपी, बिहार और कर्नाटक आगे हैं लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन बिहार, आंध्र, बंगाल में ज्यादा है। अन्य राज्यों को भी मक्का की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अकेलेपन को एकांत में बदल देने में सक्षम है योग

अकेलापन और भविष्य का भय युवाओं को कॉर्पोरेट जगत में और बड़े-बूढ़ों को परिवार में सता रहा है। जिन्होंने नौकरी, कारोबार की दुनिया में खूब सुख और धन अर्जित किया, उनके चेहरे पर भी इसकी झलक मिलती है। और परिवार में बड़े-बूढ़ों के जीवन में अकेलापन ऐसा उतरा कि वृद्धावस्था घोर पीड़ा लगने लगी। दुनियादारी की भाषा में एक शब्द चलता है 'सोशल कैपिटल'। इसे यूं समझें कि जब लोग आपस में मिलें, एक-दूसरे पर भरोसा रखें, साथ समय बिताएं, तो उस अदृश्य शक्ति को सोशल कैपिटल कहते हैं। देश में लगातार कई क्षेत्रों में खूब विकास हो रहा है, लेकिन सोशल कैपिटल धीरे-धीरे खत्म हो रही है- यह बात जानकार लोग मानने लगे हैं। तो यदि हमारे-आपके जीवन में सोशल कैपिटल खत्म होने की तकलीफ दिख रही है तो निदान भी हमें निकालना पड़ेगा। व्यावहारिक निदान यह है कि मेलजोल बढ़ाइए। दूसरों में पॉजिटिव रुचि लीजिए। कोई न कोई रचनात्मक कार्य हाथ में लेकर उससे जुड़ जाएं। और आध्यात्मिक इलाज यह है कि अपने अकेलेपन को एकांत में बदलिए, और यह काम होगा योग से। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

अच्छा आदमी

अरे सुना क्या?

मथुरा के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं
और आगरा के पेठे के तो क्या कहने
और दिल्ली की परांठे वाली गली तो आहाहा

और हां-
बंगाल के रसगुल्ले भी कमाल ही होते हैं
और नागपुर के संतरे भी लाजवाब
और बनारस का पान तो बहुतई अच्छा

और आदमी कहां का अच्छा होता है जी?

जी आदमी तो
कहीं का अच्छा नहीं होता
सब जगह के बेस्वाद ही हैं जी!

हमें ही डालना पड़ता है-
नमक, मसाला, चाशनी, तेल
पैसा, दोस्ती,
प्यार, चापलूसी....
-विनायक दुबे, भोपाल
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

बिना टिकट यात्रा पर सख्ती हो

भारत में रोजाना लगभग 20 लाख यात्री रेल यात्रा करते हैं। इनमें से हजारों लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे भारतीय रेल को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय रेल को इस समस्या पर सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि उचित समाधान निकल सके। **-राजवीर सारस्वत,** जोधपुर, राजस्थान

जल-प्रबंधन में लोगों की भागीदारी जरूरी

डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में लगभग 220 करोड़ लोग दूषित पेयजल पीने को विवश हैं। इससे लाखों लोगों की जान जा रही है। प्रभावी जल प्रबंधन का अभाव और लापरवाही इसका मूल कारण है। केवल सरकार पर निर्भर रहने के बजाय जनभागीदारी से ही प्रभावी जल-प्रबंधन संभव है।
-ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा, मध्यप्रदेश

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

भूकम्प को भांपकर खुद ही रुक जाती हैं ट्रेनें

जापान का शिंकान्सेन बुलेट ट्रेन सिस्टम इतना सुरक्षित है कि बीते साठ वर्षों में इसके ट्रैक पर किसी हादसे में एक भी यात्री की मौत नहीं हुई है। भूकंप जोखिम वाले जापान में यह सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि धरती में हल्की-सी हलचल को भांपते ही ट्रेनें अपने-आप रुक जाती हैं।
10 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं इन ट्रेनों से।

बामुलाहिज़ा • जबकि अतीत में इसका कोई नेता ऐसा नहीं हुआ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में कमजोर रहा हो...

कांग्रेस ने राष्ट्रवाद के मुद्दे से दूरी क्यों बनाई?

नेशन फर्स्ट

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
X @ShekharGupta

राष्ट्रीय राजनीति में फिलहाल जो मंथन चल रहे हैं, उसके दो पहलू हैं। एक यह कि लोकसभा में अल्पमत में होने के बावजूद भाजपा ने भारत को लगभग एक पार्टी के शासन वाला देश बनाने का चमत्कार कर डाला है। और दूसरा यह कि यह काम क्षेत्रीय दलों को तोड़कर किया जा रहा है और अब कांग्रेस ही एकमात्र महत्वपूर्ण साबुत विपक्षी पार्टी बची है। इस तरह भारतीय राजनीति दो-दलीय समीकरण में तब्दील हो गई है।

यह बिलकुल सरल और सीधा समीकरण होना चाहिए था, बशर्ते कांग्रेस दमदार चुनौती के रूप में सामने होती। लेकिन भाजपा के खिलाफ केवल 10 फीसदी मुकाबले में जीत हासिल करने की दर के बूते वह ऐसा नहीं कर सकती। वैसे, दो दलीय व्यवस्था तो भाजपा को बिलकुल मुफीद होगी, क्योंकि उसे केवल ताकतवर क्षेत्रीय दलों से मुकाबले में मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसे अधिकतर दल कमजोर किए जा चुके हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का इम्तिहान आगामी मुकाबले में योगी से हो जाएगा।

अब 3 सवाल उभरते हैं। पहला : भाजपा को कांग्रेस इतनी सुविधाजनक प्रतिद्वंद्वी क्यों लगती है? दूसरा : कांग्रेस में क्या कमी है कि वह विश्वसनीय चुनौती नहीं बन सकती? तीसरा : कांग्रेस खुद को कैसे उबारे? पहले सवाल का जवाब बहुत आसान है : भाजपा चार इंजिन के बूते उड़ान भर रही है- हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जनकल्याण के कार्यक्रमों का कुशल क्रियान्वयन और सबकी नजरों में आने वाले भारी-भरकम इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास। कांग्रेस के पास इन सबका कोई विश्वसनीय जवाब नहीं है, यह दूसरे सवाल का जवाब दे देता है। कांग्रेस के मुताबिक, भाजपा जो कर रही है वह गलत है, तो सवाल उठता है वह खुद सत्ता में आने के बाद क्या करेगी?

अर्थव्यवस्था, रणनीतिक मसलों और डिफेंस के मोर्चों पर कांग्रेस भाजपा से अलग क्या करेगी? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और पश्चिम एशिया से वह कैसे निबटेगी? प्रतिरक्षा पर वह किस तरह खर्च करेगी? भाजपा के विकल्प के तौर पर भविष्य का उसका क्या खाका है? भाजपा अगर उसके मुताबिक पूंजीवादी है और राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर रही है, तो वो ऐसा क्या करेगी, जो अलग होगा? अगर कांग्रेस खुद को एक विकल्प मानती है, जिसे मतदाता भाजपा के बदले चुनेंगे, तो वह अलग क्या पेश कर रही है?

कांग्रेस को पहले इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। इसके अलावा, हमने भाजपा की उड़ान को ऊंचाई देने वाले जिन चार इंजिनों का जिक्र किया था उनका जवाब ढूंढना होगा। सबसे पहले तो हिंदुत्व को ही लें। कांग्रेस को इस मोर्चे पर भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश तक नहीं करनी चाहिए। यह जमीन जीती जा चुकी है और कांग्रेस उसमें कोई टूट-फूट नहीं कर सकती, चाहे उसके नेता कितने ही मंदिरों के दर्शन कर लें। शिवसेना तक ने यह कोशिश छोड़ दी है। वास्तव में, उद्धव ठाकरे ने कुछ दार्शनिक अंदाज से मुझसे एक बार कहा भी था कि उनके पिता ने महाराष्ट्रवाद के मुद्दे को छोड़ हिंदुत्व को अपनाकर गलती की, क्योंकि इसने भाजपा को शिवसेना की जमीन पर कदम रखने और उस पर कब्जा करने का मौका दे दिया।

जनकल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी दुनिया मुट्ठी में देने का वादा कर सकती है। ऐसा उसने कर्नाटक और तेलंगाना में करके सफलता हासिल की। इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इतने सालों से वह कई बड़ी परियोजनाओं का विरोध करती दिखी है, निकोबार की परियोजना ताजा मिसाल है। तो धर्म का मुद्दा उसकी पहुंच से परे है, जनकल्याण/विकास का मुद्दा इतना निर्विवाद है कि उसमें भावनात्मकता नहीं जोड़ी जा सकती। सो, कांग्रेस के लिए ले-देकर राष्ट्रवाद का मुद्दा ही बचता है।

कांग्रेस ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को किस तरह खारिज किया है, यह 2014 के बाद की उसकी सियासत का सबसे रहस्यमय पहलू है। उसके कुछ नेता आज भले ही यूरोप के पर्यावरणवादी नेताओं जैसे दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन असली कांग्रेस खून के आंसू रोने वाले शांतिवादियों की पार्टी कभी नहीं रही है। यह वह पार्टी रही है, जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और लाल बहादुर शास्त्री के राज में 1965 की जंग इस लिहाज से जीती कि उसने कश्मीर को हड़पने के इरादे से हमला करने वाले पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया था।

कांग्रेस चाहे तो राष्ट्रवाद पर एक बहस छेड़ सकती है

भारतीय राष्ट्रवाद हमारे इतिहास, आजादी के आंदोलन और संविधान के बारे में साझा भावनाओं से उभरा है। भाजपा ने इसका हिंदूकरण कर दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस बहस उठा सकती है। लेकिन अगर उसने अपना वर्तमान रवैया जारी रखा, तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा।

कांग्रेस ने उत्तर-पूर्व के बागियों से भी क्रूरता के साथ मुकाबला किया, 5 मार्च 1966 को आइजोल की घेराबंदी किए बागियों को सरकारी खजाने पर कब्जा करने, असम राइफल्स की बटालियन के मुख्यालय और डिप्टी कमिश्नर के निवास पर कब्जा करने से रोकने के लिए वायुसेना के विमानों को रवाना किया। ऑपरेशन ब्लूस्टार के तहत उसने सेना को स्वर्ण मंदिर में भेज दिया था। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी किया था।

पहले दो ऑपरेशन इंदिरा गांधी के दौर में और अंतिम दो ऑपरेशन उनके पुत्र राजीव गांधी के दौर में किए गए। इसके बाद कांग्रेस ने कश्मीर घाटी और पंजाब (1991-95) में आतंकवाद और अलगाववाद के सबसे खूनी दौर का मुकाबला किया। यह पीवी नरसिंह राव के समय में किया गया। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू के दौर में भी नगा बागियों के साथ सबसे कठोर तरीकों से लड़ाई लड़ी गई। नेहरू ने गोवा को मुक्त कराने के लिए सेना भेजी थी। कांग्रेस अपने उन प्रधानमंत्रियों को भले न पसंद करे, जो नेहरू परिवार से नहीं थे, लेकिन हकीकत यही है कि उसका कोई नेता ऐसा नहीं हुआ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कमजोर रहा हो। इसलिए भी आश्चर्य होता है कि राष्ट्रवाद वाली मूल पार्टी रास्ता कैसे भूल गई।

चाहे उरी कांड के बाद 'सर्जिकल स्ट्राइक' हो या पुलवामा कांड के बाद बालाकोट पर हवाई हमला या पूर्वी लद्दाख/गलवान में संकट या ऑपरेशन सिंदूर- कांग्रेस ने सब पर सवाल खड़े करके और सबूतों की मांग करके अपना ही नुकसान किया। ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर संसद में राहुल गांधी के बयान में ज्यादा जोर इस बात पर था कि भारत ने कितने विमान गंवाए और क्यों। उनकी पार्टी के पंजाब के एक सांसद ने तो भारतीय वायुसेना के मार गिराए गए विमान का एक टुकड़ा तक प्रदर्शित किया। इस सबको कितना 'स्मार्ट' कदम कहा जाएगा? **(ये लेखक के अपने विचार हैं।)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

विश्लेषण • अफगानिस्तान से मिल रही है चुनौती

पश्चिमी सीमा पर अनवरत संघर्ष में उलझ चुका है पाक

भू-राजनीति

सैयद अता हसनैन
बिहार के राज्यपाल और कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का नाटकीय कब्जा हुआ तो लगा कि पाकिस्तान अपने भू-राजनीतिक प्रयासों में सफल हो गया। पाकिस्तान ने चार दशकों से अधिक समय तक राजनीतिक पूंजी, खुफिया संसाधन और सैन्य प्रयास इस बात के लिए खर्च किए थे, ताकि अफगानिस्तान में रणनीतिक बढ़त हासिल कर सके। पर्यवेक्षकों को लग रहा था कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में पकड़ मजबूत करेगा, पश्चिमी सरहद सुरक्षित करेगा और रणनीतिक तौर पर अपना ध्यान भारत की ओर फिर से केंद्रित करेगा। लेकिन पांच साल से भी कम समय में घटनाक्रम ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एक शत्रुतापूर्ण सरकार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की अगुवाई में उग्रवादी हिंसा और सीमा पर बिगड़ती सुरक्षा-व्यवस्था झेलनी पड़ रही है। सवाल यह है कि सबसे बड़ी भू-राजनीतिक सफलता हासिल करने के तत्काल बाद ही पाकिस्तान ने रणनीतिक नियंत्रण कैसे खो दिया?

इसकी जड़ में एक सदी से चला आ रहा उस डूरंड रेखा से जुड़ा विवाद है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 1893 में निर्धारित किया गया था। पश्तून जनजातीय क्षेत्रों को विभाजित करने वाली यह विवादित सीमा समान जातीय पहचान वाले समुदायों को भी बांटती है। अफगान सरकारों ने भी इस सीमा को स्वीकार नहीं किया। वास्तव में 1947 में अफगानिस्तान ही इकलौता देश था, जिसने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिए जाने का विरोध किया था। पाकिस्तान को भरोसा था कि दशकों तक उसने तालिबान को समर्थन दिया है तो इसके चलते उसकी सरकार अंततः डूरंड रेखा को स्वीकार लेगी। लेकिन उसका आकलन गलत साबित हुआ। इस्लामिस्ट होने के बावजूद तालिबान पर पश्तून राष्ट्रवाद का भी प्रभाव है। ऐसे में पाकिस्तानी दावों को स्वीकारना उसकी घरेलू वैधता को गंभीर रूप से कमजोर करता है।

दशकों तक तालिबान कमांडरों पर पाकिस्तान की आईएसआई का दबदबा रहा, क्योंकि नाटो के खिलाफ विद्रोह के दौरान वे पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकानों पर निर्भर थे। लेकिन जब कोई उग्रवादी आंदोलन सत्ता हासिल कर ले तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। अगस्त 2021 से पहले तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद स्थिति उलट गई और पाकिस्तान को तालिबान की जरूरत पड़ने लगी। पाकिस्तान इस अहम बदलाव को समझने में विफल रहा। तालिबान के सत्ता हासिल करने के तुरंत बाद पाकिस्तान के खुफिया चीफ की हाई-प्रोफाइल काबुल यात्रा इसी भटके हुए आत्मविश्वास का प्रतीक थी। और यहीं से हालात के आकलन में एक बड़ी भूल की शुरुआत हुई।

इस बदलाव का सबसे पहला परिणाम यह रहा कि टीटीपी फिर से सिर उठाने लगा। भले टीटीपी अफगान तालिबान से अलग संगठन है, लेकिन वह तालिबान के साथ अपनी वैचारिक जड़ें, जनजातीय संबंध साझा करता है। सीमापार युद्धक्षेत्रों में दोनों संगठनों के आपसी सहयोग का लंबा इतिहास है। सत्ता में लौटने के बाद अफगान तालिबान ने तेजी से टीटीपी के लिए सुरक्षित ठिकानों का विस्तार किया। वैचारिक एकजुटता के कारण तालिबान सरकार के लिए यह कठिन है कि वह महज पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए अपने साथी इस्लामिस्ट लड़ाकों पर कार्रवाई करे।

पाकिस्तान की आतंकवादियों को 'अच्छे' और 'बुरे' में श्रेणीबद्ध करने वाली नीति की कलई खुल चुकी है। दशकों तक पाकिस्तान ने उन आतंकी संगठनों को समर्थन दिया है, जो अफगानिस्तान और भारत में उसके रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करते थे।

पाकिस्तान द्वारा अफगान नीति को डिक्टेट करने की कोशिशों को लेकर भी असंतोष बढ़ा है। पाकिस्तान के सीमापार हमलों ने अविश्वास को और गहरा किया, जिससे टीटीपी की पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल बन गया। जैसे-जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते गए, भारत ने अपना महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रभाव फिर से हासिल कर लिया है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा • इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री

'डिजिटल इंडिया' में बच्चों की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी

डिजिटल

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील
viraggupta@hotmail.com

बच्चों के यौन शोषण के मामले में यूपी के एक जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी को विशेष अदालत ने फरवरी 2026 में फांसी की सजा सुनाई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम ने भी धन लेकर रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के माध्यम से बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को भारत में बढ़ावा दिया है। पर इस पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय सरकार ने मेटा कम्पनी से एक सप्ताह में जवाब भर मांगा है। इस मामले से जुड़े 5 पहलुओं की समझ जरूरी है।

1. बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए मई 2017 में महिला एवं बाल विकास, गृह, कानून, आईटी, विदेश और दूरसंचार मंत्रालय की अंतर-मंत्रालय समिति का गठन हुआ था। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के राज्यसभा में दिए जवाब के अनुसार सोशल मीडिया में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रसार पॉक्सो, आईटी और बीएनएस कानूनों के अनुसार गम्भीर अपराध है। दोषियों को सजा के लिए 774 फास्टट्रैक अदालतों का गठन हुआ है।

2. नीट में पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम पर रोक लगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने कहा था कि टेलीग्राम से नकल माफिया, आतंकवाद, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। फेसबुक, वॉट्सएप और इंस्टाग्राम के 154 करोड़ ग्राहकों वाला भारत मेटा कंपनी के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में यौन शोषण के संगठित अपराध से बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाने वाली मेटा पर भारी जुर्माने के साथ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।

3. बच्चों के यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ईयू में टेक कम्पनियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के साथ जुर्माना वसूलने के मामले चल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वॉट्सएप में सिम बाइंडिंग होने से साइबर अपराधों में कमी आएगी। लेकिन टेक कम्पनियों की लॉबीइंग के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने नियम पालन की समय-सीमा बढ़ा दी। फरवरी 2026 में आईटी इंटरमीडियरी नियमों में हुए बदलावों के अनुसार इंस्टाग्राम वाले मामले में 2 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के बजाय उसे जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

4. विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसुस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने डिजिटल जगत में बच्चों को बचाने के लिए अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट के 23 अगस्त 2013 के आदेश के अनुसार 13 से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया जॉइन नहीं कर सकते। 2021 में ट्विटर के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस की एफआईआर के साथ दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी हुआ था। भारत के नियमों का पालन नहीं करने वाली टेक कंपनियों की सेफ हार्बर की सुरक्षा खत्म करने के लिए आईटी मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने अक्टूबर 2023 में संसद में बयान दिया था। उसके अनुसार इंस्टाग्राम के नामांकित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

फेसबुक, वॉट्सएप और इंस्टाग्राम के 154 करोड़ ग्राहकों वाला भारत मेटा कंपनी के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में यौन शोषण के संगठित अपराध से बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाने वाली मेटा पर भारी जुर्माने के साथ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।

5. बांदा के इंजीनियर दम्पती को फांसी की सजा देते हुए बाल यौन शोषण अपराध को जज ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा था। पॉक्सो में दर्ज हजारों मामलों में लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली के 16600 स्कूलों और आंगनबाड़ी में बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम, उसके विज्ञापनदाता और चाइल्ड पोर्नोग्राफी सम्बंधी वीडियो का प्रसार करने वाले संगठित अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मामला तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने के साथ कानून के शासन की भी बुनियाद कमजोर हो रही है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • पर इसके लिए दुनिया के शीर्ष धनकुबेरों पर टैक्स लगाना होगा, जो राजनीतिक रूप से कठिन है...

99% आबादी की समस्याओं को 1% 'सुपर-रिच' हल कर सकते हैं

वेलफेयर

ज्यां द्रेज़
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री

हाल ही में पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट है। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब एक शोध-समूह है, जिसका नेतृत्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी करते हैं। इस रिपोर्ट में आज दुनिया के सामने मौजूद दो गंभीर संकटों- जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विषमता से निपटने की बात की गई है।

जलवायु परिवर्तन तो हमारे अस्तित्व के लिए ही एक गंभीर खतरा है। पृथ्वी हर साल गर्म होती जा रही है। औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में पृथ्वी का तापमान अब तक 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। गर्मी बढ़ने की मौजूदा गति से यह जल्द ही 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुछ क्षेत्रों में तो तापमान 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। तब भारत में बिहार और यूपी जैसे इलाकों में जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करके उनकी जगह पवन और सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। यह संभव है, लेकिन इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। अमीर और गरीब देश इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि इसका खर्च किस तरह बांटा जाए।

दुनिया के सामने एक और बड़ा संकट आर्थिक असमानता का बढ़ना है। एक छोटा-सा वर्ग बेहद अमीर हो गया है और उसकी संपत्ति हर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया में लगभग 3,000 लोगों के पास एक अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति है। यह बहुत बड़ी रकम होती है- लगभग 10,000 करोड़ रुपए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की संपत्ति तो ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। यह 100 लाख करोड़ रु. के बराबर है।

अत्यधिक केंद्रित धन लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। अति-अमीर लोग मीडिया, राजनीतिक दलों, चुनावी नतीजों और सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। जब सरकारी नीतियों पर उनकी पकड़ होती है, तो वे उन्हें अपने फायदे के हिसाब से मोड़ देते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों से मुनाफा कमाने के लिए पर्यावरण संबंधी नियमों को कमजोर करते हैं। यह प्रक्रिया अमेरिका में साफ दिखाई देती है। भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है।

ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट इन दोनों संकटों- ग्लोबल वार्मिंग और आर्थिक असमानता से बचने की योजना पेश करती है। इस योजना का मुख्य आधार एक ग्लोबल जस्टिस फंड है, जिसे वैश्विक धन-कर (ग्लोबल वेल्थ टैक्स) से वित्तपोषित किया जाएगा। इसके तहत 20 लाख डॉलर से अधिक संपत्ति वाले हर व्यक्ति को धन-कर देना होगा। यह 1% प्रति वर्ष से शुरू होगा और धीरे-धीरे बढ़कर उन लोगों के लिए 20% तक पहुंच जाएगा, जिनकी संपत्ति 50 करोड़ डॉलर से अधिक है।

ग्लोबल जस्टिस फंड का उपयोग इस तरह किया जाएगा कि दुनिया के सभी देश 2100 तक नई आर्थिक व्यवस्था तक पहुंच सकें। इस व्यवस्था में सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय आज के अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के आसपास होगी। काम के घंटे घटाकर रोज केवल तीन या चार घंटे कर दिए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बड़ा विस्तार होगा। और ऊर्जा परिवर्तन की मदद से ग्लोबल वार्मिंग का अंत हो जाएगा।

चौंकाने वाली बात है कि 1% से भी कम आबादी वाले अति-अमीर लोगों पर कर लगाकर इतना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कई लोग कहेंगे कि इसे राजनीतिक रूप से लागू करना संभव नहीं है। लेकिन अगर यह योजना दुनिया की 99% आबादी के लिए फायदेमंद है, तो इसे राजनीतिक रूप से लागू करना मुश्किल क्यों है? कारण, बाकी 1% लोग बहुत प्रभावशाली हैं। वे वैश्विक धन कर को लागू नहीं होने देंगे। यही आज की दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भास्कर एक्सप्लेनर सेंसेक्स के कमजोर प्रदर्शन के बीच नए शेयरों में रैली

6 महीने में आए 27 आईपीओ, इनमें 74% मुनाफे में, 124% तक रिटर्न

...पर औसत लिस्टिंग गेन 7 साल में सबसे कम 1.3%

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर बाजार सेंटीमेंट के बीच भी भारत के प्राइमरी मार्केट ने दम दिखाया है। 2026 की पहली छमाही में (6 जुलाई तक) 27 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए कुल ₹22,572 करोड़ से ज्यादा जुटाए। जिनमें से 20 कंपनियां यानी करीब 74% के शेयर अभी इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

हालांकि इस साल अब तक आए आईपीओ के औसत लिस्टिंग गेन घटकर सिर्फ 1.3% रह गया है, जो पिछले सात वित्त वर्षों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 18-19 के बाद पहली बार यह आंकड़ा इतना कम रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहली छमाही में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स डॉलर के लिहाज से 13% गिर गया, जबकि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 23% चढ़ा है। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार दुनिया के सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले बाजारों में शुमार रहा।

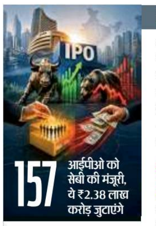

157 आईपीओ को सेबी की मंज़ूरी, ये ₹2.38 लाख करोड़ जुटाएंगे

विदेशियों ने शेयर बेच इश्यू में लगाए पैसे

पुराने शेयरों और आईपीओ बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का रुख अलग-अलग रहा। एनएसडीएल आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-जून 2026 में एफआईआई ने आईपीओ बाजार में ₹21,630 करोड़ लगाए। इसी दौरान लिस्टेड शेयरों से ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा निकाल लिए। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में लगातार बिकवाली के बावजूद इन्होंने चुनिंदा आईपीओ में निवेश जारी रखा।

लिस्टिंग गेन में बड़ा फर्क... -62% से लेकर +124% तक

- 27 नई लिस्टेड कंपनियों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। भारत कोकिंग कोल, सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स, ओम्नीटेक इंजीनियरिंग और एडविट ज्वेल्स जैसी कंपनियों के लिस्टिंग गेन जोरदार (70% से 124%) रहे।
- वाटरवेज लेजर टूरिज्म, इनोविजन, क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस और श्री राम ट्विस्टेक्स की लिस्टिंग कमजोर (-9% से -62%) रही। इसी असमान प्रदर्शन के चलते औसत लिस्टिंग गेन सात साल के निचले स्तर पर आ गया।

यहां रैली... सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 आईपीओ

कंपनी	लिस्टिंग	इश्यू प्राइस	करंट प्राइस	रिटर्न
ओम्नीटेक इंजीनियरिंग	05 मार्च	₹227	₹509	+124.4%
सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स	11 मार्च	₹1,352	₹2,862	+111.7%
ओनईएमआई टेक्नोलॉजी	08 मई	₹171	₹311	+82.0%
शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज	28 जनवरी	₹124	₹225	+81.7%
भारत कोकिंग कोल	19 जनवरी	₹23	₹39	+70.4%

यहां सुस्ती...सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले 5 आईपीओ

कंपनी	लिस्टिंग	इश्यू प्राइस	करंट प्राइस	रिटर्न
श्री राम ट्विस्टेक्स	02 मार्च	₹104	₹40	-61.6%
इनोविजन	23 मार्च	₹519	₹291	-44.0%
अमीर चंद जगदीश कुमार	02 अप्रैल	₹212	₹161	-23.8%
सीएसएम टेक्नोलॉजीज	02 जुलाई	₹113	₹102	-9.7%
टर्टलमिंट फिनटेक	29 जून	₹152	₹138	-9.0%

स्रोत: बीएसई

सप्लाई... ₹3.96 लाख करोड़ के आईपीओ पाइपलाइन में

1. 157 कंपनियों के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी, ये कुल मिलाकर ₹2.38 लाख करोड़ जुटाना चाहते हैं।
2. 77 और कंपनियां नियामकीय मंजूरी के इंतजार में हैं, इनका लक्ष्य कुल मिलाकर ₹1.58 लाख करोड़ जुटाने का है।
3. पाइपलाइन में हेल्थकेयर, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं।

रफ्तार • एक साल में डार्क स्टोर्स डेढ़ गुना, 1 लाख करोड़ का बाजार

झटपट डिलीवरीः पेय पदार्थ, आइसक्रीम और फेस केयर की बिक्री सबसे ज्यादा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश में क्विक कॉमर्स तेजी से पारंपरिक ई-कॉमर्स को पीछे छोड़ रहा है। इक्विरस कैपिटल की जून 2026 कंज्यूमर सेक्टर रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का डिजिटल कॉमर्स बाजार 2026 में 8 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है, जिसमें क्विक कॉमर्स की हिस्सेदारी 1.08 लाख करोड़ रुपए है। सबसे खास बात यह है कि क्विक कॉमर्स सालाना आधार पर 40% की दर से बढ़ रहा है, जो समूचे डिजिटल कॉमर्स की ग्रोथ रफ्तार से दोगुने से भी ज्यादा है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसी प्रमुख कंपनियों के डार्क स्टोर नेटवर्क में पिछले एक साल में भारी इजाफा हुआ है। मई 2025 में इन तीनों कंपनियों के मिलाकर 3,405 डार्क स्टोर थे, जो मई 2026 में बढ़कर 5,026 हो गए। यानी महज एक साल में डार्क स्टोर्स की संख्या करीब डेढ़ गुना बढ़ी है। यह आक्रामक विस्तार बताता है कि कंपनियां छोटे शहरों और नए इलाकों में तेजी से पैर पसार रही हैं, ताकि 10-15 मिनट में डिलीवरी का वादा पूरा किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, इस सीजन में आइसक्रीम, पेय पदार्थ (बेवरेजेज) और फेस केयर उत्पाद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सबसे तेज ग्रोथ दिखाने वाली कैटेगरी रहीं। गर्मी के मौसम में इन उत्पादों की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, लेकिन क्विक कॉमर्स ने इस मांग को तुरंत पूरा करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे पारंपरिक रिटेल चैनलों पर दबाव बढ़ा है।

क्विक कॉमर्सः एक नजर में ग्रोथ

पैरामीटर	मई 2025	मई 2026	वृद्धि
डार्क स्टोर्स	3,405	5,026	48%
साइज	--	₹1.08*	40%

साइज लाख करोड़ में | डार्क स्टोर (ब्लिंकिट + इंस्टामार्ट + जेप्टो)

कमजोर मानसून से ग्रामीण मांग सुस्त पड़ने का खतरा बढ़ा

हालांकि कंज्यूमर सेंटीमेंट के लिए एक चिंता की खबर भी है। रिपोर्ट में बताया गया कि 4 जून से 22 जून के बीच देश में सामान्य 97.6 मिलीमीटर के मुकाबले महज 53.1 मिमी बारिश हुई। यानी 46% की भारी कमी। इससे जून 2026 पिछले 146 वर्षों में सबसे सूखे महीनों में शुमार हो गया है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अल नीनो की स्थितियां और कमजोर मानसून ग्रामीण आय और मांग पर विपरीत असर डाल सकते हैं, जो एफएमसीजी खपत का एक अहम आधार है।

एआई शेयर फिर क्रैश

डीपसीक की चिप के 'डर' से लुढ़का नैस्डैक

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

अमेरिकी शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उथल-पुथल देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर में आई तेजी पर अचानक ब्रेक लगने और सेमीकंडक्टर (चिप) कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के कारण नैस्डैक और एसएंडपी 500 इंडेक्स दबाव में रहे। दिलचस्प है कि दक्षिण कोरियाई दिग्गज कंपनी सैमसंग के बंपर मुनाफे के बावजूद बाजार का मूड खराब रहा। इसकी वजह यह है कि चीनी एआई स्टार्टअप डीपसीक अब अपना खुद का एआई चिप बना रहा है। इस कदम से उसकी एनवीडिया और हुआवे जैसी दिग्गज कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसके चलते एनवीडिया का शेयर 1.8% टूट गया। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 5.5% गिरकर 4 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। रिवियन के शेयर 13.3% टूट गए।

• घरेलू बाजार में 4 दिनों की तेजी थम गई। आखिरी में मुनाफावसूली से सेंसेक्स 104 अंक टूट गया।

एपल के सेफ्टी फीचर्स में बदलाव

डेटा शेयरिंग के लिए यूजर्स की मंजूरी लेगी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

एपल अब अपने नए एआई फीचर्स एपल इंटेलीजेंस को प्रोसेस करने के लिए गूगल क्लाउड पर डेटा भेजने से पहले यूजर्स से अनुमति मांग रहा है। कंपनी ने हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी इवेंट में गूगल के जेमिनाई एआई मॉडल को एकीकृत किया, जिससे फीचर्स तो बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ यूजर डेटा गूगल क्लाउड के साथ साझा करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईओएस 26 और आईओएस 27 में एक नया प्रॉम्प्ट जोड़ा गया, जो यूजर्स से डेटा साझा करने की अनुमति मांगता है। यूजर्स के पास एक बार या हमेशा के लिए अनुमति देने का विकल्प है। आईवर्क एप में शेप जनरेशन फीचर का उपयोग करते समय स्क्रीन पर मेसेज आता हैः 'आकृतियां बनाने के लिए आपका टेक्स्ट गूगल क्लाउड पर भेजा जाएगा। ये डेटा ट्रेनिंग के लिए उपयोग नहीं होगा।' हालांकि एपल ने भरोसा दिलाया है कि गूगल क्लाउड पर उसके 'प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट' आर्किटेक्चर के कारण डेटा सुरक्षित रहेगा।

आखिर क्यों पड़ी जरूरतः एपल ने हमेशा यूजर्स से वादा किया था कि उनका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब कंपनी ने एपल इंटेलिजेंस के लिए एआई मॉडल जेमिनाई से हाथ मिलाया, तो बड़ी चुनौती सामने आई। इन एडवांस फीचर्स को चलाने के लिए यूजर्स का कुछ डेटा गूगल क्लाउड पर भेजना जरूरी हो गया था।

गोल्ड रिजर्व • ऊंची कीमत के बीच केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे निवेश

आरबीआई के सोने की कीमत 11 लाख करोड़ रु., दो साल में दोगुनी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

सोने की कीमतों में उछाल के बीच आम लोग इस एसेट क्लास में निवेश करें या न करें, केंद्रीय बैंक जरूर पैसे लगा रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदारी तेज कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने के भंडार की वैल्यू सिर्फ दो साल में लगभग दोगुनी यानी करीब ₹11 लाख करोड़ हो गई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी एक साल पहले के 12% से बढ़कर 17% हो चुकी है। यह बढ़ोतरी कीमतों और खरीदारी, दोनों की वजह से हुई है। 2024 की शुरुआत में सोना करीब 2,000 डॉलर प्रति औंस था। 2026 में इसकी कीमत बढ़कर 4,000 डॉलर से ऊपर पहुंच गई। रिजर्व बैंक का सोने का भंडार बीते एक दशक में करीब 58% (322.7 टन) बढ़कर 880.5 टन पर पहुंच गया है।

चेक रिपब्लिक ने 3 साल में गोल्ड रिजर्व 5 गुना बढ़ाया, तुर्की का 11 साल में 4 गुना

पोलैंडः जनवरी-मार्च 2023 से जनवरी-मार्च 2026 के बीच सोने का भंडार 228.7 टन से रिकॉर्ड तोड़ 154% बढ़कर 581.6 टन हो गया।

चीनः 2023 से लेकर 2026 के बीच सोने का भंडार 2,068 टन से 12% बढ़कर 2,313 टन हो गया।

चेक रिपब्लिकः बीते तीन वर्षों में सोने का भंडार सिर्फ 13.5 टन से 5 गुना बढ़कर 76.6 टन तक पहुंच गया।

तुर्किएः साल 2015 से लेकर 2026 के बीच सोने का भंडार 116 टन से साढ़े चार गुना बढ़कर भारी-भरकम 535 टन हो गया। यानी आक्रामक खरीदारी का ट्रेंड।

दिलचस्पः दुनिया के उलट अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने हाल के वर्षों में सोने की कोई बड़ी खरीदारी नहीं बढ़ाई है।

रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार 10 साल में 58% बढ़ा

पैरामीटर	आंकड़ा
भारत का गोल्ड रिजर्व मूल्य	₹11 लाख करोड़
रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी	12% से बढ़कर 17%
2024-2026 के बीच दाम बढ़े	100%
आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग	880.5 टन

स्रोत: डब्ल्यूजीसी

बिजनेस ब्रीफ

स्विगी अब बनी भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी

मुंबई| स्विगी में विदेशी हिस्सेदारी मंगलवार को 49.76% रह गई। इसके साथ ही यह फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भारतीय स्वामित्व वाली हो गई। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया कि इससे ओनरशिप या कंट्रोल में बदलाव नहीं आया। इससे पहले सितंबर में विदेशी निवेश लगभग 60% था।

भारत विदेशी निवेश के मामले में 11वां बड़ा देश

नई दिल्ली| भारत 2025 में एफडीआई के मामले में 13वें से 11वें स्थान पर पहुंच गया। अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल एफडीआई 44% बढ़कर ₹3.7 लाख करोड़ हो गया। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस से यह बढ़ोतरी हुई, हालांकि ग्रीनफील्ड निवेश घटा है। चीन चौथे स्थान पर रहा।

कोचीन शिपयार्ड का ओएफएस 3.5 गुना भरा

मुंबई| कोचीन शिपयार्ड का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) पहले दिन 3.52 गुना सब्सक्राइब हो गया। मजबूत मांग को देखते हुए सरकार ने पूरे 2.52% ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल किया। फ्लोर प्राइस 1,400 प्रति शेयर है। रिटेल और कर्मचारी 8 जुलाई को बोली लगाएंगे।

आय उम्मीद से कम, ट्रेंट के शेयर 12.4% टूटे

नई दिल्ली | टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर मंगलवार को 12.4% गिरकर ₹2,928 पर आ गए। कंपनी की उम्मीद से कम ग्रोथ इसकी वजह रही। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की स्टैंडअलोन आय 19% बढ़कर ₹5,666 करोड़ हो गई। जूडियो और वेस्टसाइड के स्टोर विस्तार से यह बढ़ोतरी हुई।

जूलियस बेयर इंडेक्स • दुनिया के सबसे महंगे शहरों की रैंकिंग

सिंगापुर चौथे साल सबसे महंगा शहर; पहली बार एक भी अमेरिकी शहर टॉप-10 में नहीं

एजेंसी | न्यूयॉर्क

सिंगापुर लगातार चौथे साल अमीरों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा। इसकी वजह वहां रिहायशी प्रॉपर्टी और कारों की ऊंची कीमतें हैं। स्विस वेल्थ मैनेजर जूलियस बेयर ग्रुप लिमिटेड की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ज्यूरिख तीन पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। उसने लंदन को पीछे छोड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक का मजबूत होना है। मोनाको पहली बार टॉप-3 में शामिल हुआ। यहां यूरो की मजबूती और महंगी रिहायशी प्रॉपर्टी का असर दिखा। हॉन्गकॉन्ग चौथे और लंदन पांचवें स्थान पर रहे। यह इंडेक्स दुनिया के 25 शहरों में लग्जरी जीवनशैली की लागत की तुलना करता है।

पैमानाः 20 लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं की समीक्षा

इंडेक्स में रिहायशी प्रॉपर्टी, कार, बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, स्कूल फीस और प्रीमियम डिनर समेत 20 लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का विश्लेषण किया गया। फरवरी से मार्च 2026 के बीच 10 लाख डॉलर से अधिक बैंक योग्य संपत्ति वाले 360 हाई नेटवर्थ लोगों का सर्वे किया गया।

मुंबई 22वां सबसे महंगा शहर • सिडनी छह पायदान चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गया। पिछले तीन साल में पहली बार अमेरिका महाद्वीप का कोई भी शहर टॉप-10 में नहीं रहा। वजह अमेरिकी डॉलर की कमजोरी रही। मुंबई 22वां सबसे महंगा शहर है।

3 महीने की सुस्ती टूटी

मई में हवाई यात्री 12% बढ़कर 1.53 करोड़ हुए

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

तीन महीनों की सुस्ती के बाद देश के एविएशन मार्केट ने शानदार वापसी की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक सालाना आधार पर 9.5% बढ़ा है। वहीं, अप्रैल के मुकाबले इसमें 12% की तेजी आई है और यह आंकड़ा 1.53 करोड़ पर पहुंच गया। मई 2025 में यह संख्या 1.40 करोड़ ही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक अप्रैल की तुलना में मई में छुट्टियों के कारण मांग हमेशा मजबूत रहती है। लेकिन सालाना आधार पर दिख रही यह तेजी बेस इफेक्ट की वजह से है। पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर ने हवाई सफर की धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। हालांकि, लंबी अवधि में अब भी सुस्ती है। जनवरी से मई के दौरान घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या महज 1.91% बढ़कर 7.29 करोड़ रही, जो 2025 की समान अवधि में दर्ज 8% से ज्यादा की ग्रोथ के मुकाबले काफी कम है। इंडिगो 64.9% मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बनी हुई है। इस एयरलाइन ने सालाना आधार पर अपनी क्षमता करीब 6% बढ़ाई।

योजना... टू-व्हीलर्स को 5000 तक सब्सिडी, थ्री-व्हीलर्स का कोटा फुल

ईवी मेकर्स को राहत... पीएम ई-ड्राइव स्कीम की समय-सीमा बढ़ सकती है

सुरजीत दास गुप्ता | नई दिल्ली

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) 'पीएम ई-ड्राइव' योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स के बीच हुई बैठक के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए इस योजना को पहले की तय डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर इस साल 31 जुलाई तक कर दिया गया है। कुल 10,900 करोड़ रुपए के बजट वाली इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर अधिकतम 5,000 रुपए प्रति वाहन या 2,500 रुपए प्रति किलोवाट-घंटा की सब्सिडी मिलती है। इसके लिए वाहनों की संख्या 24 लाख तय की गई है। योजना में थ्री-व्हीलर्स, ई-बस, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए भी इंसेंटिव तय था, जिसमें से थ्री-व्हीलर्स का बजट खत्म हो चुका है। यह योजना 31 मार्च 2028 तक चलनी है। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल ऑटो इंडस्ट्री के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा, 'अधिकारियों ने यह तो नहीं बताया कि कितना बजट और मिलेगा, लेकिन चर्चा के दौरान स्कीम को आगे बढ़ाने के संकेत जरूर दिए। अगर ऐसा होता है, तो इंडस्ट्री के लिए यह बड़ी राहत होगी, खासकर तब जब कमोडिटी की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।'

ई-दोपहियाः 60 दिन तक का पहुंचा वेटिंग पीरियड

जून में ईवी की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 63% बढ़कर 3 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पहली बार कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 12% रही। ईवी टू-व्हीलर की बिक्री 74.98% बढ़कर 1.93 लाख यूनिट रही। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दोगुनी से अधिक उछलकर 31,823 यूनिट रही। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, ई-दो पहिया में हर महीने 2.5 लाख यूनिट्स की मांग है, जबकि रजिस्ट्रेशन 1.9 लाख यूनिट्स का हो पा रहा है। इस वजह से एथर एनर्जी पर 60 दिन, टीवीएस मोटर पर 45 दिन का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

आरबीआई ने चेताया...

सामान्य बीमा की कंप्लेन तीन गुना, ये चिंताजनक

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ग्राहकों की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। इसने क्लेम मैनेजमेंट, सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट कम्युनिकेशन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 के बीच सामान्य बीमा को लेकर शिकायतें तीन गुना बढ़कर 1.78 लाख तक पहुंच गईं। यह क्लेम सेटलमेंट और ग्राहक सेवा में लगातार कमियों का ठोस संकेत है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शिकायतों में लगातार और तेज बढ़ोतरी दिखाती है कि क्लेम मैनेजमेंट, सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट की जानकारी देने के मामले में गंभीर खामियां रही हैं। अगर इन्हें समय रहते नहीं सुधारा गया, तो पॉलिसी धारकों का भरोसा कमजोर हो सकता है और पॉलिसी रिन्युअल रेट घट सकती है। अगर बड़े पैमाने पर लोग पॉलिसी छोड़ने लगे तो यह वित्तीय स्थिरता के लिए भी खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में हालात सुधरे हैं। यहां शिकायतें 2021-22 के 1.5 लाख से घटकर 2025-26 में 1.2 लाख रह गईं। यह बेहतर मार्केट कंडक्ट, ग्राहकों के लिए सही प्रोडक्ट चुनने और मजबूत पोस्ट-सेल सर्विस दर्शाता है।

बढ़ती शक्ति...

देश की आबादी में 31% मध्यम वर्गः सीतारमण

एजेंसी | एक्स-एन-प्रोवांस (फ्रांस)

भारत का मध्यम वर्ग 1995 से 2021 के बीच सालाना 6.3% की दर से बढ़ा है। फ्रांस में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब देश की 31% आबादी मध्यम वर्ग में आती है। ओईसीडी के अनुमान के अनुसार, 2030-35 के बीच मध्यम वर्ग की आबादी के मामले में भारत चीन से आगे निकल जाएगा।

2036 तक 93% उपभोक्ता खर्च में मध्यम और समृद्ध वर्ग की हिस्सेदारी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि देश की समृद्धि अब महानगरों तक सीमित नहीं है। टियर-2, टियर-3 के करीब 500 शहर नए आर्थिक केंद्र बन रहे हैं। जनधन योजना, डिजिटल भुगतान, कम ब्याज वाले सरकारी गारंटी ऋण व जीएसटी दरों में कटौती जैसे कदमों से मध्यम वर्ग मजबूत हुआ है।

बिजनेस एंकर दावा- माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए दुनिया को स्क्रीन से चिपकाया

परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ श्रीनिवास का दावाः 'बिल गेट्स ने दुनिया को 9-5 की जॉब में फंसाया, ताकि सॉफ्टवेयर बेचकर अमीर बन सकें'

बिजनेस संवाददाता | सैन फ्रांसिस्को

क्या आप भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कंप्यूटर के सामने बैठकर डेस्क जॉब करते हैं? अगर हां, तो परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास का दावा आपको चौंका सकता है। श्रीनिवास का कहना है कि यह 9 से 5 की डेस्क जॉब इंसानी काम का कोई स्वाभाविक विकास नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स द्वारा तैयार की गई एक बेहद सफल बिजनेस स्ट्रैटजी थी। हाल ही में मशहूर पॉडकास्ट 'द जो रोगन एक्सपीरियंस' में बातचीत के दौरान श्रीनिवास ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए जानबूझकर 'आधुनिक ऑफिस वर्कर' का कॉन्सेप्ट तैयार किया था। श्रीनिवास ने कहा, 'माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस वर्कर की इस पूरी अवधारणा को सिर्फ इसलिए खड़ा किया क्योंकि वे अपना ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचना चाहते थे। बिल गेट्स का मिशन ही यही था कि हर डेस्क पर एक पीसी (कंप्यूटर) हो और लोग उससे चिपके रहें।' उन्होंने आगे बताया कि दिनभर डेस्क पर बैठकर स्क्रीन को घूरते रहने वाले इस वर्क कल्चर को सुनियोजित तरीके से नीचे से ऊपर तक तैयार किया गया था।

सीईओ श्रीनिवास का यह दावा सुनकर पॉडकास्ट के होस्ट जो रोगन भी हैरान रह गए। रोगन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'वाह! इस तरह की लाइफस्टाइल बहुत ही हालिया चीज है जिसे हम सबने अब सामान्य मान लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मामले में सटीक निशाना लगाया।' परप्लेक्सिटी प्रमुख श्रीनिवास ने समझाया कि इस रणनीति के तहत कॉरपोरेट जगत में आने से पहले ही पीढ़ियों को माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों का आदी बनाया गया। उन्होंने कहा, 'यही वजह है कि हम सभी को बचपन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का इस्तेमाल करना सिखाया गया। एक बार जब आप यह सीख गए, तो आप किसी ऐसी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो गए जिसके डेस्क पर पीसी हो और जो माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के पैसे दे रही हो।' स्कूलों और शुरुआती कॉरपोरेट कल्चर में वर्ड और एक्सेल को अनिवार्य बनाकर माइक्रोसॉफ्ट ने मुनाफे का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र तैयार कर लिया।

गेट्स का मकसद जॉब्स की तरह कंप्यूटिंग को सुंदर बनाना नहीं थाः सीईओ

अरविंद श्रीनिवास ने बिल गेट्स के आक्रामक कॉरपोरेट विजन की तुलना एपल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स से की। उन्होंने कहा कि जहां स्टीव जॉब्स का ध्यान सुंदर, आकर्षक और आसान मशीनें बनाने पर था, वहीं माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना था। श्रीनिवास ने कहा, 'जैसा स्टीव जॉब्स सोचते थे। उन्हें सिर्फ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बेचने की परवाह थी, क्योंकि ज्यादा सॉफ्टवेयर बेचने से ही आप अमीर बनते हैं।'

नकली लग्जरी सामानों के हब में बड़ा एक्शन

एजेंसी | हो ची मिन्ह सिटी

अमेरिका की ओर से लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद वियतनाम सरकार ने नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। हाल में हो ची मिन्ह सिटी के पास दो गोदामों से नाइकी, एडिडास, क्रॉक्स और गुची के लोगो वाली 23 हजार से ज्यादा नकली चप्पलें जब्त की गईं। इनकी कीमत ₹72.2 लाख थी। मई के अंतिम तीन सप्ताह में 1,400 से ज्यादा बौद्धिक संपदा (आईपी) उल्लंघन के मामले पकड़े गए। जून में पुलिस ने 10 हजार से ज्यादा नकली गहने बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच वियतनाम ने कार्रवाई और तेज की है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कम आय और सस्ते सामान की मांग के कारण नकली सामान का कारोबार पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होगा।

रैली... एआई चिप की तगड़ी मांग बड़ी वजह

सैमसंग ने मुनाफा 1,800% बढ़ने का अनुमान जताया

एजेंसी | सोल

कोरियाई कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अप्रैल-जून तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,800% (19 गुना) बढ़ने का अनुमान जताया है। कंपनी का मानना है कि बीती तिमाही में मुनाफा करीब 5.57 लाख करोड़ रुपए रहेगा। यह लगातार तीसरी रिकॉर्ड तिमाही होगी। इस दौरान बिक्री करीब 171 लाख करोड़ वॉन (करीब 10.71 लाख करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले दोगुने से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मंदी के बावजूद केवल सेमीकंडक्टर बिजनेस के दम पर कंपनी ने यह शानदार रिकवरी की है। एआई मेमोरी चिप की वैश्विक मांग और सीमित आपूर्ति से चिप की कीमतें बढ़ी हैं। इससे कंपनी के नतीजों को बड़ा सहारा मिला है। सैमसंग ने भी अपनी मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनी इस महीने बाद में विस्तृत तिमाही नतीजे जारी करेगी। आईडीसी के अनुसार, एआई डेटा सेंटरों की मजबूत मांग के कारण अगले साल तक चिप की सप्लाई तंग रहने का अनुमान है। हालांकि रिकॉर्ड मुनाफे के अनुमान के बावजूद मंगलवार को सोल में सैमसंग के शेयर करीब 7% गिर गए। वजह निवेशकों को इससे भी बेहतर नतीजों की उम्मीद थी।